

अर्थव्यवस्था की स्थिति*

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) और उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में वैश्विक आर्थिक गतिविधि मजबूत होती दिख रही है और वस्तुओं और सेवाओं में वैश्विक व्यापार गति पकड़ रहा है। मौद्रिक नीति में वैविध्य वैश्विक आर्थिक विकास के लिए दिशा तय कर रहा है। भारत में, 2024-25 की दूसरी तिमाही अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेतों के साथ शुरू हुई है। कृषि के प्रति दृष्टिकोण में सुधार और ग्रामीण खर्च में सुधार, मांग स्थितियों के उद्भव में उज्ज्वल बिंदु साबित हुए हैं। जून 2024 में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में लगातार तीन महीनों की नरमी के बाद बढ़ोतरी हुई, क्योंकि सब्जियों की कीमतों में व्यापक उछाल ने चल रही समग्र अवरस्फीति को रोक दिया।

परिचय

'अर्थव्यवस्था की स्थिति' के जून 2024 संस्करण के बाद से, वैश्विक आर्थिक गतिविधि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) और उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में मजबूत होती दिख रही है। विश्व बैंक के अनुसार, आर्थिक विचलन सूचकांक (ईएसआई) बताते हैं कि गतिविधि, ईई के लिए वृद्धिशील और ईएमई में अधिक मार्जिन के कारण, प्रत्याशा से अधिक है। भावना संकेतक यह भी संकेत देते हैं कि आर्थिक स्थितियाँ और अपेक्षाएँ स्थिर बनी हुई हैं। क्रय प्रबंधकों के सूचकांकों के संदर्भ में, ईएमई ने लगातार दूसरे वर्ष ईई से बेहतर प्रदर्शन करना जारी रखा, जिसमें मजबूत संवृद्धि अपेक्षाओं के कारण भारत बाकी देशों से आगे रहा। श्रम बाजार ऐतिहासिक रूप से तंग स्थितियों से मुक्त हो रहे हैं और वेतन वृद्धि धीमी हो रही है। दूसरी ओर, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस) ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता हुआ ऋण स्तर निवेशकों में अत्यधिक विकर्षण और वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रति जोखिम पैदा करता है। अपने हालिया बजट पूर्वानुमान

* यह आलेख डॉ. माइकल देवव्रत पात्र, जी. वी. नथनएल, शाहबाज खान, अर्पिता अग्रवाल, कुणाल प्रियदर्शी, हर्षिता केशन, यामिनी जांब, हरेंद्र बेहरा, के. एम. नीलिमा, अरिजीत शिवहरे, मधुरेश कुमार, ऋषभ कुमार, सत्येन्द्र कुमार, खुशी सिन्हा, आयुषी खंडेलवाल, देबप्रिया साहा, शिवम, शैलजा भाटिया, युवराज कश्यप, अरात्रिका कुंडू, शाओनी नंदी, कमल गुप्ता, अवनीश कुमार, सुप्रियो मंडल, अमित पवार, हिमानी शेखर, आशीष थॉमस जॉर्ज, समीर रंजन बेहरा, विनीत कुमार श्रीवास्तव और रेखा मिश्र द्वारा तैयार किया गया है।

में, यूएस कांग्रेसनल बजट ऑफिस (सीबीओ) को उम्मीद है कि 2024 में अमेरिकी राजकोषीय घाटा जीडीपी के 7 प्रतिशत तक पहुँच जाएगा, जो कुछ मंदियों की अवधि के स्तर से अधिक है। सीबीओ का कहना है कि घाटा कई वर्षों तक ऊंचा बना रहेगा और 2034 में जनता द्वारा रखा गया अमेरिकी ऋण जीडीपी के 122 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संघीय ऋण के एक अज्ञात समुद्र में जा रही है। इस संदर्भ में, जहाँ बीआईएस ने केंद्रीय बैंकों को उपयुक्त समय से पहले नीतिगत दरों को कम न करने की सलाह दी है, वहीं स्थिति के गंभीर होने से पहले राजकोषीय रूप से कार्य करने के महत्व को रेखांकित किया है।

अमेरिका में सकारात्मक व्यापार गतिशीलता और एशिया में मजबूत निर्यात प्रदर्शन से प्रेरित होकर वैश्विक व्यापार वस्तुओं और सेवाओं में गति पकड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) के तात्कालिक अनुमान ने पहली तिमाही के सापेक्ष दूसरी तिमाही में अधिक सकारात्मक गति पकड़ी, जिससे 2024 की पहली छमाही में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया। यदि ये रुझान शेष वर्ष में भी बने रहते हैं, तो वैश्विक व्यापार 2024 में लगभग 32 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है, हालाँकि यह 2022 के रिकॉर्ड स्तर (32.2 अमेरिकी डॉलर) को पार करने की संभावना नहीं है। जहाँ वैश्विक माल व्यापार में गति फिर से आ रही है, वहीं सेवा व्यापार में जोरदार उछाल खत्म होता दिख रहा है। व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ रही हैं, मात्रा की तुलना में मूल्यों में अधिक वृद्धि हो रही है। इस उछाल के बावजूद, व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमत में वार्षिक परिवर्तन नकारात्मक रहने की उम्मीद है। लगातार भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ती शिपिंग लागत और सख्त औद्योगिक नीतियाँ - नकारात्मक जोखिम बनी हुई हैं।

विशेष रूप से, औद्योगिक नीतियाँ पारंपरिक और उच्च वृद्धि दोनों क्षेत्रों को लक्षित कर रही हैं, जिससे व्यापार पुनर्वितरण और आपूर्ति संकेन्द्रण में वृद्धि हो रही है। व्यापारिक प्रकाशनों में 'औद्योगिक नीति' के उल्लेख की बारंबारता बढ़ गई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, दुनिया भर में औद्योगिक नीति हस्तक्षेपों में भी भारी वृद्धि हुई है। ये नीतिगत

हस्तक्षेप, भू-राजनीतिक पुनर्व्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण की आवश्यकता और कंप्यूटिंग शक्ति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित हैं। आई और ईएमई में, रणनीतिक उद्योगों को बढ़ाने, घरेलू फर्मों को कम कार्बन उत्पादों के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के रूप में स्थान देने और आपूर्ति शृंखलाओं और महत्वपूर्ण उत्पादों के लचीलेपन को मजबूत करने के उद्देश्य से समर्थन उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। व्यापार के दृष्टिकोण से, ये नीतिगत हस्तक्षेप व्यापार पर प्रतिबंध लगाते हुए और ऊर्ध्वाधर समेकन की सुविधा देते हुए आयात प्रतिस्थापन की तलाश करते हैं। परिणामस्वरूप, व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव तब पड़ा है, जबकि कई लक्षित क्षेत्रों में वैश्विक मांग बढ़ रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहना। इस दृष्टिकोण के बुरे प्रभाव - आपूर्ति संकेन्द्रण में वृद्धि, प्रमुख खंडों में वैश्विक व्यापार विखंडन और संरक्षणवाद, व्यापार लागत और अनिश्चितता में वृद्धि - हैं।

ये घटनाक्रम विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) में गिरावट के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह के लिए एक निराशावादी माहौल की ओर ले जा रहे हैं, हालांकि विकासशील देशों में ग्रीनफील्ड निवेश की संभावना उज्ज्वल है, जैसा कि खंड IV में अधिक विस्तार से चर्चा की गई है। 2024 में एफडीआई के लिए वैश्विक वातावरण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, जिसमें बहुराष्ट्रीय उद्यम विदेशी विस्तार के लिए सतर्क दृष्टिकोण अपना रहे हैं। फिर भी, इन निगमों का लाभ स्तर उच्च बना हुआ है, जिसे पुनर्निवेशित आय द्वारा बढ़ावा मिला है। इसके अलावा, वित्तीय स्थितियाँ आसान हो रही हैं, विशेष रूप से आई में, जिससे परियोजना वित्त की संभावनाएँ उज्ज्वल हो रही हैं। हालांकि, 'अंकटाड' के अनुसार, ग्रीनफील्ड परियोजना घोषणाओं के शुरुआती संकेतक अभी भी कमजोर हैं।

मुद्रास्फीति लक्ष्य के करीब पहुंच रही है, लेकिन मुद्रास्फीति में कमी की गति कुछ धीमी हुई है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, 2 प्रतिशत के स्तर पर कुछ दूरी से ही सही, नज़र आ रहे हैं। अधिकांश उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में, मुद्रास्फीति लक्ष्य पर या उससे थोड़ा ऊपर स्थिर है। मौद्रिक नीतियां वैश्विक आर्थिक संवृद्धि के लिए दिशा तय कर रहा है। यूएस फेड से संबंधित विचारों का एकीकरण अब 'अगर' नहीं बल्कि 'कब' है। फेड फंड फ्यूचर्स

चालू कैलेंडर वर्ष में 60 आधार अंकों की दर कटौती की उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें पहली कार्रवाई एफओएमसी की सितंबर 2024 की बैठक के लिए पूरी तरह से मूल्यांकित है। यह मई 2024 में कोर व्यक्तिगत उपभोग व्यय मुद्रास्फीति के 2021 के बाद से सबसे कम वृद्धि पर पहुंचने और श्रम बाजार में सुस्ती के संकेतों के मद्देनजर हुआ है। आगे की पुष्टि में, जून 2024 के लिए उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति हेडलाइन और कोर दोनों के लिए अपेक्षाओं से कम रही, जैसा कि खंड II में विस्तार से बताया गया है। आखिरी मील स्पष्ट रूप से आखिरी चरण तक छोटा होता जा रहा है।¹ यू.एस. प्रतिफल और व्यापक डॉलर सूचकांक में तेज गिरावट आई, जिससे दुनिया के बाकी हिस्सों को काफी राहत मिली। पाठ्यपुस्तकों के पूर्वानुमान के अनुसार, ढीली राजकोषीय और सख्त मौद्रिक नीतियों के मिश्रण ने अब तक यू.एस. डॉलर को मजबूत बनाया है। मुद्रास्फीति में कमी के साथ-साथ नीतिगत दरों में कमी की जा रही है, इसलिए नीतिगत मिश्रण संभवतः डॉलर के लिए कम सकारात्मक होगा। यू.के. में, मुद्रास्फीति अंततः मई में 2 प्रतिशत के लक्ष्य पर पहुंच गई, लेकिन इसके परिणामस्वरूप दरों में कटौती नहीं हुई। बैंक ऑफ कनाडा, जिसने दरों में कटौती की शुरुआत की, अपनी जुलाई की बैठक में विराम ले सकता है। ईएमई में, पहले कदम उठाने वाले देश सहजता-गति को कम कर रहे हैं, जबकि इंडोनेशिया जैसे अन्य देश और दक्षिण कोरिया और सिंगापुर भी दरों को स्थिर रख रहे हैं, और कुछ ने अधिक आक्रामक रुख अपनाया है, जैसे कि रूस। वर्ष की शुरुआत के सापेक्ष, बाजार सहभागियों को अब देशों के बीच अधिक नीतिगत-दर वैविध्य की उम्मीद है।

वित्तीय स्थितियाँ मोटे तौर पर अपरिवर्तित बनी हुई हैं। उल्लेखनीय अस्थिरता के बीच ईएमई मुद्राएँ आम तौर पर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर रहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नीति दर अंतर में कमी, प्रतिफल संवाहक व्यापारों (कैरी ट्रेडों) के समापन के साथ मिलकर ईएमई में समूह के रूप में पोर्टफोलियो प्रवाह में कुछ मंदी आई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार, दुनिया के 30 प्रतिशत केंद्रीय बैंक 2023 में जोड़े गए 1037 टन के अलावा 2024 में अपने स्वर्ण भंडार में वृद्धि करेंगे, जो अमेरिकी डॉलर में विश्वास में कमी और रणनीतिक स्तर

¹ रॉयटर्स, 11 जुलाई 2024।

पर स्वर्ण होल्डिंग्स के अधिक पसंदीदा पुनर्संतुलन की कोशिश को दर्शाता है। ब्लॉकबस्टर पहली छमाही के बाद जब ईएमई सरकारों और कॉरपोरेट्स ने हार्ड करेंसी² में मूल्यवर्गित रिकॉर्ड 321 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बॉन्ड बेचे, परंतु 2024 की दूसरी छमाही में वित्तीय राजधानियों में बढ़ते राजनीतिक जोखिम के मद्देनजर जारीकर्ताओं में घबराहट के संकेत मिल रहे हैं। वर्ष के लिए फंडिंग जरूरतों के संदर्भ में, यह अनुमान लगाया गया है कि 80 प्रतिशत पहले ही कवर किया जा चुका है। ईएमई द्वारा जारी किए गए अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग के बॉन्ड ने धारकों को अब तक 2.2 प्रतिशत का लाभ दिया है, क्योंकि अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के कारण प्रतिफल में वृद्धि हुई है। यह प्रदर्शन मोटे तौर पर अमेरिकी उच्च-प्रतिफल वाले कॉरपोरेट बॉन्ड के अनुरूप है।

28 जून को जारी संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) रिपोर्ट 2024 ने बताया है कि 2030 तक एसडीजी हासिल करने के लिए सिर्फ छह वर्ष शेष हैं, प्रगति असमान, धीमी और ज्यादातर अबूझ बनी हुई है। केवल 17 प्रतिशत एसडीजी पटरी पर हैं, जबकि लगभग आधे न्यूनतम या मध्यम प्रगति दिखाते हैं और एक तिहाई से अधिक रुके हुए हैं या पीछे जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस के शब्दों में “शांति को सुरक्षित करने, जलवायु परिवर्तन का सामना करने और अंतरराष्ट्रीय वित्त को बढ़ावा देने में हमारी विफलता विकास को कमजोर कर रही है।”³ अगले छह वर्षों में लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निवेश को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से विकासशील देशों में जहां निवेश अंतर लगभग 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष होने का अनुमान है। 2024 का रिपोर्ट कार्ड कुछ आशाहीन नहीं है। उदाहरण के लिए, मोबाइल ब्रॉडबैंड दुनिया के 95 प्रतिशत लोगों तक पहुंच चुका है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि अक्षय ऊर्जा के उपयोग में प्रगति हुई है, जो वर्तमान में दुनिया की बिजली आपूर्ति का 30 प्रतिशत है।

21 जून, 2024 को, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति का अनुभव हुआ जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचा। यह एक मौन क्रांति की शुरुआत थी। यह कोई सांसारिक संसाधन

उपयोग नहीं करती, लगभग कुछ भी खर्च नहीं करती लेकिन वह प्रदान करती है जो दुनिया को चलाती है - बिजली। सौर क्रांति, सिलिकॉन से बने छोटे फोटोवोल्टिक सेल द्वारा संचालित होती है जिसमें 60-72 सेल एक विद्युत परिपथ के साथ होते हैं, जो दुनिया भर में 10,000 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र को कवर करते हैं, 2023 में दुनिया की लगभग 6 प्रतिशत बिजली का उत्पादन करते हैं। 2024 में, लगभग 70 बिलियन सेल का उत्पादन किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप 520-655 गीगावाट (जीडब्ल्यू) की स्थापित क्षमता होगी जो हर तीन वर्ष में दोगुनी हो रही है और हर दशक में दस गुना बढ़ रही है। सौर पैनल वर्तमान में बिजली उत्पादन में निवेश की सबसे बड़ी श्रेणी है, जिसका अनुमान अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) द्वारा 2024 में US \$ 500 बिलियन लगाया गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा सोसाइटी के अनुसार, सौर ऊर्जा 2026 में दुनिया के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, 2027 तक सभी पवन टर्बाइनों, 2028 तक सभी बांधों, 2030 तक सभी गैस-चालित बिजली संयंत्रों और 2032 तक सभी कोयला- चालित संयंत्रों से अधिक बिजली पैदा करेगी। न केवल बिजली, सौर ऊर्जा 2040 के दशक तक मानव जाति के प्राथमिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बनने के लिए तैयार है।⁴ आगे का रास्ता नवोन्मेषों से होकर गुजरेगा जिसमें लंबी दूरी के कनेक्शन, भंडारण (विशेष रूप से बैटरी) और सौर ऊर्जा की समग्र मांग को बढ़ाने के नए रास्ते शामिल होंगे। इसके अलावा, सौर ऊर्जा के विकास में चीन, अमेरिका और उत्तरी यूरोप का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब उत्पादन के लिए वैश्विक दक्षिण की ओर रुख करने का समय आ गया है, जहाँ बहुत सारी खाली जमीन है, धूप तक बेहतर पहुँच है और बहुत अधिक अपूरित मांग है। निकट भविष्य में, सौर ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसका उपयोग बैटरी की तुलना में अधिक समय तक ऊर्जा संगृहीत करने के तरीके के रूप में किया जा सकता है, लेकिन जिस बाधा को दूर करना होगा, वह है इलेक्ट्रोलिसिस की निषेधात्मक लागत, जिसके तहत हाइड्रोजन को पानी से अलग किया जाता है।

इस संदर्भ में भारत का महत्व बढ़ जाता है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े सौर डेवलपर्स का घर, जिसकी क्षमता पिछले 25 वर्षों में जर्मनी द्वारा स्थापित की गई क्षमता से दो-तिहाई से अधिक है,

² ब्लूमबर्ग, 1 जुलाई 2024।

³ 28 जून 2024 को न्यूयॉर्क में धारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) रिपोर्ट 2024 के शुभारंभ पर प्रेस को संयुक्त राष्ट्र महासचिव की टिप्पणी।

⁴ इकोनॉमिस्ट, 22 जून 2024।

भारत 84 गीगा वाट (जीडब्ल्यू) में वैश्विक सौर क्षमता का 5.2 प्रतिशत हिस्सा रखता है, जो पांचवां सबसे अधिक है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान कोयला बिजली में 1.6 प्रतिशत की तुलना में सौर स्थापित क्षमता 24.1 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ी है। सौर ऊर्जा उत्पादन कुल बिजली का क्रमशः 6.7 प्रतिशत और नवीकरणीय बिजली का 28.4 प्रतिशत है। सौर मॉड्यूल की लागत में गिरावट सौर क्षमता वृद्धि में निरंतर वृद्धि में योगदान दे रही है - 2.54 रुपये प्रति यूनिट का सौर शुल्क नए कोयला बिजली संयंत्रों (5-6 रुपये प्रति यूनिट) की तुलना में कम है। आगे बढ़ते हुए, ग्रिड स्थिरता और चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा भंडारण में निवेश की आवश्यकता है, जिससे सौर ऊर्जा की कुल लागत बढ़ जाती है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, भारत में बैटरी स्टोरेज के साथ संयुक्त सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल के लिए बिजली की स्तरीय लागत (एलसीओई) पहले से ही नए कोयला आधारित संयंत्रों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी हो गई है और इसमें और कमी आने की उम्मीद है। भारत का लक्ष्य राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, जिसमें लगभग 125 जीडब्ल्यू की संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि शामिल है। घरों में छत पर सौर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। निर्माण के विभिन्न चरणों में अतिरिक्त 85 जीडब्ल्यू क्षमता अगले कुछ वर्षों में भारत की सौर क्षमता को बढ़ाएगी। हाल के वर्षों में, विशेष रूप से अमेरिका को सौर सेल और मॉड्यूल का निर्यात बढ़ा है। वर्तमान में, भारत सौर सेल और मॉड्यूल का शुद्ध आयातक है क्योंकि इसे अभी भी सौर सेल के उत्पादन में पर्याप्त क्षमता हासिल करनी है। एक बार जब उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) और अन्य विनिर्माण परियोजनाओं से उत्पादन क्षमता चालू हो जाएगी, तो भारत सौर मॉड्यूल का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन जाएगा, जो पूरे मूल्य शृंखला में पर्याप्त विनिर्माण क्षमताओं का दावा करेगा।

2024-25 की दूसरी तिमाही भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेतों के साथ शुरू हुई है। जून में रुकी हुई और कम बारिश देने के बाद, दक्षिण-पश्चिम मानसून ने जुलाई में गति पकड़ी है,

पिछले 12 वर्षों में सातवीं बार पूरे देश को समय से पहले कवर किया है, जिसका विवरण भाग III में विस्तार से दिया गया है। जुलाई के पहले पखवाड़े में, अतिरिक्त वर्षा ने जून की कमी को मिटा दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) को उम्मीद है कि मानसून और भी जोरदार होगा और पूरे महीने में लंबी अवधि के औसत से अधिक होगा। 04 जुलाई, 2024 तक प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण 39 सप्ताह में पहली बार बढ़ा है। खरीफ की बुवाई ने गति पकड़ी है, जो एक वर्ष पहले के रकबे से अधिक है (विवरण के लिए भाग III देखें)। इस दर से, इस वर्ष सामान्य बोंग क्षेत्र को पार कर जाने की संभावना है। खेतों पर तीव्र गतिविधि ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम की मांग को कम कर दिया है। अल नीनो वर्तमान में तटस्थ है और समुद्र की सतह का तापमान ठंडा हो रहा है। ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो ने संकेत दिया है कि ला नीना, जिसके कारण भारत और पूरे एशिया में भारी वर्षा होती है, संभवतः अगस्त के बाद उभरेगी, जिससे मानसून के विस्तार और लंबे समय तक वर्षा होने का संकेत मिलता है।

कृषि के लिए परिदृश्य में सुधार 2024-25 में मांग की स्थितियों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बनने जा रहा है - ग्रामीण क्षेत्रों में व्यय में सुधार जो शहरी क्षेत्रों से आगे निकल रहा है। परिणामस्वरूप, ग्रामीण-शहरी विभाजन कम हो रहा है, जैसा कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के हालिया मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) सर्वेक्षण में बताया गया है। यह बढ़ते राजकोषीय हस्तांतरण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा दर्शाई गई मजदूरी दर में वृद्धि और शहरी प्रवास के कारण ग्रामीण परिवारों को भेजे जाने वाले धन की बढ़ती मात्रा के कारण है। ये कुछ ऐसे तात्कालिक कारक हैं जो ग्रामीण परिवारों की प्रभावी व्यय शक्ति को बढ़ा रहे हैं। सर्वेक्षण में सामने आए उपभोग पैटर्न से पता चलता है कि ग्रामीण भारत में 46.4 प्रतिशत व्यय भोजन पर होता है, जबकि शहरी परिवारों के लिए यह 39.2 प्रतिशत था। ग्रामीण खाद्य बास्केट में, अनाज की हिस्सेदारी कम हो गई है और पेय पदार्थ, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, दूध, मांस और अंडे की हिस्सेदारी बढ़ गई है। यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीण एम.पी.सी.ई. में परिवहन, चिकित्सा व्यय और

उपभोक्ता सेवाओं का हिस्सा अनाज से अधिक है। इन विकासों ने आशा जगाई है कि ग्रामीण भारत अपने शहरी समकक्ष के साथ आगे बढ़ रहा है और अभिसरण की परिकल्पना की जा सकती है। एक चिंताजनक विशेषता ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए वर्तमान और स्थिर कीमतों पर एम.पी.सी.ई. में वृद्धि के बीच का अंतर है, जो पिछले कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति के बोझ को दर्शाता है।

फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) सेगमेंट की कंपनियों को बेहतर नतीजे मिल रहे हैं और आय में सुधार से स्टॉक वैल्यूएशन में बढ़ोतरी हो रही है। यह मुद्रास्फीति में धीरे-धीरे कमी आने के साथ बिक्री की मात्रा में सुधार को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी में कमी आने के कारण उम्मीदें कम हैं, हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को कृषि आय में वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है। अधिकांश एफएमसीजी कंपनियों को लागत बचत पहलों और विज्ञापन और प्रचार खर्चों के समर्थन से उच्च एकल अंकों में राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है। पर्सनल केयर और होम केयर सेगमेंट में, उत्प्रेरक प्रीमियम पेशकश है जो परिचालन मार्जिन का विस्तार कर रही है। इस वर्ष भीषण गर्मी की स्थिति ने बोटलबंद शीतल पेय जैसे गर्मियों के लिए विशेष एफएमसीजी की बिक्री को भी एक नए उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है। फैब्रिक सॉफ़नर और वॉशिंग लिक्विड ने पैठ के उच्च स्तर हासिल कर लिए हैं। घरेलू खपत पर नज़र रखने वाली निजी शोध फ़र्म 2024-25 की दूसरी छमाही में व्यापक ग्रामीण नेतृत्व वाली रिकवरी की उम्मीद कर रही हैं।⁵

विनिर्माण क्षेत्र में तेजी आ रही है, नए ऑर्डर के कारण जून में क्रय प्रबंधकों का सूचकांक (पीएमआई) अपने दीर्घकालिक औसत से अधिक हो गया है। विनिर्माण विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए इसके हिस्से को सकल घरेलू उत्पाद के 20-25 प्रतिशत तक पहुंचने की आवश्यकता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और ऑटोमोबाइल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, जबकि भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बढ़त मिलेगी। विनिर्माण के लिए संघीय रूप से समावेशी नीतियां, बुनियादी ढांचे और रसद पर ध्यान केंद्रित करना, व्यापार करने

में आसानी और लागत, नवोन्मेष को बढ़ावा देने वाले अनुसंधान और विकास और एक आक्रामक निर्यात अभिविन्यास भारतीय विनिर्माण को उस आकांक्षात्मक लक्ष्य की ओर ले जाएगा। एक उद्योग में, भारत के विनिर्माण पावरहाउस में बदलने के प्रयास पहले से ही फल दे रहे हैं - इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण। 2015-16 और 2023-24 के बीच उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक्स का मूल्य \$37 बिलियन से बढ़कर \$115 बिलियन (जीडीपी का 3 प्रतिशत) हो गया। निकट-अवधि का उद्देश्य 2025-26 तक उत्पादन को तिगुना करना है। वर्तमान में, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन वैश्विक कुल का 3 प्रतिशत है, और यह हिस्सा किसी भी अन्य देश की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। 2023-24 में, भारत ने 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक सामान और 2024-25 के पहले दो महीनों में 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। फोन का उत्पादन भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का लगभग आधा हिस्सा बनाता है, जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनाता है। 2015-16 में, भारत ने अपने फोन का लगभग 4/5वां हिस्सा आयात किया था। अब यह बमुश्किल कोई आयात करता है। 2023-24 में, इसने 15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मोबाइल फोन और अप्रैल 2024 में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। Apple अपने सात में से लगभग एक iPhone भारत से खरीदता है, जो एक वर्ष पहले की तुलना में दोगुना है। सैमसंग - जो दक्षिण कोरियाई प्रतिद्वंद्वी है - के पास भारत में सबसे बड़ी फोन निर्माण सुविधा है।⁶

विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करना भारत के निर्यात में हिस्सेदारी को विश्व निर्यात के मौजूदा 2.4 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 5 प्रतिशत करने के लिए भी महत्वपूर्ण है, वस्तुओं और सेवाओं दोनों को मिलाकर।⁷ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, 2023-24 में करीब 780 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात और पहली तिमाही में 10.2 प्रतिशत की संचयी विस्तार दर के दम पर भारत 2024-25 में 800 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निर्यात हासिल करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है। इसके लिए श्रम-गहन निर्यात को फिर से शुरू करना होगा जो

⁶ द इकोनॉमिस्ट, 21 जून 2024।

⁷ भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर, डॉ. माइकल देवब्रत पात्र द्वारा, 9 जुलाई 2024 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बीच 'मिड-करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम' में प्रस्तुत संबोधन।

⁵ कांतार, एफएमसीजी पल्स, ति2 2024।

बीते वर्ष धीमा रहा था; एमएसएमई से निर्यात को बढ़ावा देना जो भारत के कुल निर्यात में लगभग 45 प्रतिशत, विनिर्माण उत्पादन में 38 प्रतिशत का योगदान देता है और 110 मिलियन लोगों को रोजगार देकर कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है; और सॉफ्टवेयर, आईटी और व्यापार से हटकर अन्य श्रेणियों में सेवा निर्यात में विविधता लाना, जो विश्व निर्यात का 64 प्रतिशत है लेकिन जिसमें भारत की वैश्विक बाजार में केवल 1.9 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ई-कॉमर्स निर्यात को प्राथमिकता देकर उन्हें वर्तमान स्तर 4-5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2030 तक लगभग 250-300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने से पारंपरिक निर्यात को रोकने वाली बाधाओं और भू-राजनीतिक चुनौतियों को दूर किया जा सकेगा। भारत के माल व्यापार के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में बंदरगाह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। महाराष्ट्र के तट पर वधावन बंदरगाह सभी मौसम गहरे पानी के मेगा बंदरगाहों की स्थापना की दिशा में एक कदम है। इसमें नौ कंटेनर टर्मिनल, एक तटीय बर्थ सहित चार बहुउद्देशीय बर्थ, चार लिक्विड कार्गो बर्थ, रोल ऑन रोल ऑफ जहाजों के लिए एक बर्थ और एक तट रक्षक बर्थ होगा। कंटेनर जहाज वर्तमान में दुनिया के समुद्री व्यापार का 16 प्रतिशत संभालते हैं। इसके लिए कंटेनर हैंडलिंग क्षमता को मौजूदा 20 मिलियन टीईयू से बढ़ाना ज़रूरी है।

भारत की विकास संभावनाओं के बारे में बढ़ती आशा, मजबूत लाभ वृद्धि और भागीदारी नोटों के जारी होने सहित विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों से खरीद समर्थन की वापसी ने जून और जुलाई में इक्विटी बाजारों को नए शिखर पर पहुंचा दिया। जुलाई में तेजी का नेतृत्व बैंकिंग और प्रौद्योगिकी शेयरों ने किया है। एमएससीआई सूचकांक के पुनर्संतुलन ने भारत की हिस्सेदारी 2020 में 8 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है, और सहकर्मी ईएमई के सापेक्ष मूल्यांकन अंतर बढ़ रहा है। छोटे और मध्यम-कैप शेयर आय से आगे चल रहे हैं और बड़े कैप साधियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रबंधन के तहत समग्र संस्थागत इक्विटी परिसंपत्तियों में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी जून 2024 के अंत में रिकॉर्ड पर पहुंच गई, यह दर्शाता है कि इक्विटी कीमतों में मौजूदा गति शायद बरकरार रह सकती है।

द्वितीयक बाजार के साथ-साथ प्राथमिक बाजार भी ऊर्जा से गुलजार है। 2024 की पहली छमाही 17 वर्षों में आईपीओ के लिए सबसे अच्छी पहली छमाही साबित हुई है, और सौदों का आकार बढ़ा होता जा रहा है (बॉक्स 1, खंड IV)। इससे पता चलता है कि कंपनियाँ अपनी बैलेंस शीट को मजबूत बनाने के लिए नई पूंजी जुटा रही हैं, ताकि नई क्षमता जोड़ने की तैयारी की जा सके। इसी तरह, स्टार्ट-अप फंडिंग का ज्वार बदल रहा है, इस वर्ष अब तक 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए गए हैं, जबकि स्टार्ट-अप आईपीओ की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। अक्षय ऊर्जा आईपीओ में तेजी आ रही है, क्योंकि निवेशक सौर ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। वेंचर कैपिटल सौदे रुकने के बाद बढ़ रहे हैं, आखिरकार वे बिना अनाबंटित पूंजी के रूप में आरक्षित नकद धन (ड्राई पाउडर) का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भारत के लिए 8-10 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अब तक, द्वितीयक हिस्सेदारी बिक्री और बायआउट ने इस क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाए रखा है, और देर से होने वाली गतिविधियाँ गति पकड़ रही हैं। रिकॉर्ड ऋण वितरण और ऋण आकार में वृद्धि के बावजूद फिनटेक फंडिंग में भारी गिरावट देखी गई है। बड़ी लागत वाले टेक-आउट सौदों में वृद्धि से आईटी सेवा कंपनियों के लिए माहौल बेहतर हो सकता है। बहुराष्ट्रीय निगम (एमएनसी) मूल्य अनलॉक करने और अपनी मूल कंपनी को पूंजी जुटाने में मदद करने के लिए आईपीओ के माध्यम से भारत में सूचीबद्ध होने के विकल्प तलाश रहे हैं। यह घरेलू समकक्षों के सापेक्ष एमएनसी शेयरों के अपेक्षाकृत आकर्षक मूल्यांकन के अनुरूप है। कुछ एमएनसी शेयर बाजार के प्रदर्शन का लाभ उठाकर हिस्सेदारी बेच रहे हैं।

विदेशी मुद्रा बाजार में, व्यापार घाटे में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती के बावजूद, मजबूत पूंजी प्रवाह के कारण जुलाई में रुपया मजबूत होने लगा है। मौद्रिक नीति के भावी पथ और अमेरिकी डॉलर (डीएक्सवाई) में उतार-चढ़ाव से संबंधित बाजार की अपेक्षाओं पर असर पड़ने के बावजूद, रुपया एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। तदनुसार, मुद्रा हेजिंग लागत पहले की तुलना में कम हो गई है। कथित तौर पर यूरो को लंबे समय तक रुपया कैरी ट्रेड के लिए मुद्रा के रूप में पसंद किया जा रहा है।

जेपी मॉर्गन इंडेक्स में भारतीय सॉवरेन बॉन्ड को शामिल किए जाने से पहले, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इन बॉन्ड में अपना स्वामित्व 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक बढ़ा दिया है। विदेशी बैंक सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभरे हैं, जिनका निवेश इंडेक्स-योग्य बॉन्ड में निवल प्रवाह के मूल्य से अधिक है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड ने भारत में अपने निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की है। समावेशन के बाद, प्रवाह धीमा रहा है और प्रतिफल लगभग स्थिर रहा है, जो आने वाले महीनों में अस्थिर उछाल के बजाय स्थिर प्रवाह का संकेत है।

ऋण बाजार में, कम लागत वाली चालू और बचत जमाराशियों की हिस्सेदारी 2021-22 में लगभग 44 प्रतिशत से लगातार गिरावट के साथ 39-40 प्रतिशत की सीमा में काफी हद तक नीचे आ गई है। इससे आगे चलकर बैंकों के शुद्ध मार्जिन में कमी आने और जमा बही के पुनर्मूल्यन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। वास्तव में, बैंकों को तिमाही समाप्ति से पहले जून में जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) के माध्यम से धन जुटाने के लिए प्रेरित किया गया है, जैसा कि खंड IV में दर्शाया गया है। सीडी में निवेश के लिए फंड जुटाने में म्यूचुअल फंड मुख्य भूमिका निभाते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अर्ध-वार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ने आकलन किया कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बेहतर बैलेंस शीट और निरंतर ऋण विस्तार के साथ वित्तीय प्रणाली मजबूत और लचीली बनी हुई है। मार्च 2024 के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का पूंजी से जोखिम-भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) और सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) अनुपात क्रमशः 16.8 प्रतिशत और 13.9 प्रतिशत रहा। एससीबी की सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात कई वर्षों के निचले स्तर 2.8 प्रतिशत और निवल अनर्जक आस्ति (एनएनपीए) अनुपात मार्च 2024 के अंत में 0.6 प्रतिशत पर आ गया। आस्ति पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) क्रमशः 1.3 प्रतिशत और 13.8 प्रतिशत के दशक के उच्चतम स्तर के करीब हैं। क्रेडिट जोखिम के लिए समष्टि दबाव परीक्षणों से पता चलता है कि एससीबी न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन करने में

सक्षम होंगे, मार्च 2025 में सिस्टम-स्तरीय सीआरएआर क्रमशः 16.1 प्रतिशत, 14.4 प्रतिशत और 13.0 प्रतिशत अनुमानित है, जो कि आधारभूत, मध्यम और गंभीर दबाव परिदृश्यों के तहत विनियामक न्यूनतम से काफी ऊपर है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) स्वस्थ बनी हुई हैं, जिनका सीआरएआर 26.6 प्रतिशत, जीएनपीए अनुपात 4.0 प्रतिशत और आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) क्रमशः मार्च 2024 के अंत में 3.3 प्रतिशत है। सिस्टम स्तर पर, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का सीआरएआर मार्च 2024 में 17.5 प्रतिशत तक बढ़ गया। म्यूचुअल फंड और क्लियरिंग कॉरपोरेशन पर दबाव परीक्षण वित्तीय क्षेत्र के इन खंडों की सुदृढ़ता को प्रमाणित करते हैं। नेटवर्क विश्लेषण से पता चलता है कि वित्तीय संस्थानों के बीच कुल बकाया द्विपक्षीय जोखिम बढ़ रहे हैं, जिसमें एससीबी का सबसे बड़ा हिस्सा है।

हर उम्मीद की किरण के पीछे एक बादल भी होता है। जून 2024 के आंकड़ों से पता चलता है कि उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति लगातार तीन महीनों की नरमी के बाद बढ़ गई है क्योंकि सब्जियों की कीमतों में व्यापक तेजी ने समग्र अवस्फीति को रोक दिया है जो चल रही थी। इस विकास ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के कुछ सदस्यों द्वारा जून की बैठक से संबंधित अपने मिनटों में व्यक्त की गई दूरदर्शी चेतावनियों को पुष्ट किया: “लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के साथ, ... जल्दबाजी में की गई कोई भी कार्रवाई ... अच्छे से अधिक नुकसान पहुंचाएगी⁸; यह सुनिश्चित करने के लिए एक सतर्क दृष्टिकोण उपयुक्त है कि उच्च खाद्य मुद्रास्फीति का उपभोग बास्केट में अन्य वस्तुओं की कीमतों पर कोई प्रभाव न पड़े⁹; खाद्य मूल्य झटकों की बार-बार घटना मुद्रास्फीति के लक्ष्य तक अंतिम रूप से उतरने में देरी कर रही है¹⁰; (खाद्य मूल्य झटकों की पुनरावृत्ति) मौद्रिक नीति सतर्कता को तीव्र करने की मांग करती है¹¹” मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, जैसा कि अंतिम भाग में विस्तार से बताया गया है।

⁸ श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर

⁹ डॉ. शशांक भिड़े

¹⁰ डॉ. राजीव रंजन

¹¹ डॉ. माइकल देवब्रत पात्र

इस पृष्ठभूमि में, इस आलेख का शेष भाग चार खंडों में संरचित है। खंड II में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से उभर रहे घटनाक्रमों को शामिल किया गया है। खंड III में घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों का आकलन किया गया है। खंड IV में भारत की वित्तीय स्थितियों का सार प्रस्तुत किया गया है, जबकि अंतिम खंड में समापन टिप्पणियाँ दी गई हैं।

II. वैश्विक परिदृश्य

श्रम बाजार की स्थितियों में सुधार और मुद्रास्फीति में नरमी के संकेतों के बीच 2024 की दूसरी तिमाही में वैश्विक आर्थिक गतिविधि मध्यम गति से बढ़ी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 16 जुलाई 2024 को जारी अपने नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) अपडेट में 2024 के लिए वैश्विक संवृद्धि पूर्वानुमान को 3.2 प्रतिशत (अप्रैल 2024 के अनुमान के समान) पर बनाए रखा और 2025 के लिए संवृद्धि पूर्वानुमान को 10 बीपीएस बढ़ाकर 3.3 प्रतिशत कर दिया (सारणी II.1)। हमारे मॉडल-आधारित नाउकास्ट, नवीनतम उच्च आवृत्ति संकेतकों के साथ संवर्धित, दूसरी तिमाही और 2024 की तीसरी तिमाही के दौरान गति बनाए रखने की ओर इशारा करते हैं (चार्ट II.1)।

सारणी II.1: सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि पूर्वानुमान – चुनिंदा आई और ईएमई

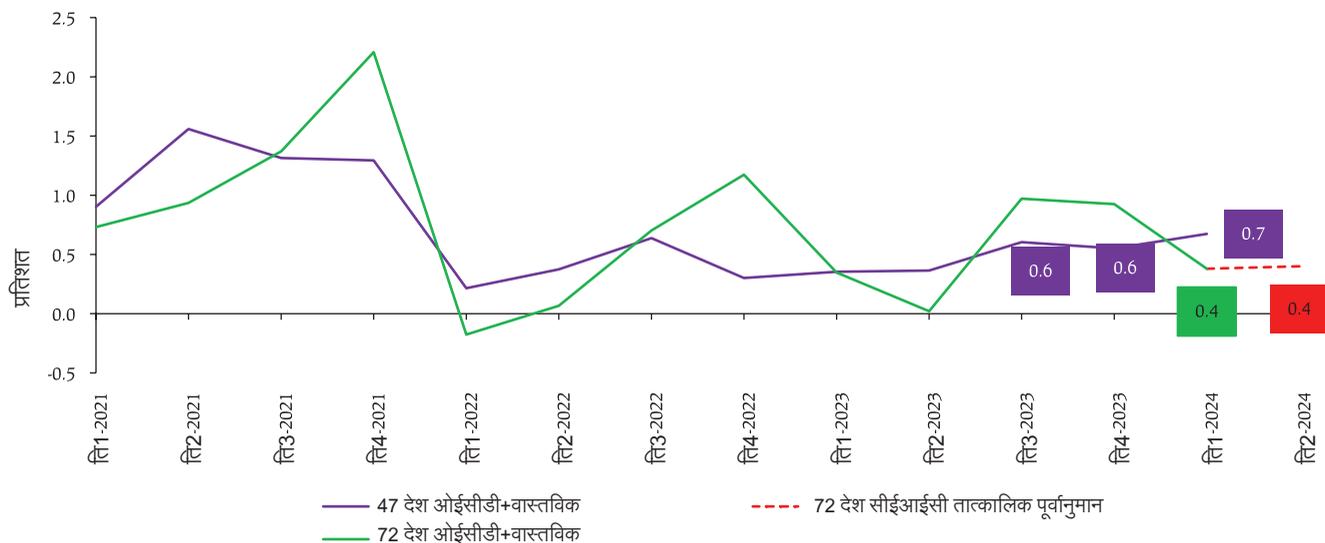
(प्रतिशत)

पूर्वानुमान माह क्षेत्र / देश	2024		2025	
	जुलाई 2024	अप्रैल 2024	जुलाई 2024	अप्रैल 2024
 विश्व	3.2	3.2	3.3	3.2
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं (आई)				
 यूएस	2.6	2.7	1.9	1.9
 यूके	0.7	0.5	1.5	1.5
 यूरो क्षेत्र	0.9	0.8	1.5	1.5
 जापान	0.7	0.9	1.0	1.0
उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई)				
 ब्राजील	2.1	2.2	2.4	2.1
 रूस	3.2	3.2	1.5	1.8
 भारत#	7.0	6.8	6.5	6.5
 चीन	5.0	4.6	4.5	4.1
 दक्षिण अफ्रीका	0.9	0.9	1.2	1.2

टिप्पणी: * #: भारत का डेटा वित्तीय वर्ष के आधार पर है।

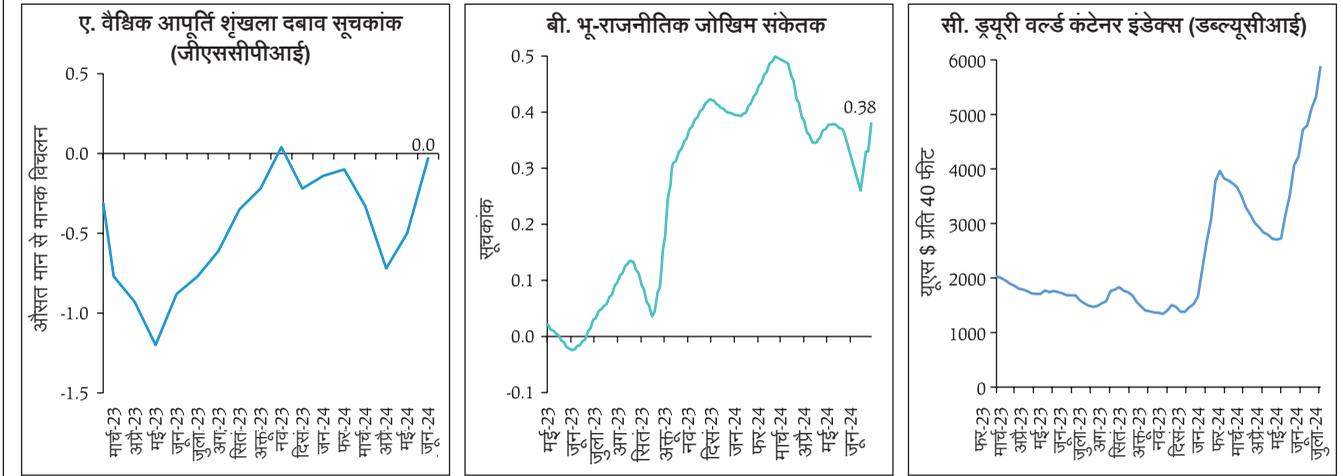
स्रोत: आईएमएफ।

चार्ट II.1: वैश्विक जीडीपी संवृद्धि तात्कालिक पूर्वानुमान (ति-द-ति)



स्रोत: सीईआईसी; ओईसीडी; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट II.2: आपूर्ति शृंखला दबाव और भू-राजनीतिक जोखिमों में प्रवृत्तियां



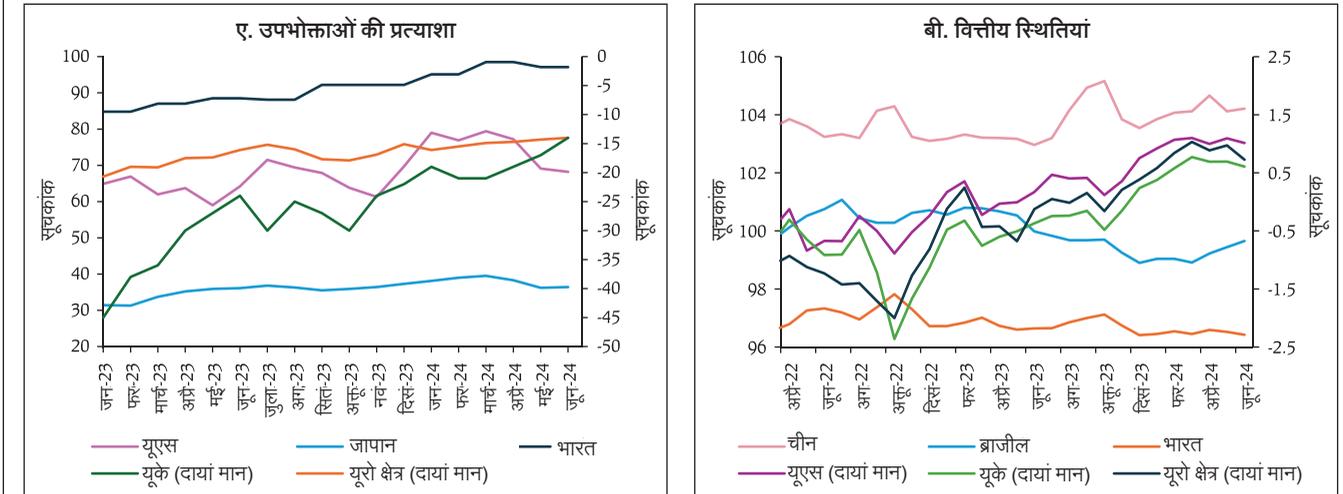
टिप्पणियाँ : 1. जीएससीपीआई परिवहन लागत और विनिर्माण संकेतकों से संबंधित डेटा दर्शाता है।
 2. डब्ल्यूसीआई प्रमुख पूर्व-पश्चिम व्यापार मार्गों के लिए वास्तविक स्पॉट कंटेनर माल ढुलाई दरों को इंगित करता है। समग्र डाटा मात्रा के हिसाब से 8 शिपिंग मार्गों के भारत औसत का प्रतिनिधित्व करता है और प्रति 40-फुट कंटेनर यूएसडी में सूचित करता है।
स्रोत : फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क; ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट इस्टीमेट, जून 2024; और ब्लूमबर्ग।

वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक (जीएससीपीआई) ने जून 2024 में वृद्धि दर्ज की, जो इसे अपने ऐतिहासिक औसत (चार्ट II.2ए) के करीब ले गया। भू-राजनीतिक जोखिम सूचकांक, जिसमें जून 2024 की पहली छमाही में मामूली गिरावट आई थी, उसके बाद मध्य पूर्व में शत्रुता के बढ़ने से प्रेरित होकर वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट II.2बी)। लाल सागर (चार्ट II.2सी) में

व्यवधानों के कारण यात्रा पारगमन समय बढ़ा रहने के कारण शिपिंग लागत में वृद्धि जारी रही।¹²

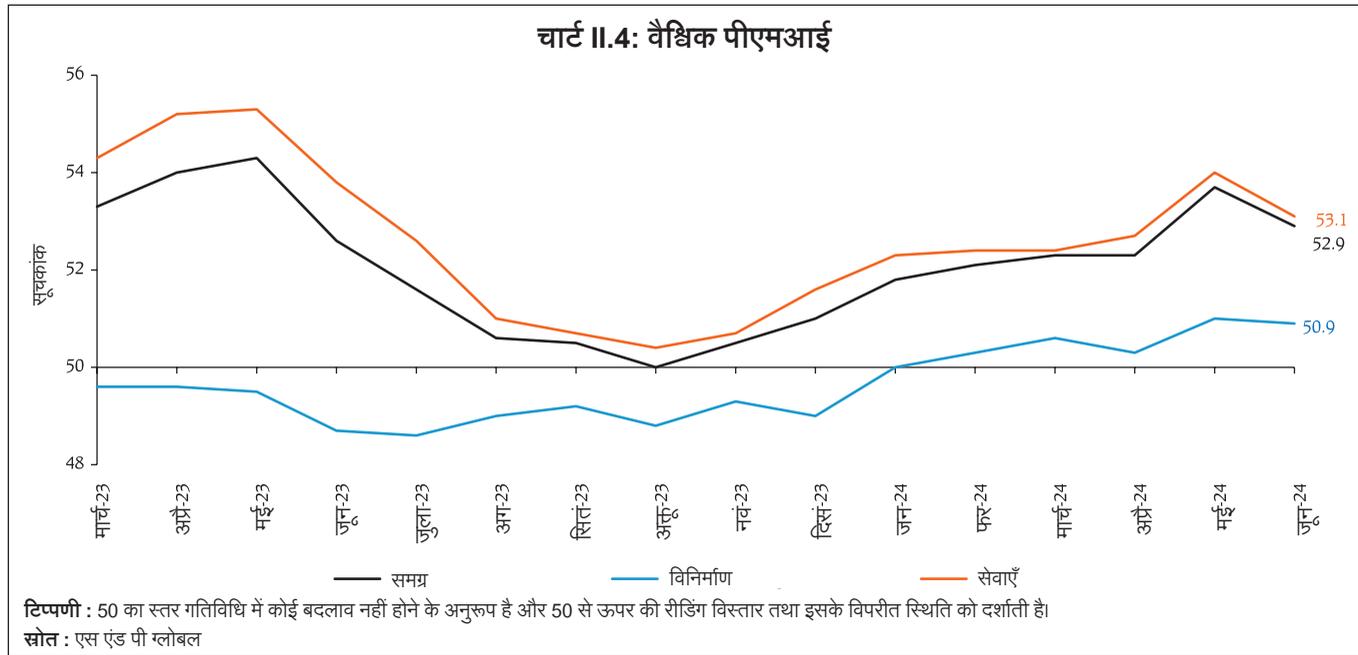
जून 2024 में अमेरिका में उपभोक्ता भावनाएँ लगातार तीसरे महीने गिरकर नवंबर 2023 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई (चार्ट II.3ए)। यूरो क्षेत्र में भी भावनाएँ इस उम्मीद पर सतर्क रहीं कि रोजगार में और गिरावट आने

चार्ट II.3: उपभोक्ता प्रत्याशा और वित्तीय स्थितियां



टिप्पणियाँ : 1. जापान: 50 से ऊपर का स्कोर उपभोक्ता आशावाद को दर्शाता है, 50 से नीचे उपभोक्ता विश्वास की कमी को दर्शाता है और 50 तटस्थता को दर्शाता है।
 2. यूरोजोन और यूके: (-)100 विश्वास की अत्यधिक कमी, 0 तटस्थता और 100 अत्यधिक विश्वास को दर्शाता है।
 3. भारत और अमेरिका: सूचकांक मूल्य जितना अधिक होगा, उपभोक्ता का विश्वास उतना अधिक होगा।
स्रोत : ब्लूमबर्ग।

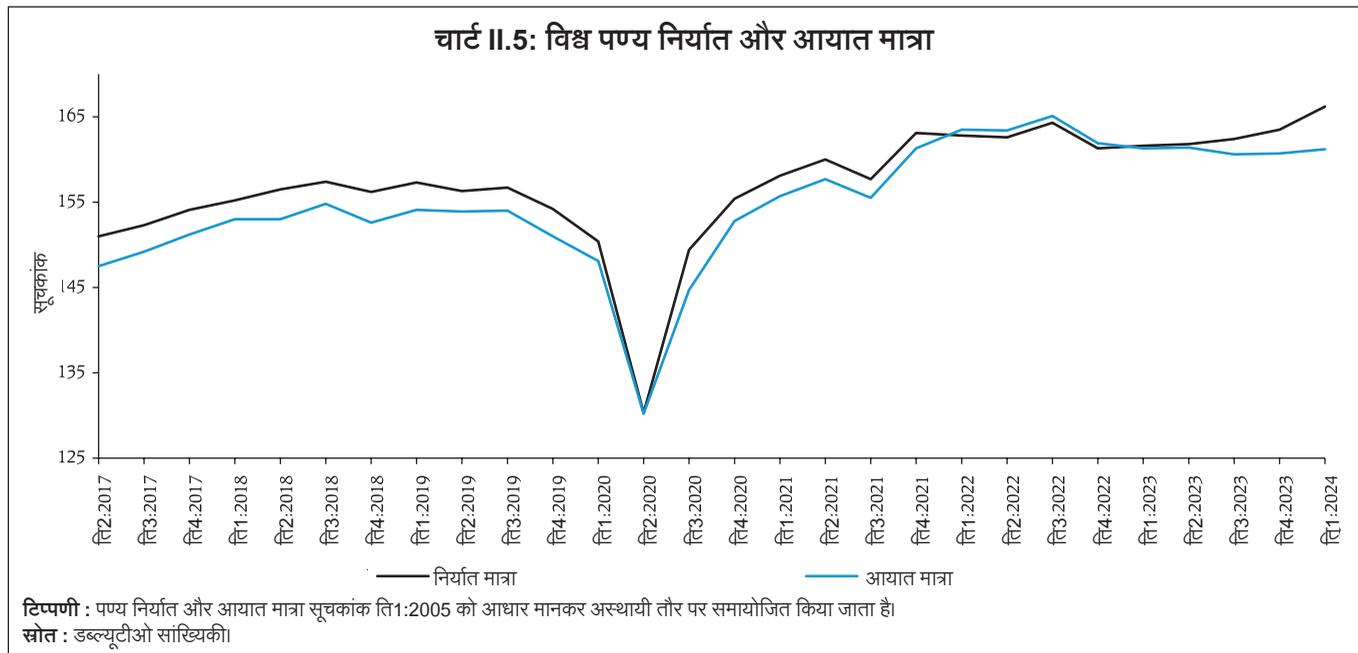
¹² कंटेनर उपकरण पूर्वानुमान रिपोर्ट | <https://www.drewry.co.uk/maritime-research-opinion-browser/maritime-research-opinions/global-container-equipment-fleet-growth-picks-up-pace>.

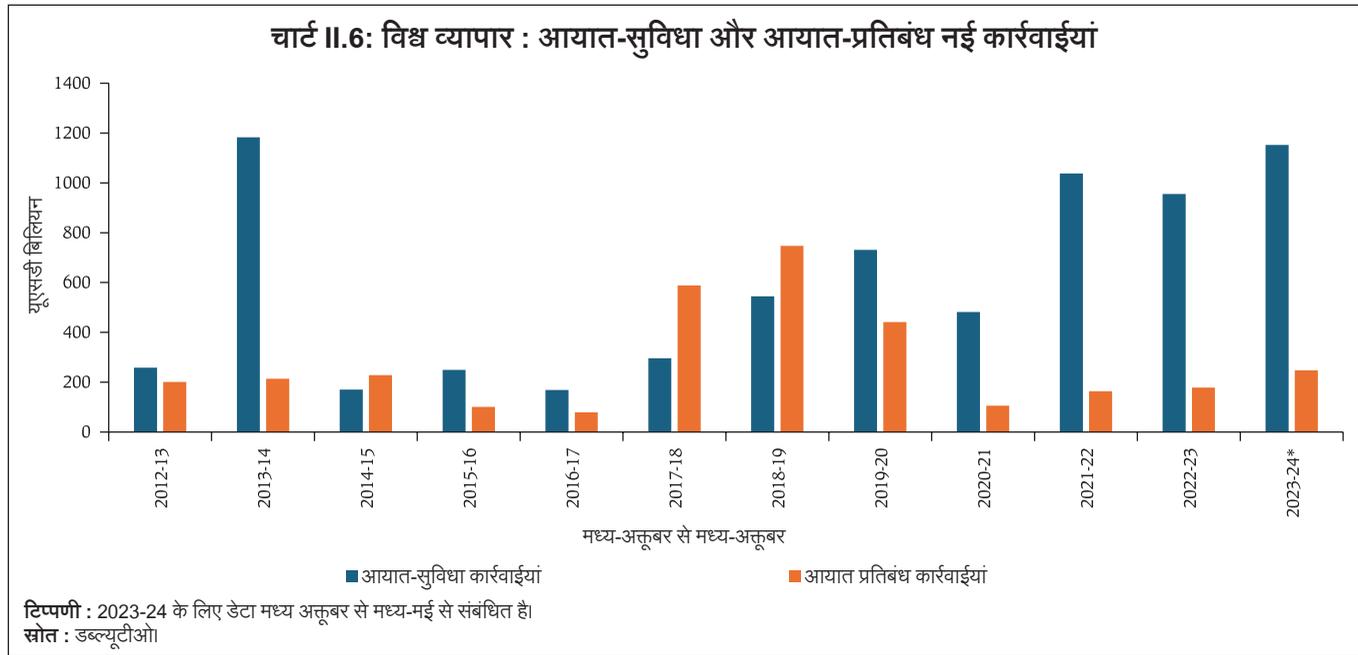


की संभावना है। एई में वित्तीय स्थितियाँ थोड़ी कम हुईं, जबकि ब्राज़ील और चीन जैसी उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में जोखिम की आशंका के कारण कुछ सख्ती हुई (चार्ट II.3बी)।

वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) ने लगातार आठवें महीने विस्तार दर्ज किया, हालांकि मई में 53.7 से जून में क्रमिक मॉडरेशन के साथ 52.9 रहा। विनिर्माण

उत्पादन और सेवा क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधि (चार्ट II.4) दोनों के लिए विस्तार की दरें महीने-दर-महीने कम हुई हैं। वैश्विक विनिर्माण पीएमआई मई के ढाई वर्ष के उच्च स्तर से जून में नरम होकर 50.9 पर आ गया, जबकि सेवा पीएमआई मई में 54.0 से जून में धीमी होकर 53.1 पर आ गया। क्रमिक मॉडरेशन के बावजूद, विकास व्यापक हो रहा है, पीएमआई



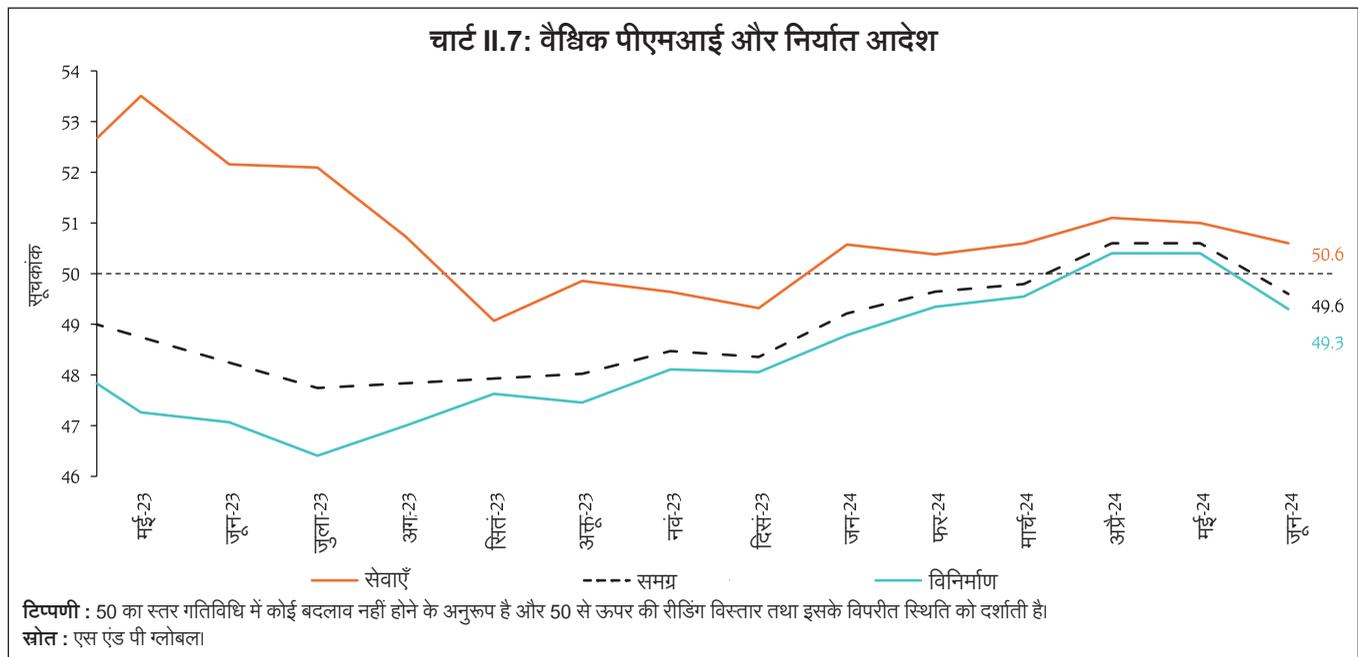


द्वारा कवर किए गए सभी 25 उप-क्षेत्रों में जुलाई 2021 के बाद पहली बार जून 2024 में विस्तार (जैसा कि 50 से ऊपर के सूचकांक मूल्य में स्पष्ट है) दर्ज किया गया है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नवीनतम व्यापार निगरानी अपडेट¹³ के अनुसार, 2023 में अपेक्षा से अधिक

गिरावट के बाद 2024-25 के दौरान विश्व व्यापार में धीरे-धीरे वृद्धि होने की उम्मीद है। ति1:2024 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विश्व माल निर्यात मात्रा में 2.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट II.5)।

यद्यपि विश्व माल आयात मात्रा में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मामूली संकुचन दर्ज किया गया, लेकिन यह क्रमिक रूप से बढ़ा।



¹³ ट्रेड मॉनिटरिंग अपडेट, विश्व व्यापार संगठन, 08 जुलाई 2024।

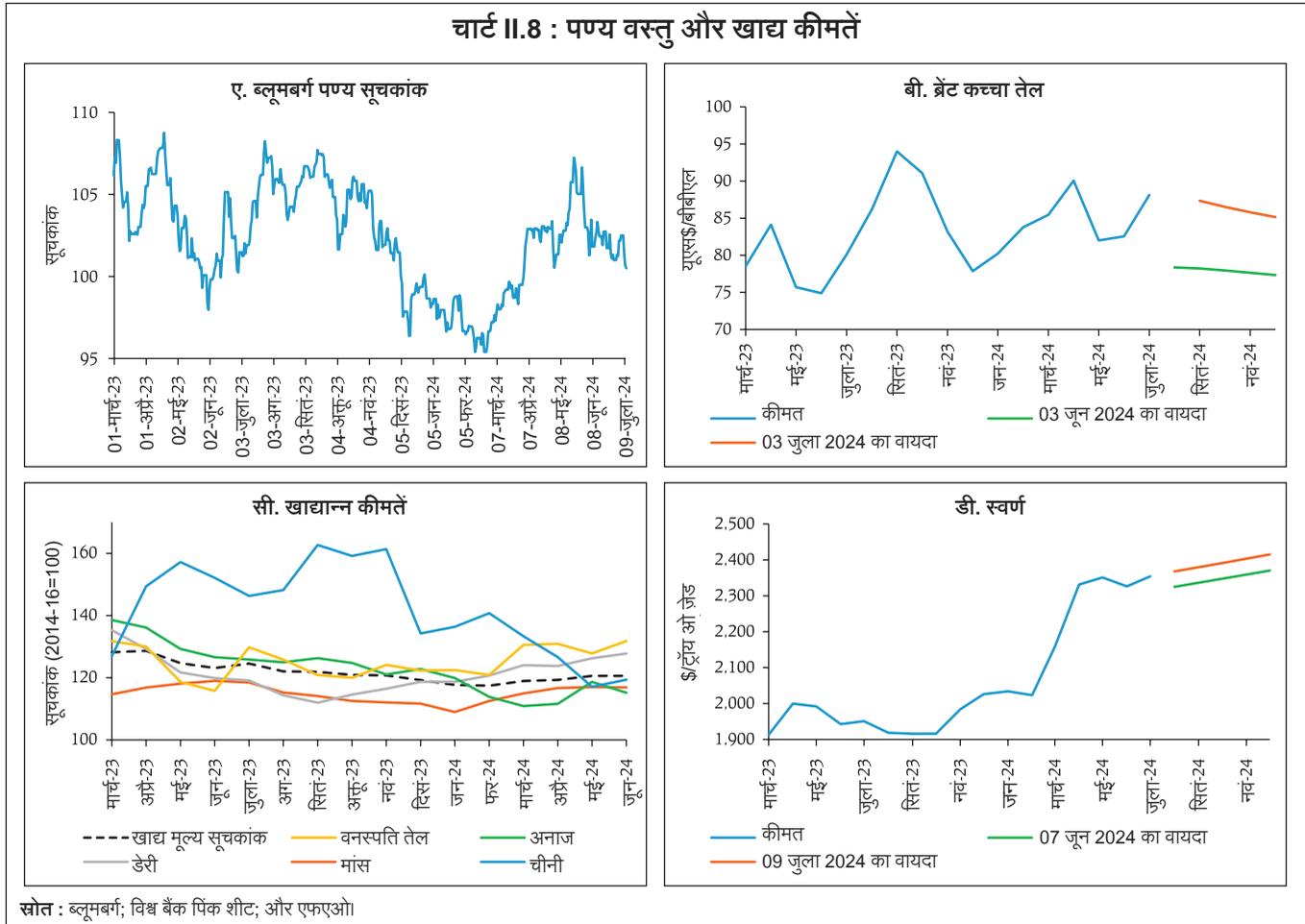
पिछले वर्ष आयात को सुविधाजनक बनाने वाले व्यापार उपायों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो आयात प्रतिबंधक उपायों में वृद्धि से अधिक है। 2024 के दौरान अब तक इस बदलाव के बने रहने से, यह वैश्विक व्यापार सुधार को और अधिक सहायता प्रदान कर सकता है (चार्ट 11.6)।

हालांकि, निर्यात ऑर्डर के लिए समग्र पीएमआई जून में कम हुआ, जबकि पिछले दो महीनों में यह विस्तार क्षेत्र में रहा। विनिर्माण और सेवा निर्यात ऑर्डर दोनों में नरमी देखी गई (चार्ट 11.7)।

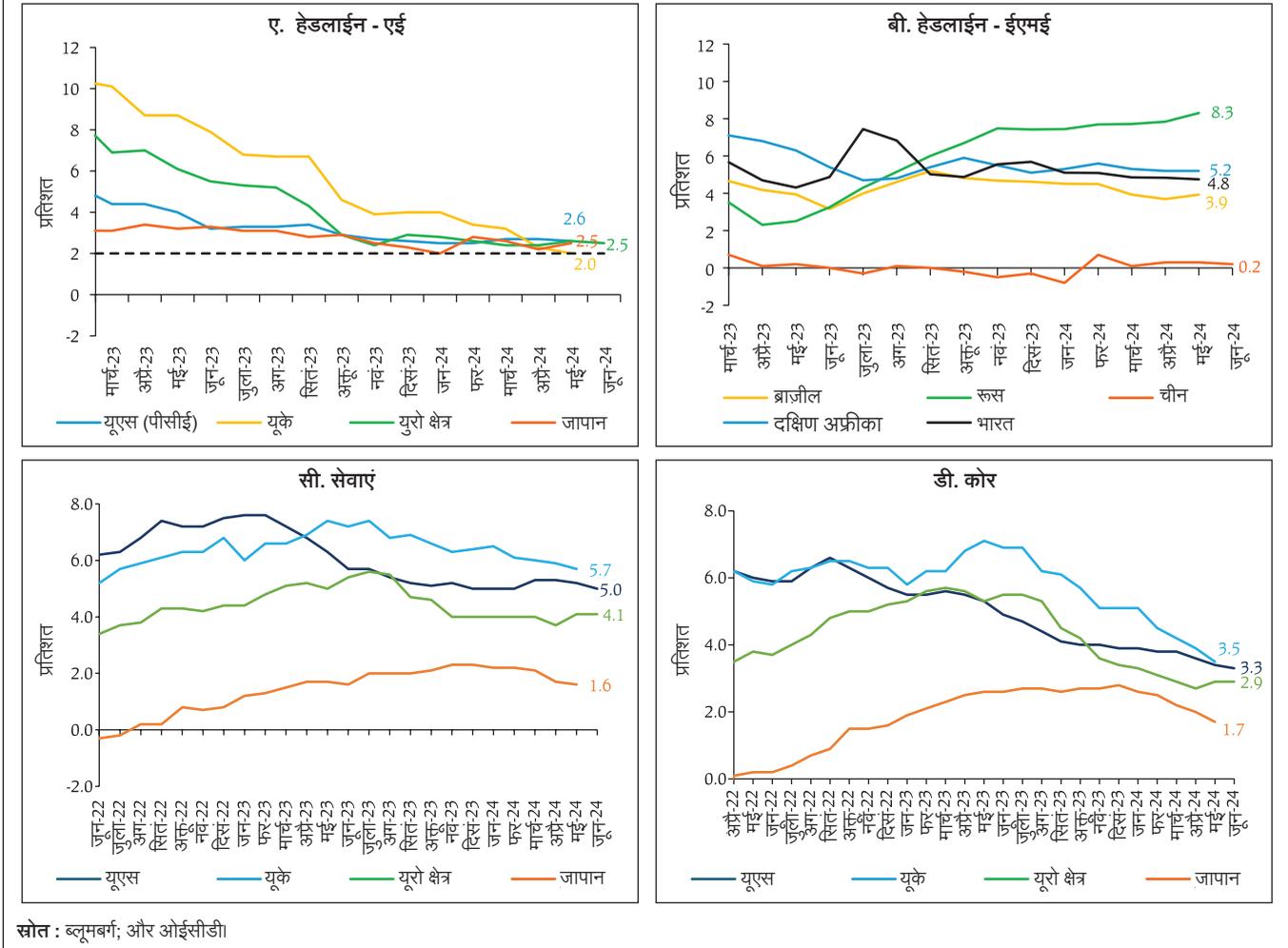
वैश्विक कमोडिटी की कीमतें अस्थिर बनी हुई हैं। कम कृषि कमोडिटी की कीमतें और औद्योगिक धातु की कीमतें आंशिक रूप से उच्च ऊर्जा कीमतों से ऑफसेट हुईं, जिसके परिणामस्वरूप ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स जून में 1.9 प्रतिशत

(माह-दर-माह) गिर गया (चार्ट 11.8ए)। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो जून के अंत में 85 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल को पार कर गई, इसका कारण भू-राजनीतिक जोखिम बढ़ना और साथ ही अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में उम्मीद से अधिक गिरावट थी (चार्ट 11.8बी)। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) का खाद्य मूल्य सूचकांक जून 2024 में स्थिर (माह-दर-माह) रहा क्योंकि वनस्पति तेलों (3.1 प्रतिशत) और चीनी (1.9 प्रतिशत) की कीमतों में वृद्धि अनाज की कीमत में कमी (-3.0 प्रतिशत) से ऑफसेट हुई। जून (माह-दर-माह) में स्वर्ण कीमतों में 1 प्रतिशत की गिरावट आई, जो मजबूत अमेरिकी डॉलर और कमजोर मौसमी मांग को दर्शाता है (चार्ट 11.8डी)।

चार्ट 11.8 : पण्य वस्तु और खाद्य कीमतें



चार्ट II.9 : मुद्रास्फीति - आई और ईएमई

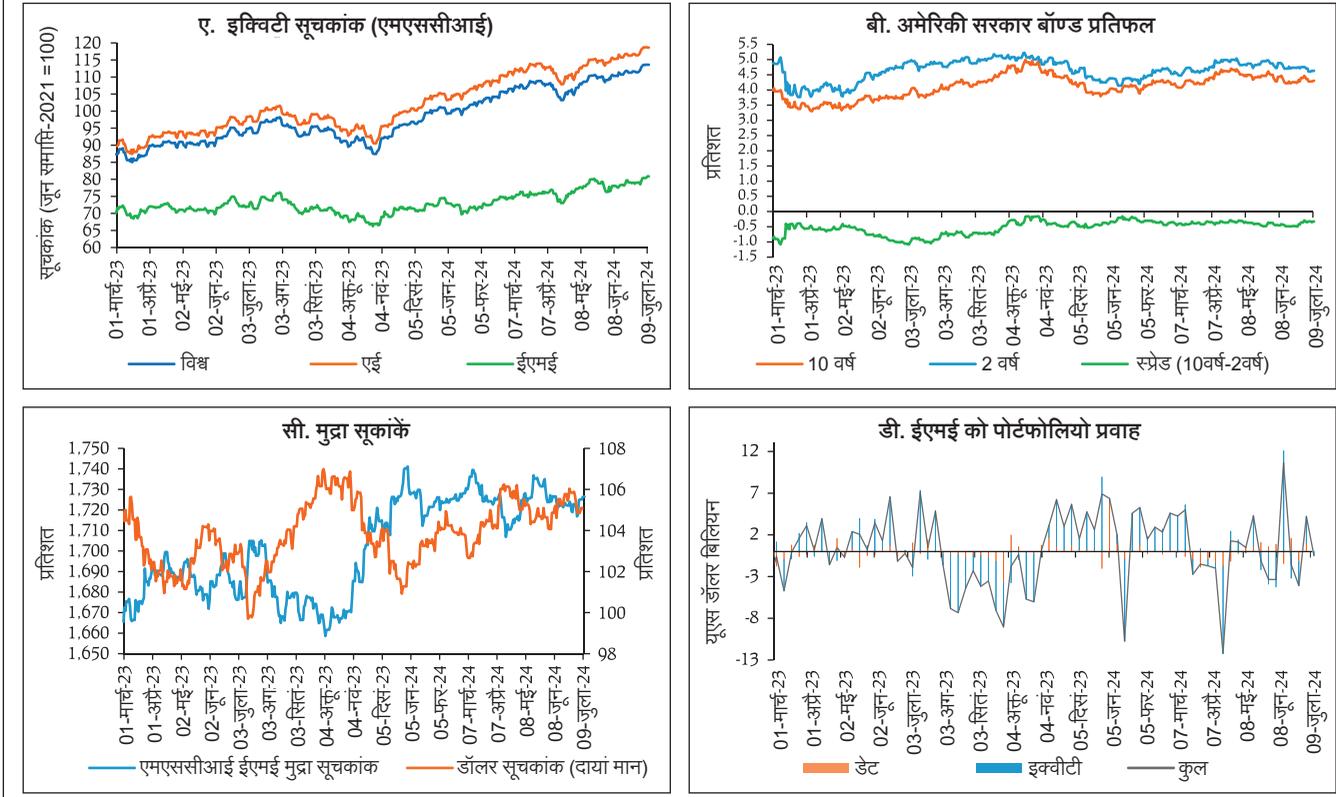


अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में हेडलाइन मुद्रास्फीति में धीरे-धीरे गिरावट जारी रही। अमेरिका में, सीपीआई मुद्रास्फीति मई में 3.3 प्रतिशत से जून में 3.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) तक कम हो गई, और सूचकांक ने गैस और ऑटोमोबाइल की कीमतों में गिरावट के कारण मई 2020 के बाद पहली बार माह-दर-माह गिरावट दर्ज की। हेडलाइन व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मुद्रास्फीति भी अप्रैल में 2.7 प्रतिशत से मई में 2.6 प्रतिशत तक कम हो गई। फ्लैश अनुमानों के अनुसार, यूरो क्षेत्र की मुद्रास्फीति जून में 2.5 प्रतिशत तक कम हो गई, जो एक महीने पहले 2.6 प्रतिशत थी, बावजूद इसके कि कोर और सेवाओं की मुद्रास्फीति जड़ बनी रही। जापान में मुद्रास्फीति (ताजा भोजन को छोड़कर सीपीआई) मई में

2.5 प्रतिशत तक बढ़ गई, जबकि यूके में यह 2.0 प्रतिशत तक कम हो गई (चार्ट II.9ए)। ईएमई में, ब्राजील और रूस में मुद्रास्फीति बढ़ी, जबकि जून में चीन में यह कम हुई (चार्ट II.9बी)। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कोर और सेवा मुद्रास्फीति में गिरावट का रुख रहा है, हालांकि अधिकांश में यह कोर मुद्रास्फीति से अधिक बनी हुई है।

जून में वैश्विक इक्विटी बाजारों में तेजी आई, मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) विश्व सूचकांक में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई क्योंकि अनुमान से पहले अमेरिकी फेड दर में कटौती की बढ़ती उम्मीदों ने शेयर बाजारों में जोखिम-जनित-भावना को बढ़ावा दिया (चार्ट II.10ए)।

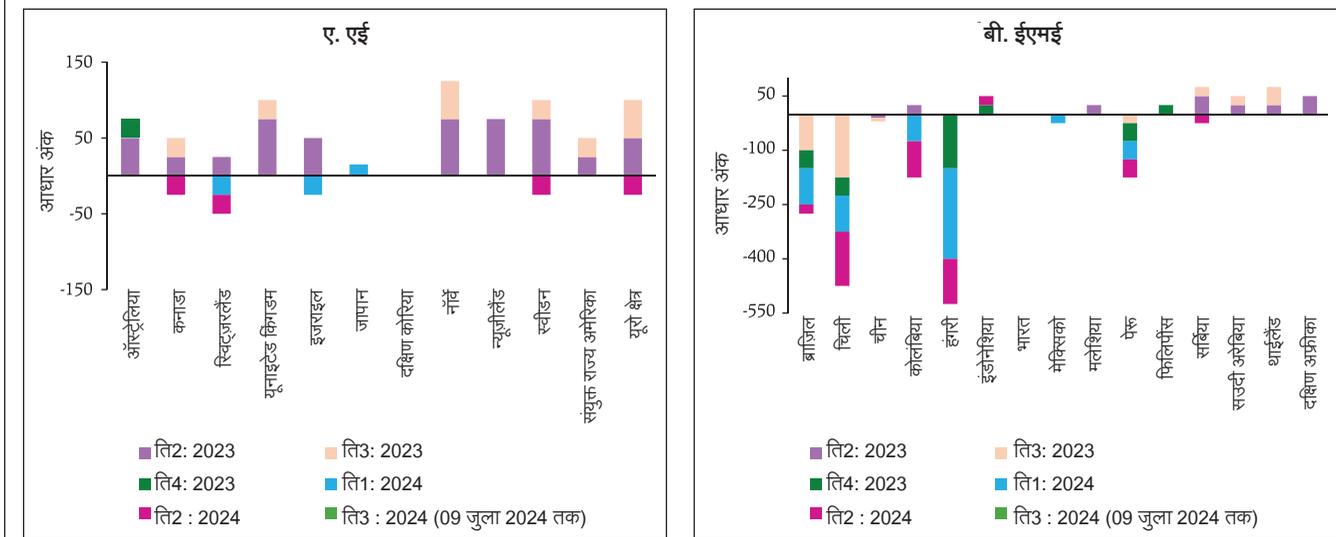
चार्ट II.10 वैश्विक वित्तीय बाजार



स्रोत : ब्लूमबर्ग; और आईआईएफा

अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) का प्रतिफल – 12 बीपीएस तक कम हो गया, क्योंकि वित्तीय बाजारों ने 10-वर्ष और 2-वर्ष दोनों – जून में क्रमशः 10 बीपीएस और उम्मीद से कमजोर श्रम बाजार और व्यावसायिक गतिविधि

चार्ट II.11: नीति दरों में परिवर्तन



स्रोत : ब्लूमबर्ग

डेटा को महत्व दिया (चार्ट II.10बी)¹⁴ मुद्रा बाजारों में, सुरक्षित पनाहगाह अपील की वजह से जून में अमेरिकी डॉलर में लगभग 1 प्रतिशत की मजबूती आई। दूसरी ओर, ईएमई के लिए एमएससीआई मुद्रा सूचकांक जून में अस्थिर पूंजी प्रवाह के साथ सीमाबद्ध रहा, मुख्य रूप से इक्विटी खंड में (चार्ट II.10सी और II.10डी)।

ईई केंद्रीय बैंकों में, स्विस नेशनल बैंक ने लगातार दूसरी बैठक में जून में अपनी बेंचमार्क दर को 25 बीपीएस घटाकर 1.25 प्रतिशत कर दिया (चार्ट II.11ए)। ईएमई केंद्रीय बैंकों में, कोलंबिया ने जून की बैठक में अपनी प्रमुख दर में 50 बीपीएस की कटौती करते हुए अपने सहजता चक्र को जारी रखा (चार्ट II.11बी)। अधिकांश अन्य केंद्रीय बैंकों ने अपनी नवीनतम बैठकों में अपनी नीतिगत दरों को बरकरार रखा है,

हालांकि उनमें से कुछ ने मुद्रास्फीति पर अनुकूल आंकड़ों की शर्त पर आगामी दर कटौती पर भावी संकेत दिए हैं।

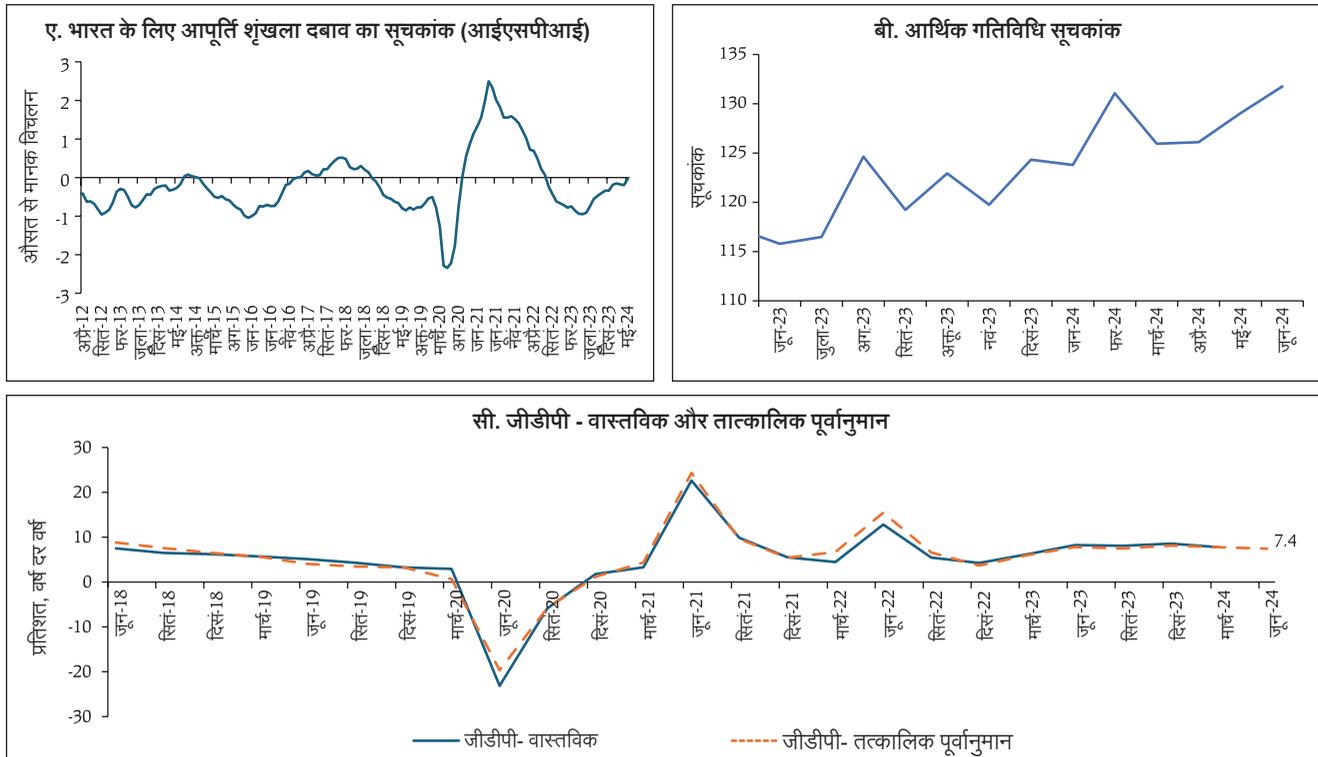
III. घरेलू घटनाक्रम

भू-राजनीतिक प्रतिकूलताओं और आपूर्ति शृंखला दबावों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत संवृद्धि गति बनाए रखी (चार्ट III.1ए)। कई उच्च आवृत्ति संकेतकों से उपलब्ध जानकारी का उपयोग करते हुए, हमारा आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) अनुमान लगाता है कि ति1:2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.4 प्रतिशत होने की संभावना है (चार्ट III.1बी और चार्ट III.1सी)।

समग्र मांग

उच्च आवृत्ति संकेतकों में उतार-चढ़ाव से पता चलता है कि 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान घरेलू मांग की

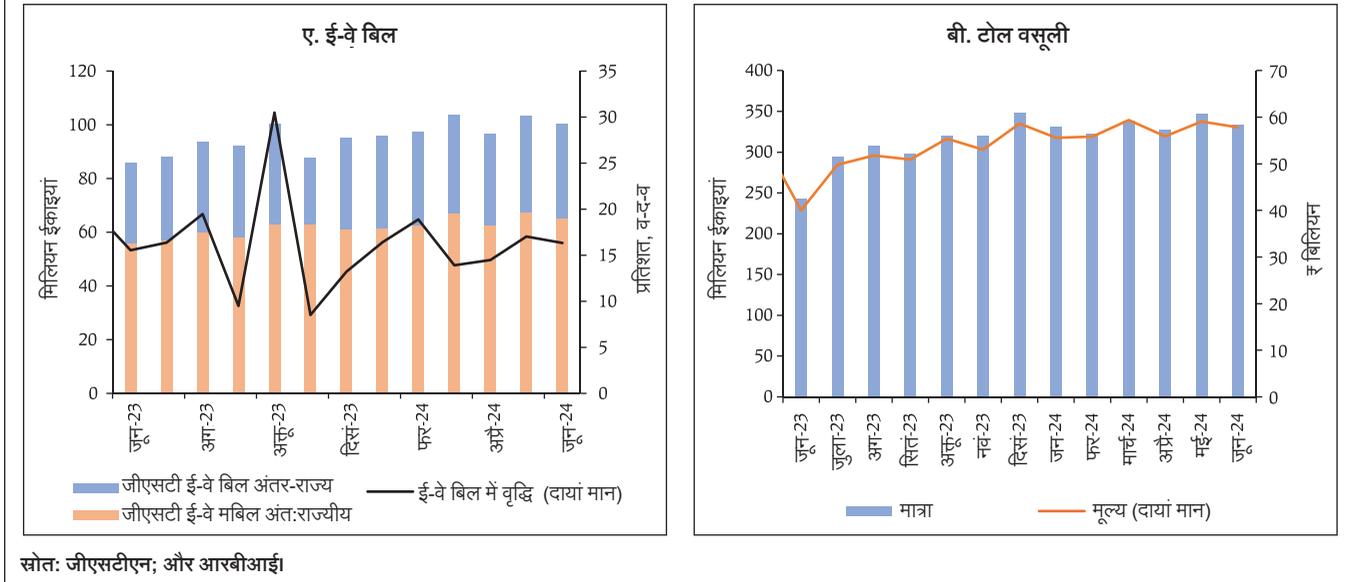
चार्ट III.1: आर्थिक गतिविधि और जीडीपी संवृद्धि तात्कालिक पूर्वानुमान



टिप्पणी : आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) का निर्माण गतिशील कारक मॉडल का उपयोग करते हुए आर्थिक गतिविधि के सत्ताईस उच्च आवृत्ति संकेतकों में अंतर्निहित सामान्य प्रवृत्तियों को लेते हुए किया गया। ईएआई फरवरी 2020 में 100 तक बढ़ गया और अप्रैल 2020 में 0 था जो गतिशीलता प्रतिबंधों के कारण सबसे अधिक प्रभावित महीना था।
स्रोत : आरबीआई; राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

¹⁴ आपूर्ति प्रबंधन संस्थान (आईएसएम) डेटा।

चार्ट III.2: ई-वे बिल और टोल वसूली

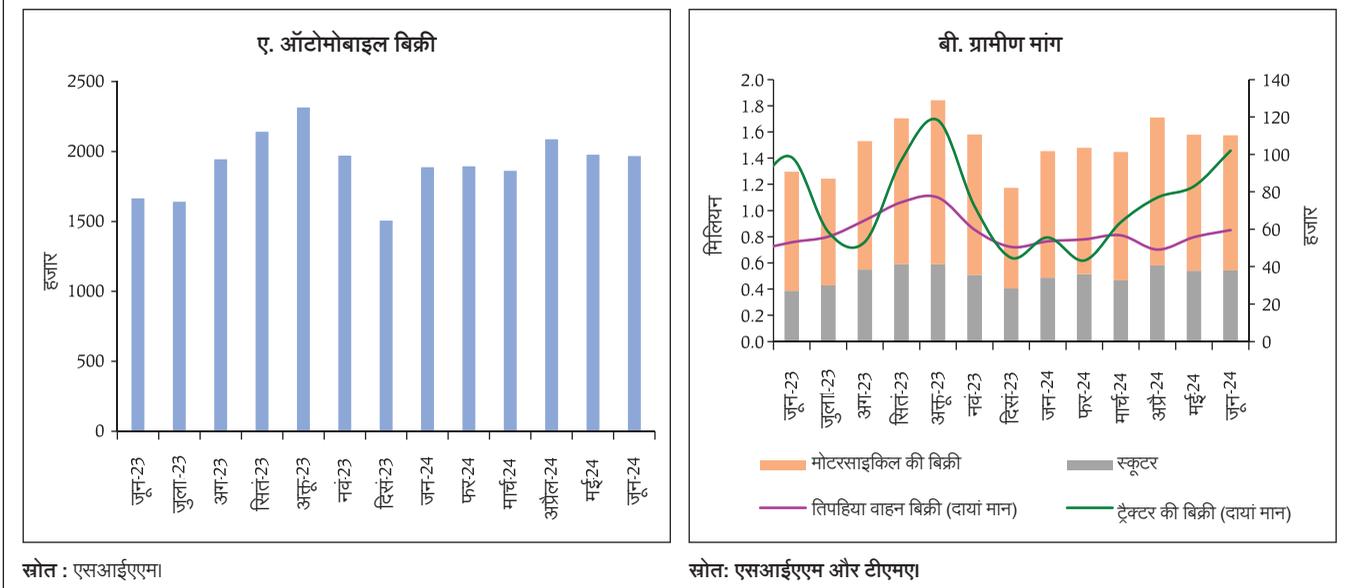


स्थिति मजबूत बनी हुई है। जून 2024 में ई-वे बिल में 16.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जिसमें अंत:राज्यीय और अंतर-राज्यीय दोनों तरह से क्रमिक वृद्धि हुई (चार्ट III.2ए)। जून 2024 में टोल संग्रह में 37.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की मजबूत वृद्धि हुई (चार्ट III.2बी)।

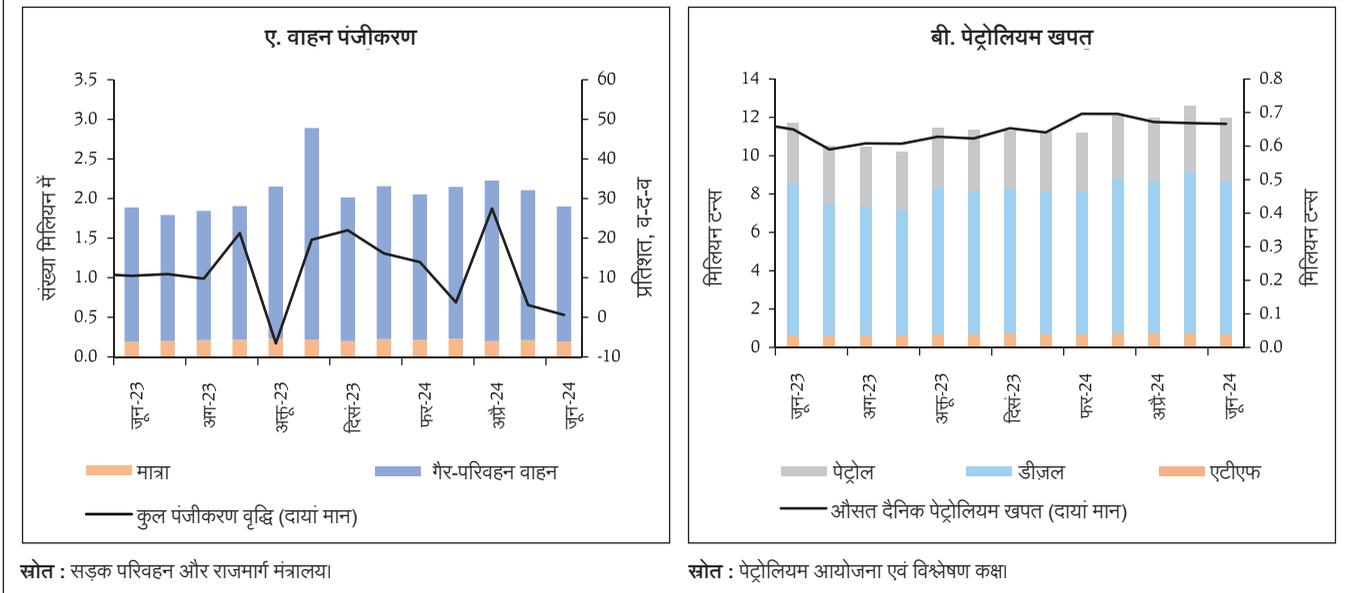
जून 2024 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में 18.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई, जिसकी अगुवाई दोपहिया

और तिपहिया वाहनों ने की और उसके बाद यात्री वाहनों का स्थान रहा, जबकि प्रवेश स्तर के वाहनों की वृद्धि कमजोर बनी रही (चार्ट III.3ए)। कृषि भावनाओं में सुधार के साथ, घरेलू ट्रैक्टर की बिक्री जून 2024 में आठ महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई, कुल मात्रा एक लाख के आंकड़े को पार कर गई (चार्ट III.3बी) जून 2024 में गैर-परिवहन वाहनों और परिवहन वाहनों दोनों क्षेत्रों में वाहन पंजीकरण में कमी आई

चार्ट III.3 ऑटोमोबाइल क्षेत्र के संकेतक



चार्ट III.4 वाहन पंजीकरण और पेट्रोलियम खपत



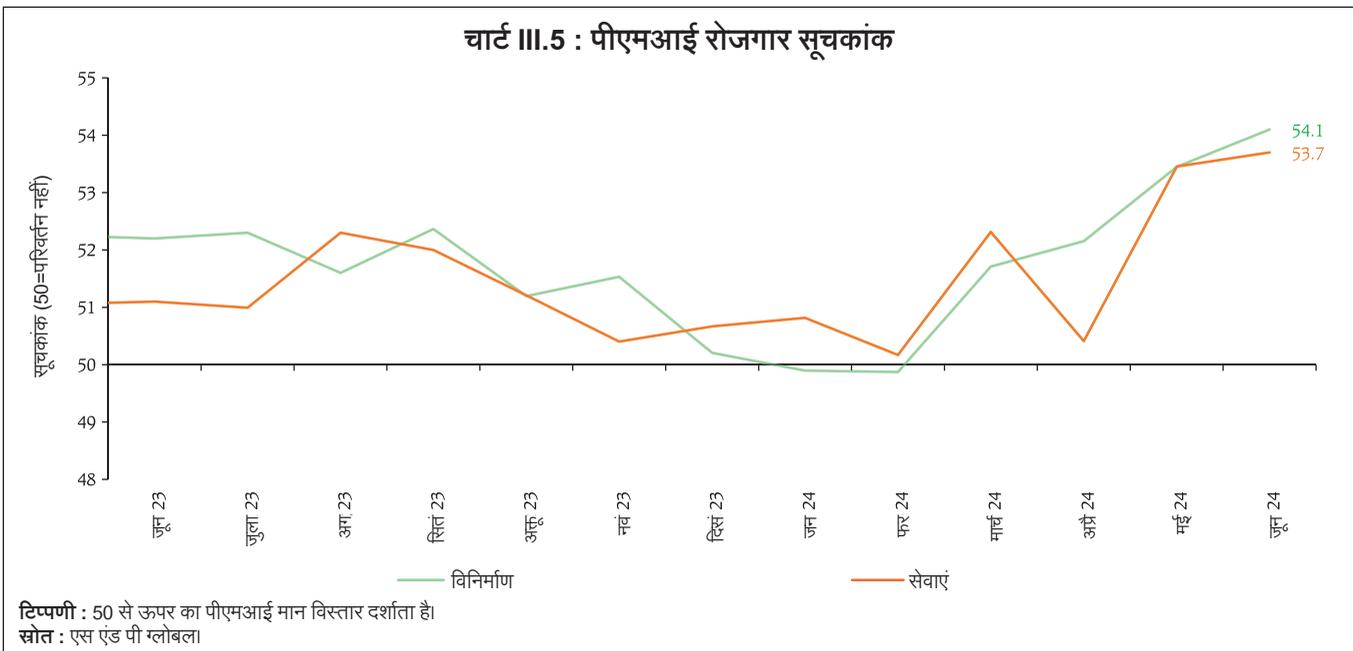
(चार्ट III.4ए)। मोटर स्पिरिट्स (पेट्रोल) और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) [चार्ट III.4बी] के कारण जून 2024 में औसत दैनिक पेट्रोलियम खपत में 2.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई।

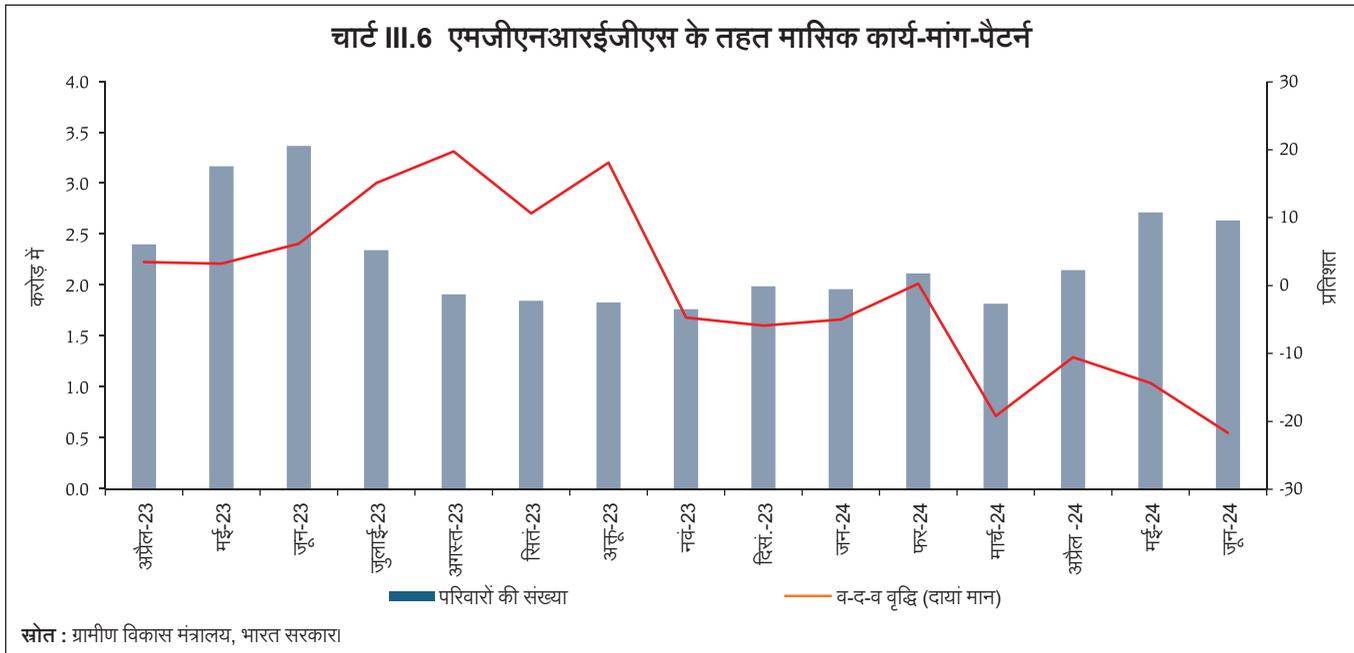
उसी महीने, संगठित विनिर्माण रोजगार, जैसा कि पीएमआई रोजगार परिदृश्य द्वारा दर्शाया गया है, ने बढ़ते उत्पादन के कारण

19 वर्षों में सबसे तेज़ विस्तार दर दर्ज की। नए व्यवसाय में उछाल के कारण सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन अगस्त 2022 के बाद से अपने सबसे मजबूत स्तर पर पहुँच गया (चार्ट III.5)।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत घरेलू कार्य मांग में जून माह में 2.9 प्रतिशत (मासिक) की मामूली गिरावट देखी गई (चार्ट III.6)।

चार्ट III.5 : पीएमआई रोजगार सूचकांक

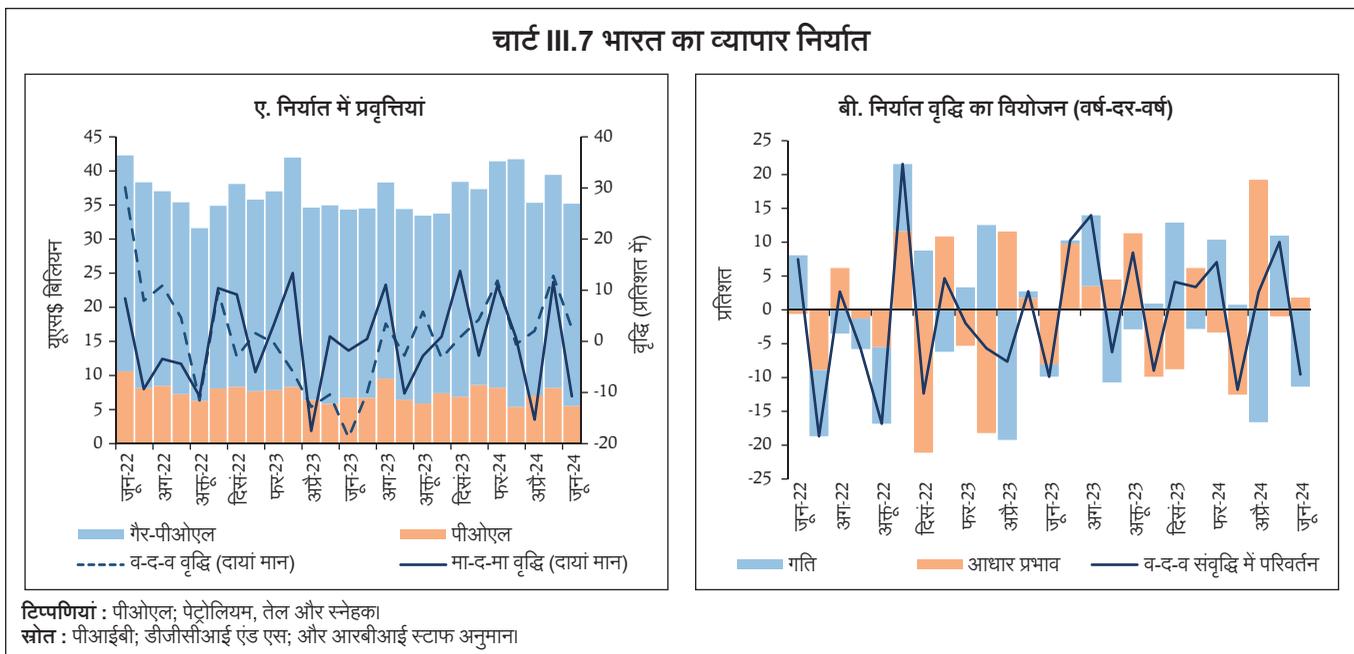


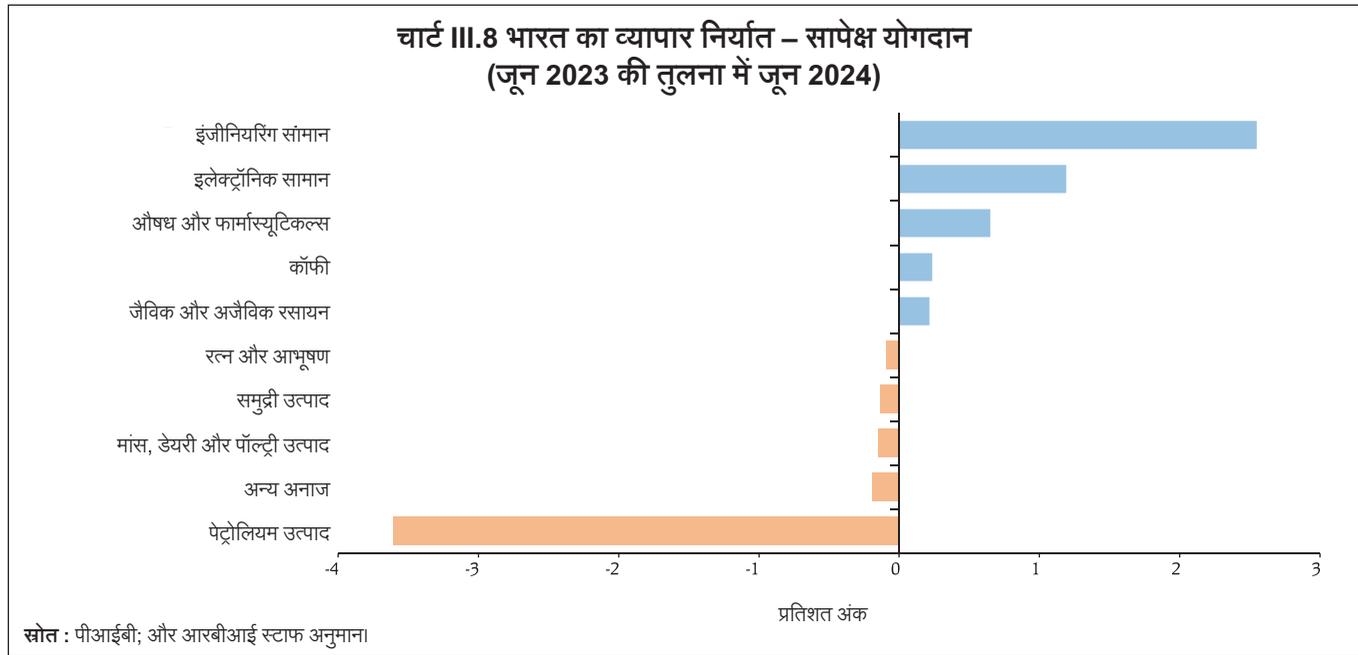


अनुक्रमिक (माह-दर-माह) गिरावट के बावजूद, अनुकूल आधार प्रभाव के कारण जून 2024 में भारत का व्यापारिक निर्यात 2.5 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) बढ़कर 35.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट III.7)।

निर्यात विस्तार व्यापक आधार पर था, क्योंकि 30 प्रमुख वस्तुओं में से 19 (निर्यात बास्केट का 62.6 प्रतिशत हिस्सा) में

वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवा और फार्मास्यूटिकल्स, कॉफी, और कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों ने जून में निर्यात वृद्धि का समर्थन किया, जबकि पेट्रोलियम उत्पाद, अन्य अनाज, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद, समुद्री उत्पाद, और रत्न और आभूषण ने वृद्धि को कम कर दिया (चार्ट III.8)।



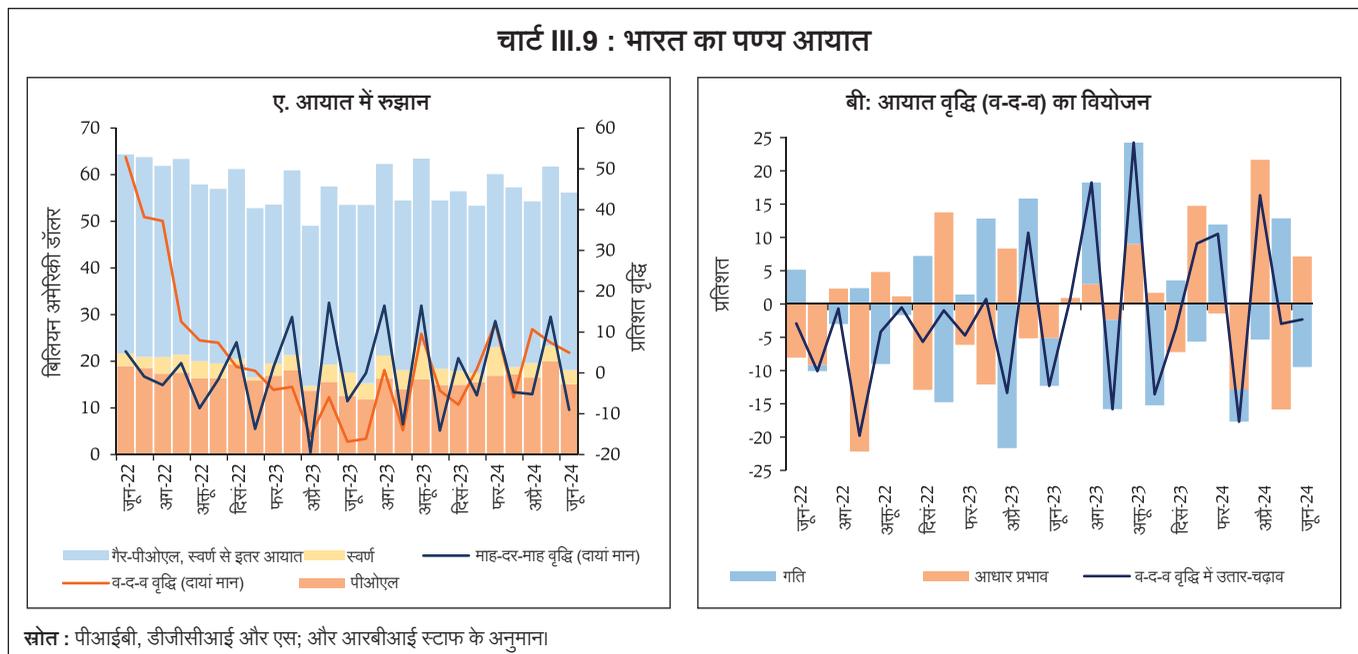


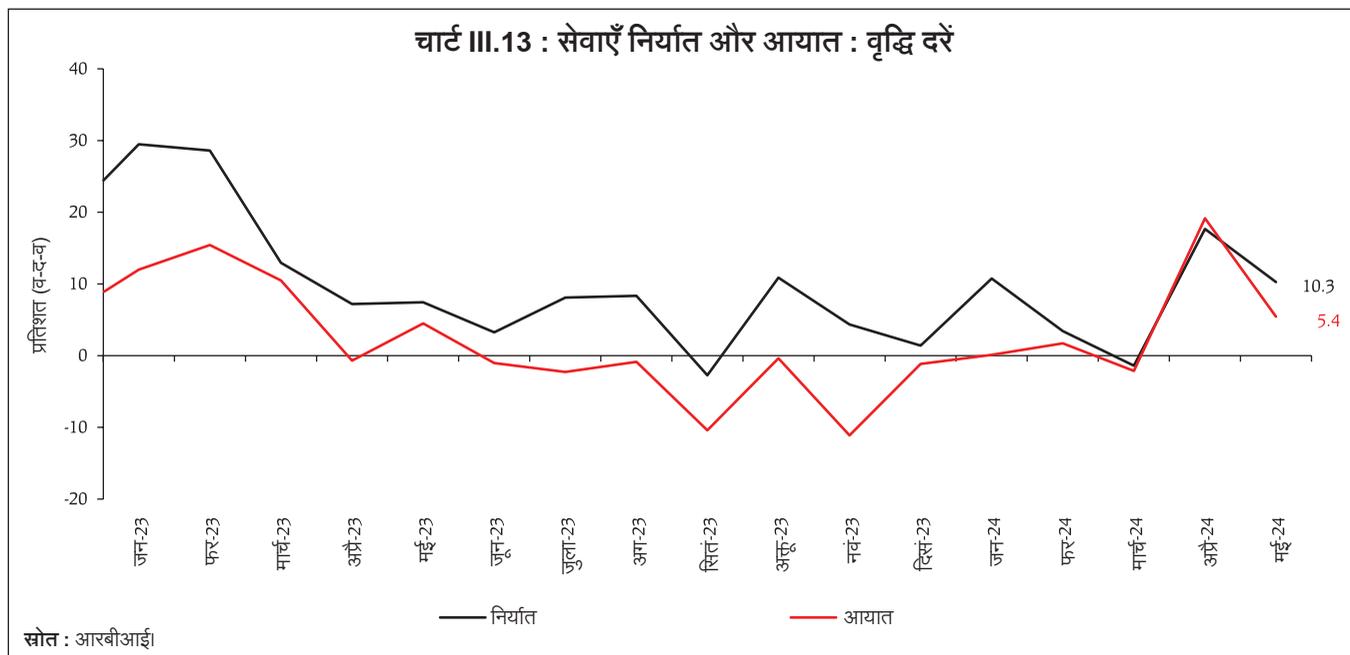
2024-25 की पहली तिमाही में, भारत का वस्तु निर्यात 5.8 प्रतिशत बढ़कर 110.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसका मुख्य कारण जून 2024 के परिणाम थे।

जून में वस्तु आयात 5.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 56.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जिसे सकारात्मक आधार प्रभाव से सहायता मिली (चार्ट III.9)। 30 प्रमुख वस्तुओं में से 21

वस्तुओं (आयात बास्केट का 71.8 प्रतिशत हिस्सा) ने जून में वर्ष दर वर्ष आधार पर वृद्धि दर्ज की।

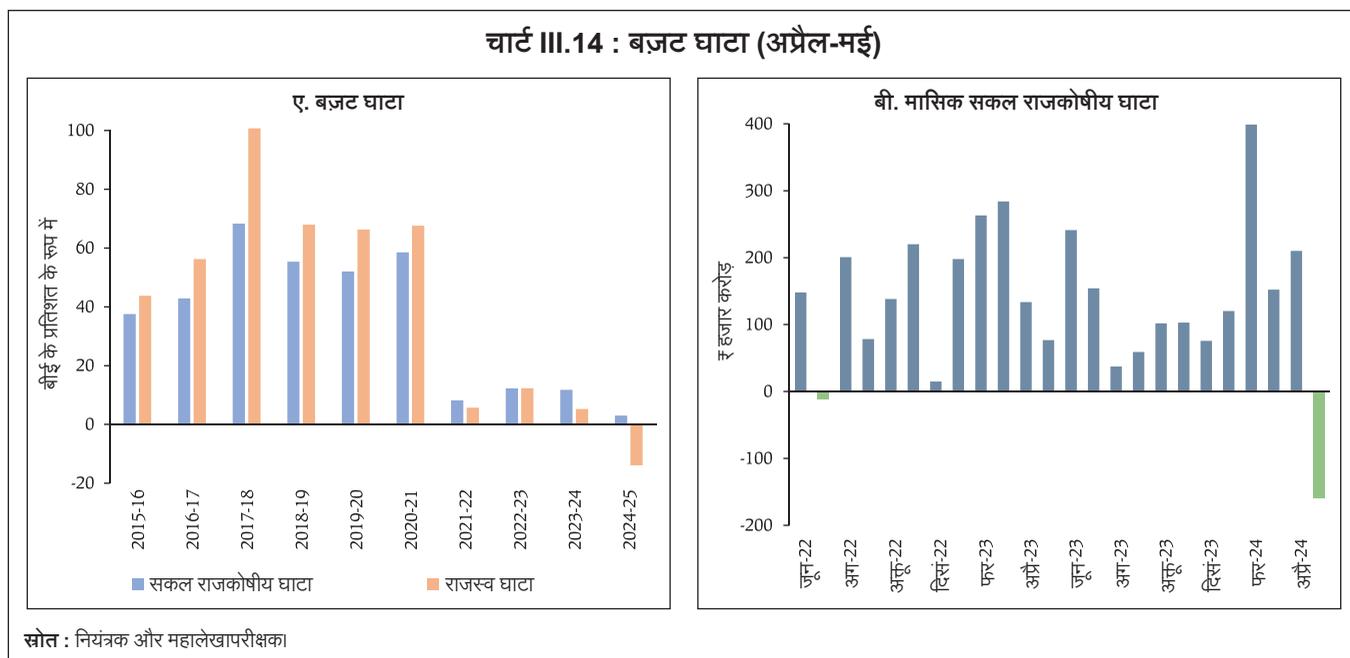
पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, अलौह धातुएं, मशीनरी और कृत्रिम रेजिन की कीमतों में वृद्धि रही, जबकि सोना, कोयला, उर्वरक, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर और रासायनिक सामग्री और उत्पाद सुस्त थे (चार्ट III.10)।





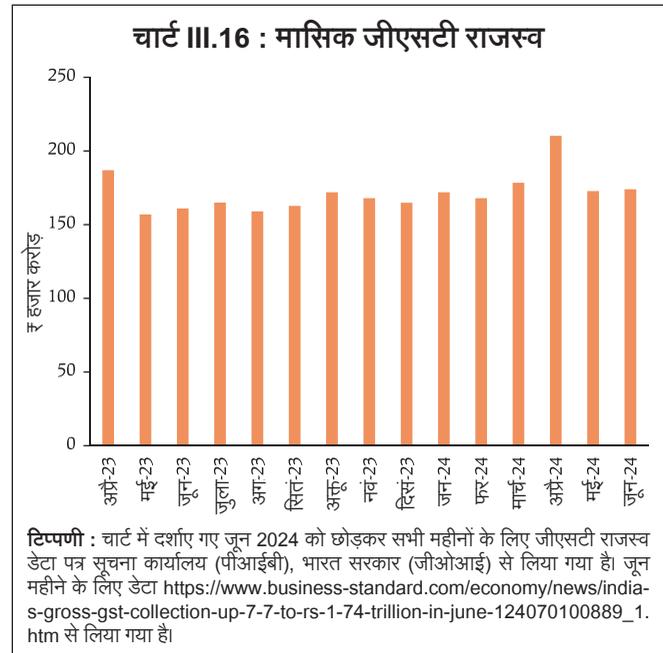
मई 2024 में, सेवाओं का निर्यात 10.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 29.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि सेवाओं का आयात 5.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट III.13)। नतीजतन, मई 2024 में शुद्ध सेवा निर्यात आय 17.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 13.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।

केंद्र सरकार के प्रमुख घाटा संकेतक, अर्थात् सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी), राजस्व घाटा (आरडी) और प्राथमिक घाटा (पीडी) में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-मई 2024 के दौरान सुधार देखा गया। जीएफडी एक वर्ष पहले के बजट अनुमानों (बीई) के 11.8 प्रतिशत के मुकाबले घटकर 3 प्रतिशत रह गया (चार्ट III.14ए)। इसके अलावा,

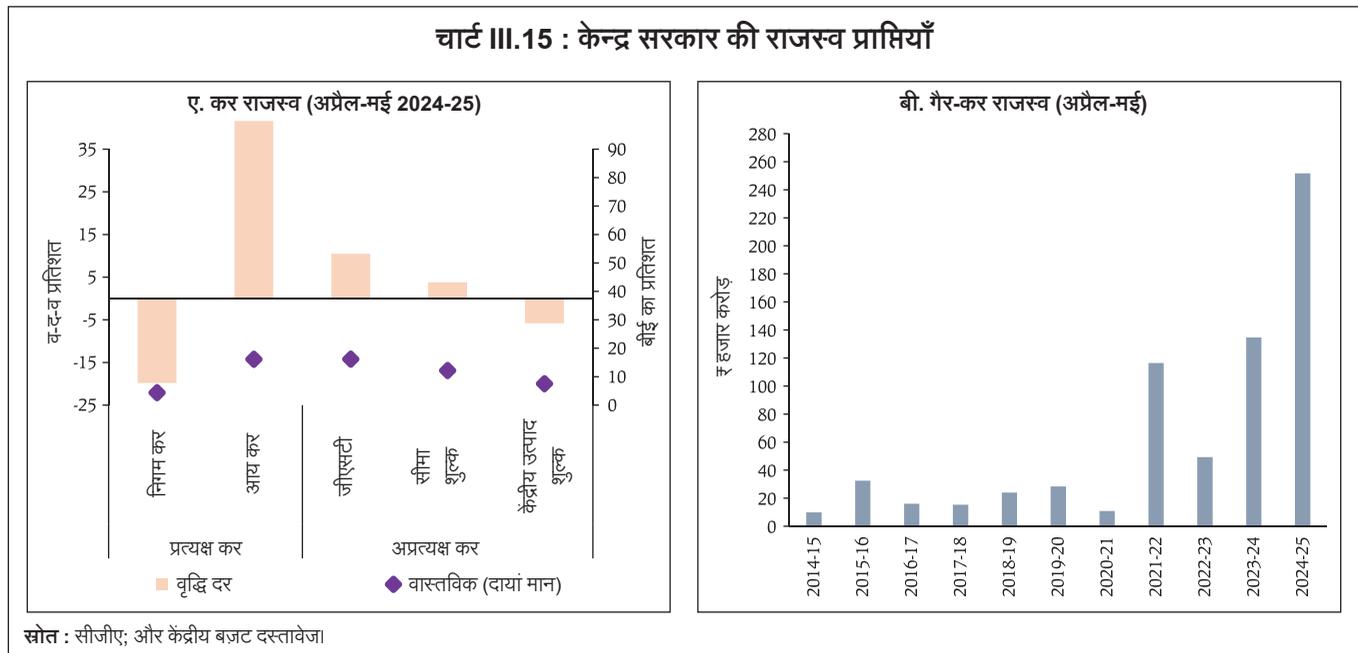


22 महीने के अंतराल के बाद मई 2024 में राजकोषीय अधिशेष दर्ज किया गया (चार्ट III.14बी)। अप्रैल-मई 2024 के दौरान केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति में यह सुधार राजस्व प्राप्तियों में मजबूत और व्यापक-आधारित वृद्धि के दम पर हुआ। दूसरी ओर, केंद्र सरकार का कुल व्यय अप्रैल-मई 2024 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.2 लाख करोड़ रुपये पर स्थिर रहा, जिसका मुख्य कारण 2024 के आम चुनावों के लिए 7 मार्च 2024 से 4 जून 2024 तक लागू आदर्श आचार संहिता है।

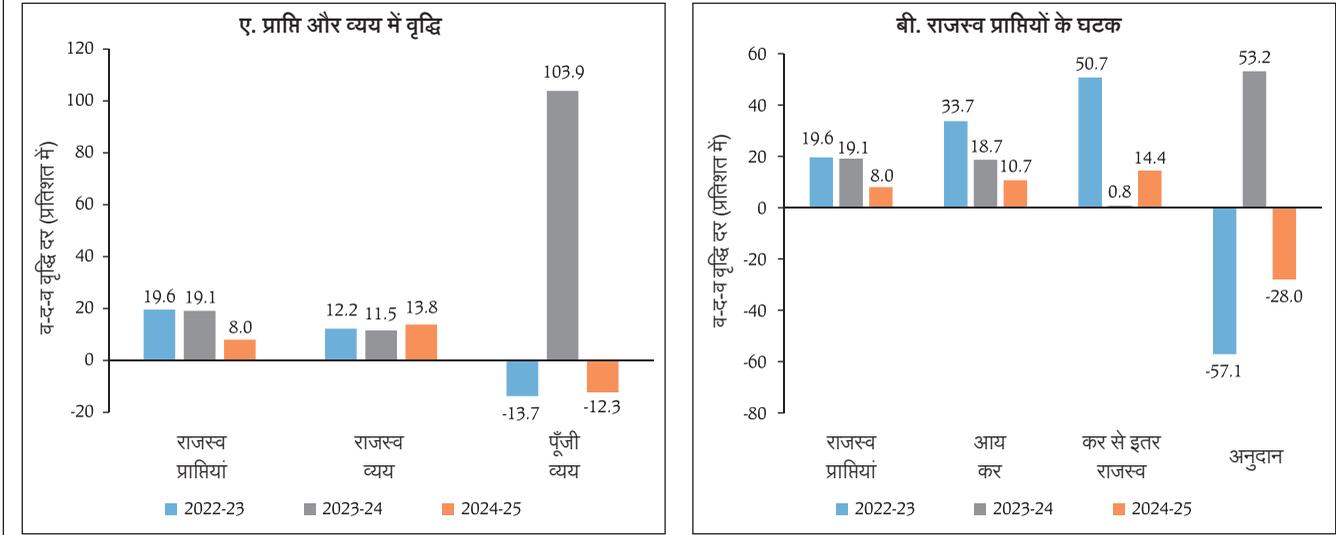
प्राप्तियों के मामले में, सकल कर राजस्व में अप्रैल-मई 2024 के दौरान 15.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में क्रमशः 24.6 प्रतिशत और 8.0 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत, निगम कर में 19.8 प्रतिशत की संकुचन दर्ज की गई, लेकिन आयकर में 41.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई। अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत, जीएसटी संग्रह और सीमा शुल्क में क्रमशः 10.5 प्रतिशत और 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.15ए)। रिज़र्व बैंक से बजट से



अधिक अधिशेष हस्तांतरण के कारण अप्रैल-मई 2024 के दौरान गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में 86.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.15बी)। दूसरी ओर, अप्रैल-मई 2024 के दौरान गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 30.2 प्रतिशत की संकुचन हुई।



चार्ट III.17: प्रमुख राजकोषीय प्रदर्शन संकेतक (अप्रैल-मई)

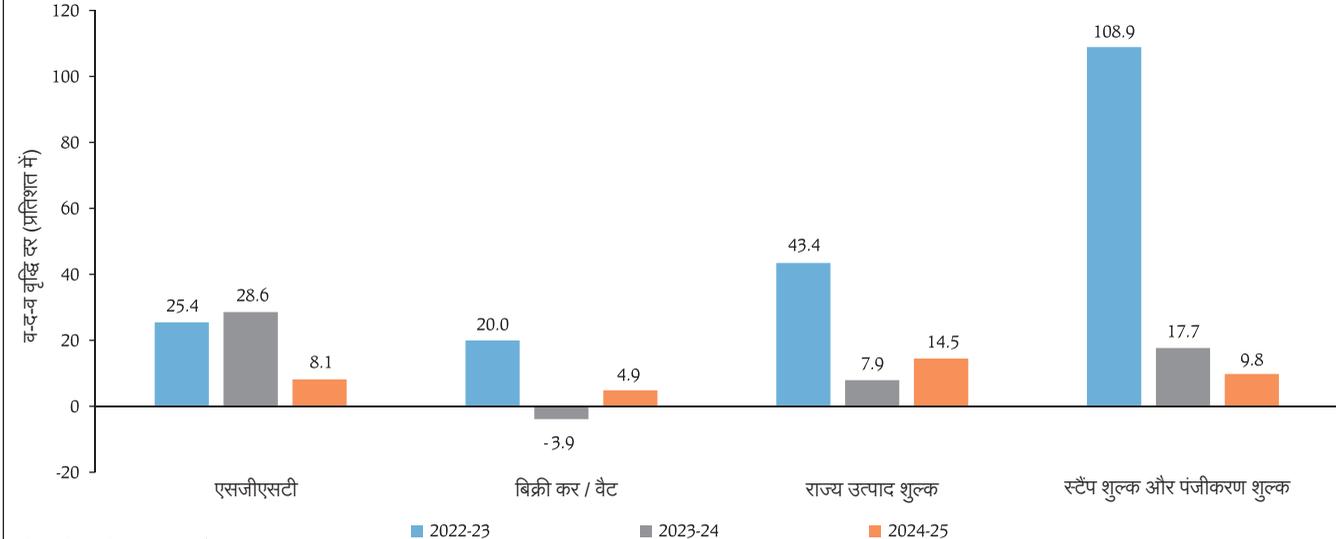


टिप्पणी : आँकड़े 24 राज्यों से संबंधित हैं।
 स्रोत : नियंत्रक और महालेखापरीक्षक।

जून 2024 के महीने के लिए सकल जीएसटी संग्रह (केंद्र और राज्य) ₹ 1.74 लाख करोड़¹⁵ रहा, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है (चार्ट III.16)। अप्रैल-जून 2024 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह

10.3 प्रतिशत बढ़कर ₹ 5.57 लाख करोड़ हो गया, जो कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी, कर अनुपालन में सुधार और कर अधिकारियों द्वारा प्रभावी प्रवर्तन को दर्शाता है।

चार्ट III.18: राज्यों के कर राजस्व के घटक



टिप्पणी : आँकड़े 24 राज्यों से जुड़े हैं।
 स्रोत : नियंत्रक और महालेखापरीक्षक।

¹⁵ https://www.business-standard.com/economy/news/india-s-gross-gst-collection-up-7-7-to-rs-1-74-trillion-in-june-124070100889_1.html [पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की ओर से जून 2024 के महीने के लिए जीएसटी संग्रह के लिए कोई प्रेस विज्ञापित जारी नहीं की गई है।]

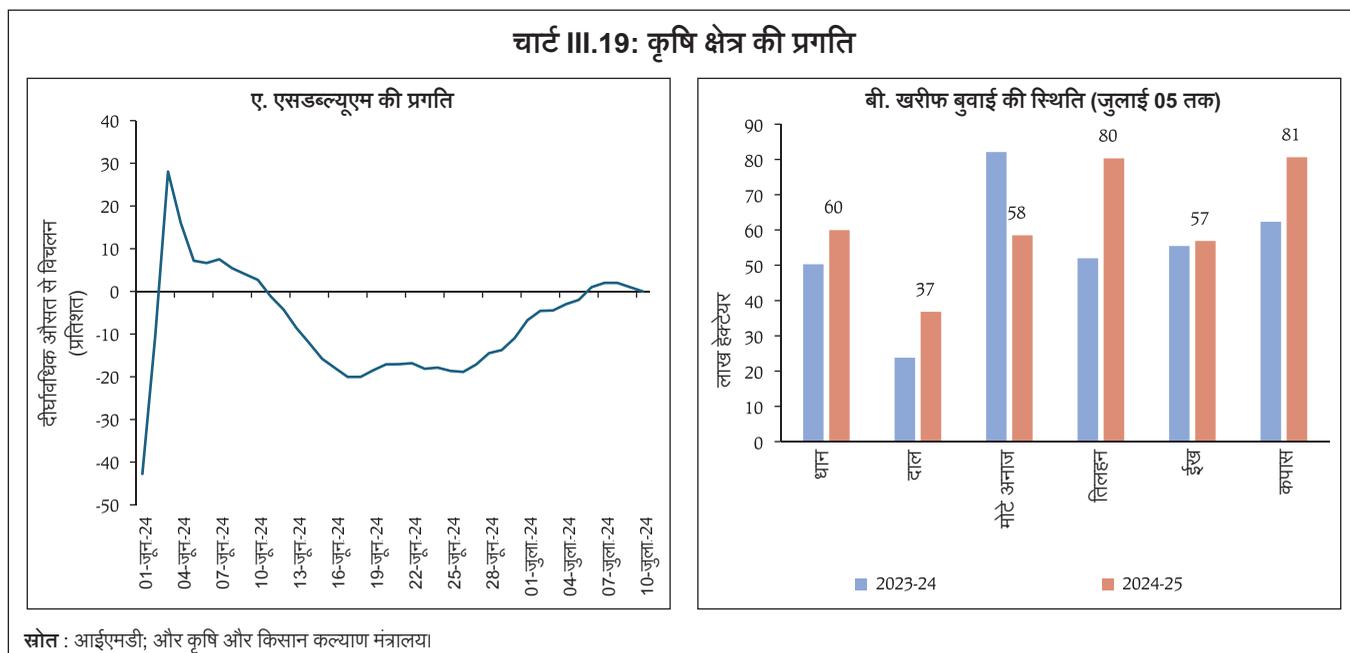
अप्रैल-मई 2024 के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि धीमी हुई है, जिसका मुख्य कारण कर राजस्व में मंदी और केंद्र सरकार से अनुदान में कमी है। इसके विपरीत, गैर-कर राजस्व में तेजी से वृद्धि हुई है। व्यय पक्ष पर, राजस्व व्यय में मामूली वृद्धि हुई, लेकिन अप्रैल-मई 2024 के दौरान पूंजीगत व्यय में कमी आई (चार्ट III.17)। राज्यों के अपने कर राजस्व के भीतर, राज्यों के माल और सेवा कर (एसजीएसटी) में वृद्धि उच्च आधार से धीमी हुई, जबकि बिक्री कर/वैट और राज्य उत्पाद शुल्क में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई (चार्ट III.18)।

पिछले वर्ष की तरह, केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय में तेजी लाने के लिए जून में राज्यों को कर हस्तांतरण की एक अतिरिक्त किस्त जारी की है। अप्रैल-जून 2024 के दौरान, राज्यों को हस्तांतरित कुल राशि ₹2.80 लाख करोड़ रही है, जबकि एक वर्ष पहले यह राशि ₹2.37 लाख करोड़ थी।^{16,17}

समग्र आपूर्ति

दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) ने 08 जुलाई की अपनी सामान्य तिथि से छह दिन पहले पूरे भारत को कवर कर लिया। 01 जून से 10 जुलाई, 2024 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर संचयी एसडब्ल्यूएम वर्षा पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान के एलपीए से 2 प्रतिशत अधिक की तुलना में अपने दीर्घकालिक औसत (एलपीए) पर रही। मैडेन जूलियन ऑसिलेशन (एमजेओ)¹⁸ की क्रमिक मजबूती और उसके बाद जून के अंत में उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बारिश के अनुकूल कम दबाव प्रणाली के निर्माण ने जून के मध्य में रुकी हुई मानसून की प्रगति में मदद की (चार्ट III.19ए)। परिणामस्वरूप, संचयी खरीफ बुआई 378.7 लाख हेक्टेयर (5 जुलाई, 2024 तक) रही, जो पूरे सीजन की सामान्य एकड़ का 34.6 प्रतिशत और पिछले वर्ष की इसी तारीख की तुलना में 14.1 प्रतिशत अधिक है (चार्ट III.19 बी)। साथ ही, देश के अधिकांश हिस्सों

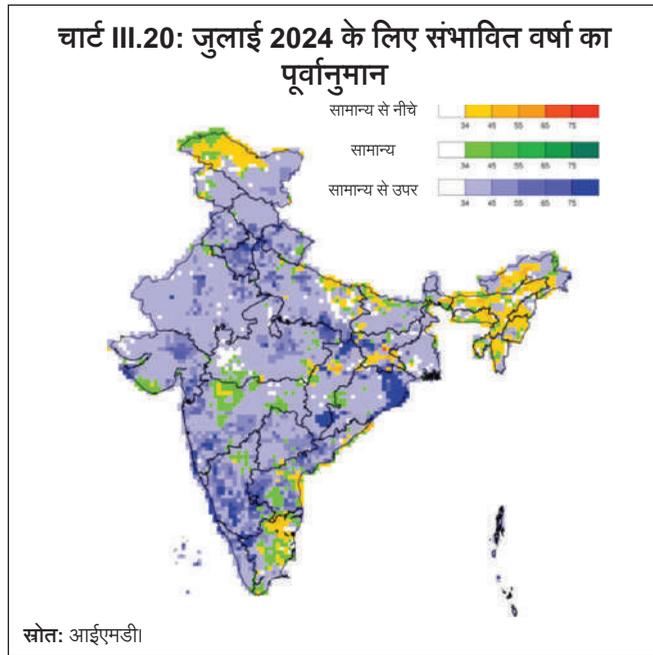
चार्ट III.19: कृषि क्षेत्र की प्रगति



¹⁶ <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2023869#:~:text=The%20Interim%20Budget%202024%2D25,2%2C79%2C500%20crore>

¹⁷ <https://cga.nic.in/MonthlyReport/Published/6/2023-2024.aspx>

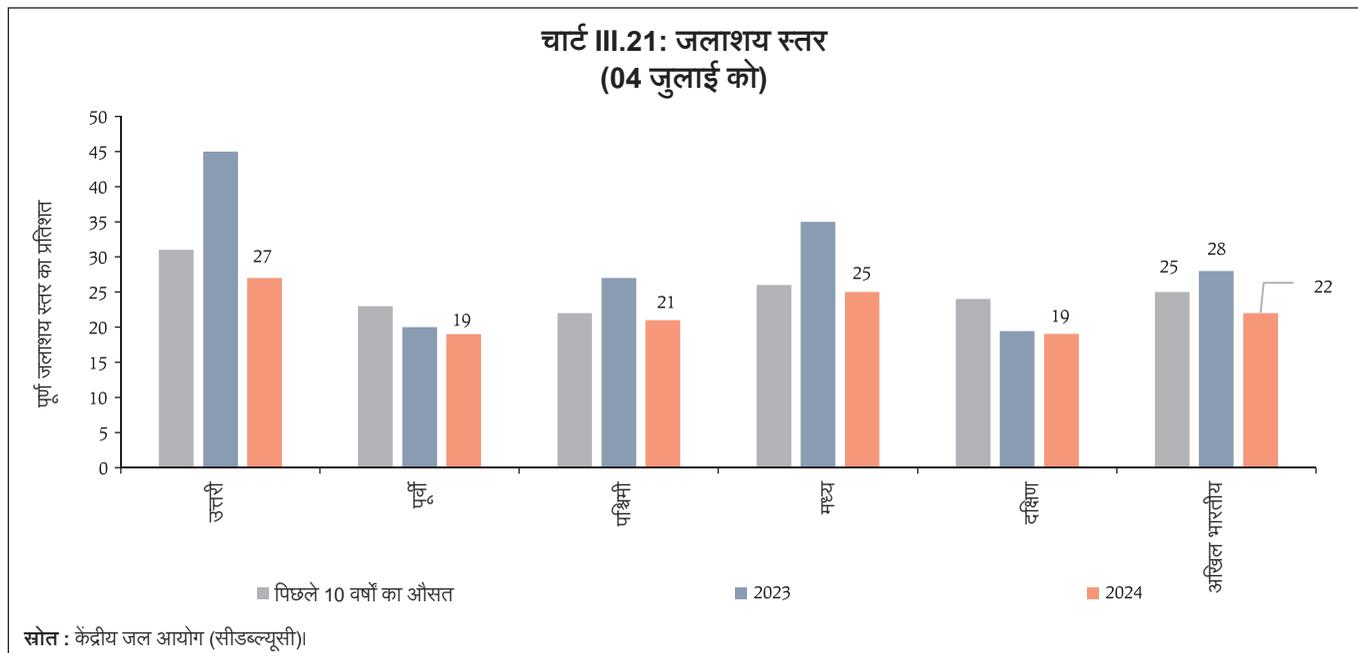
¹⁸ आईएमडी के अनुसार, एमजेओ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायुमंडल-महासागर युग्मित घटनाओं में से एक है और इसका भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसकी विशेषता यह है कि यह मुख्य रूप से हिंद और प्रशांत महासागर में देखी जाने वाली बड़ी हुई और दबी हुई उष्णकटिबंधीय वर्षा के बड़े क्षेत्रों के पूर्व की ओर फैलता है। संवहनीयता गतिविधि के आधार पर, एमजेओ की अवधि को 1-8 चरणों में विभाजित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक चरण लगभग 7 से 8 दिनों तक चलता है।



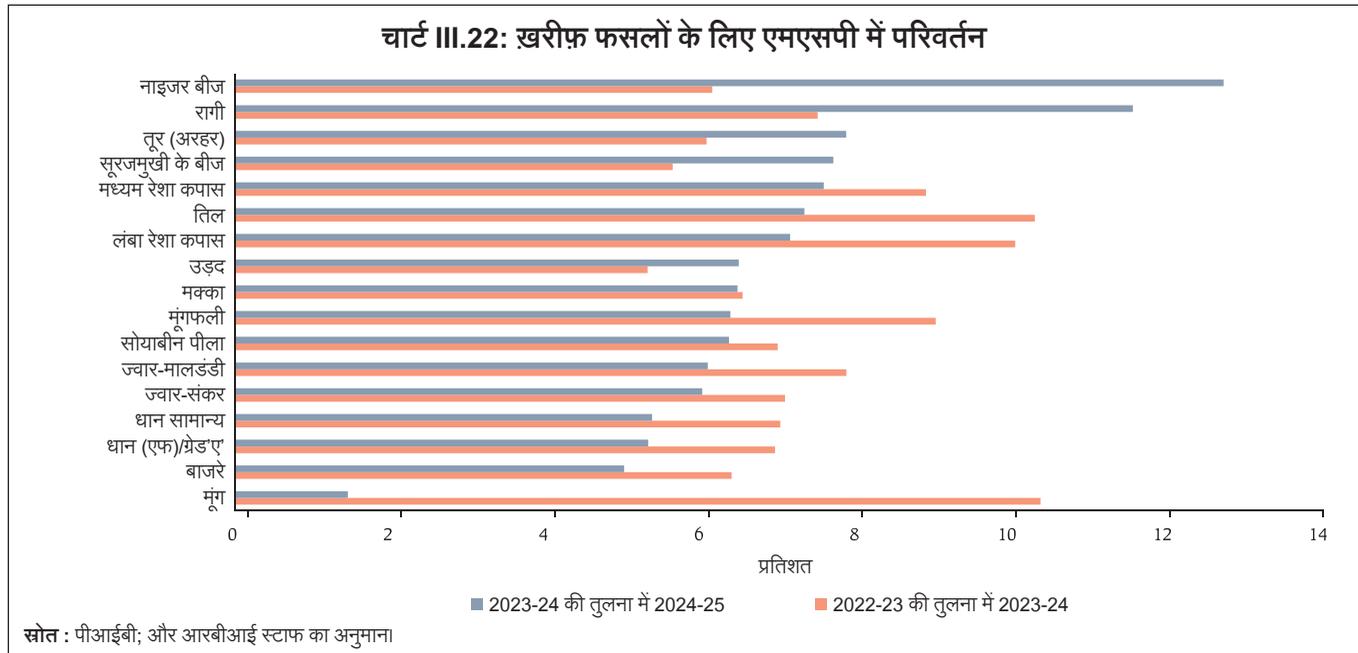
गर्मी के चलते जुलाई के दौरान अधिक बादल छाए रहने से तापमान में भी कमी आने की संभावना है।

01 जुलाई, 2024 तक चावल (बिना पिसे धान के बराबर) और गेहूं का बफर स्टॉक क्रमशः 485.0 लाख टन (मानक का 3.6 गुना) और 282.6 लाख टन (मानक के बराबर) था। 10 जुलाई, 2024 तक धान की सार्वजनिक खरीद (521.9 लाख टन) पिछले वर्ष की इसी तारीख के स्तर से 8.2 प्रतिशत कम रही। गेहूं की 266.0 लाख टन की खरीद एक साल पहले की तुलना में 1.5 प्रतिशत अधिक थी, लेकिन इस मौसम के खरीद लक्ष्य 300-320 लाख टन से कम थी। तदनुसार, केंद्र ने 24 जून, 2024 को तत्काल प्रभाव से व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों के लिए 31 मार्च, 2025 तक गेहूं पर अखिल भारतीय स्टॉक सीमा लगा दी है।¹⁹ इसके अलावा, 01 अगस्त, 2024 से गेहूं की खुले बाजार में बिक्री की योजना है। इसी तरह, *काबुली चना* सहित तुअर और चना पर भी 21 जून से 30 सितंबर, 2024 तक स्टॉक सीमा लागू की गई है।

में जुलाई के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा का भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) का पूर्वानुमान जलाशय के स्तर की पुनःपूर्ति और खरीफ बुआई की आगे की प्रगति के लिए अच्छा संकेत है (चार्ट III.20 और III.21)। मार्च के बाद से तेज हुई

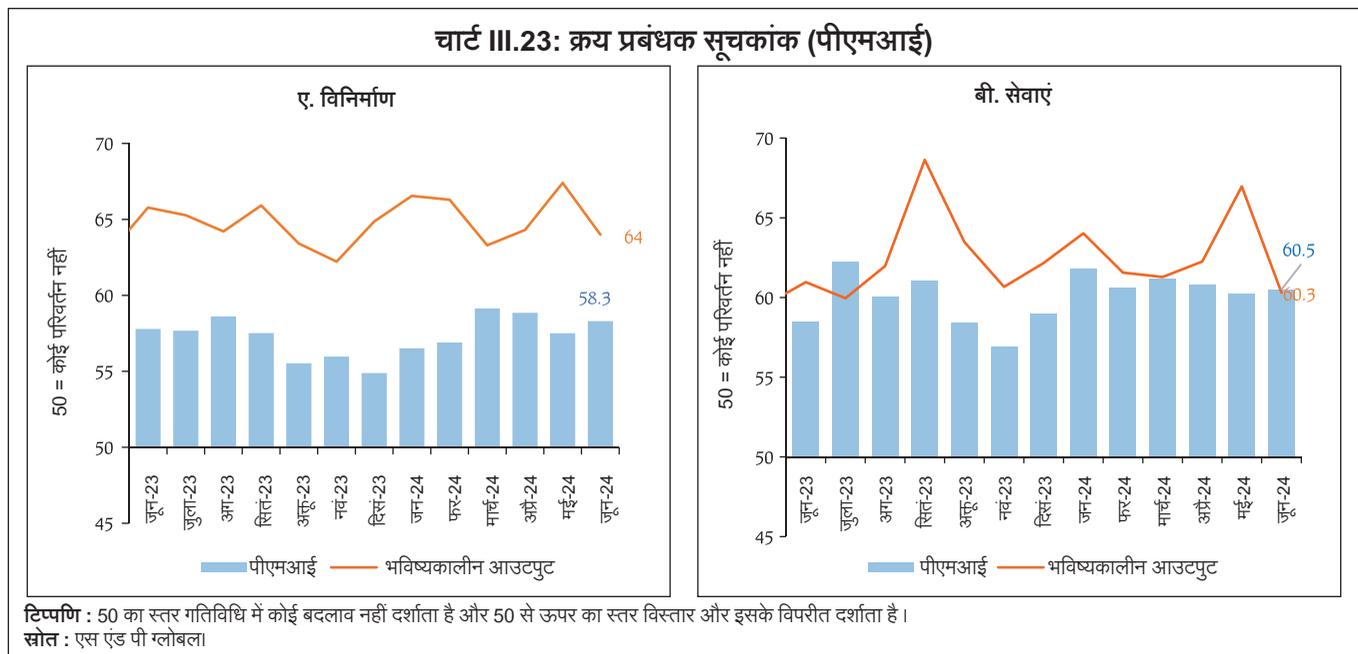


¹⁹ <https://www.financialexpress.com/policy/economy-govt-to-begin-open-market-sale-of-wheat-amp-rice-from-aug-1-3549883/>

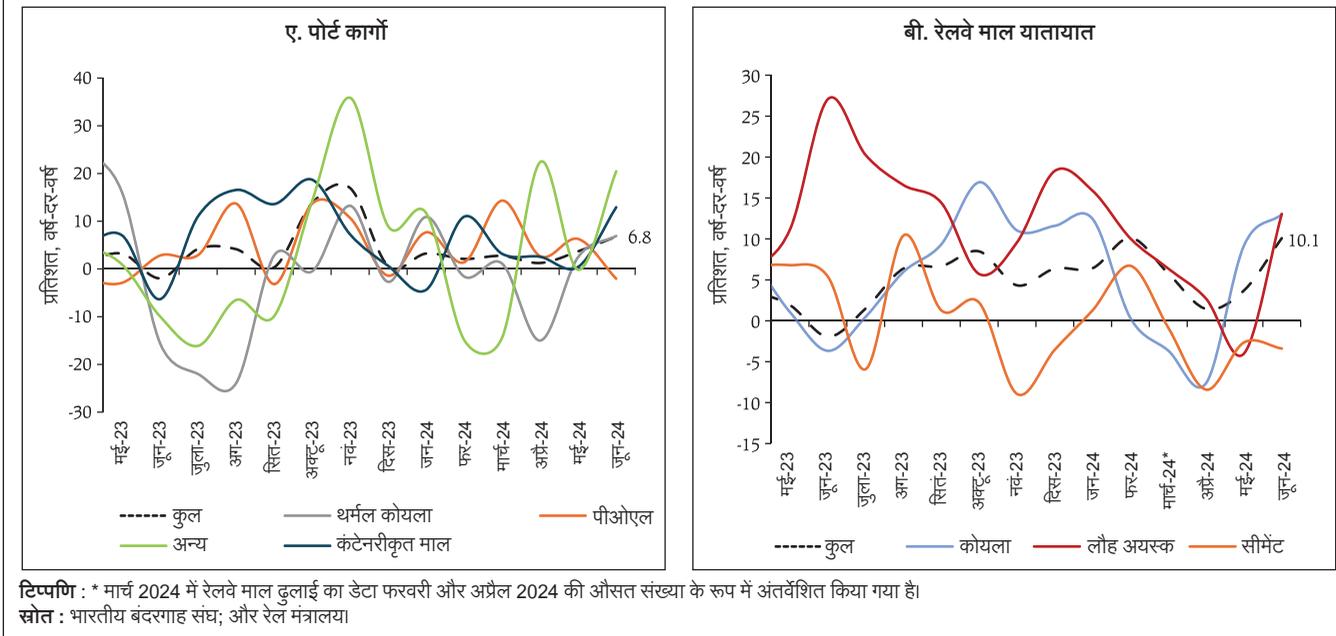


विपणन सीजन 2024-25 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए 19 जून, 2024 को 14 प्रमुख खरीफ़ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की गई थी। एमएसपी को 1.4 प्रतिशत से 12.7 प्रतिशत की सीमा में संशोधित किया गया है (चार्ट III.22)। अधिकांश फसलों के लिए, यह वृद्धि उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुरूप है।

नए कार्यदेश और उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण, जून 2024 में भारत की विनिर्माण पीएमआई रीडिंग बढ़कर 58.3 हो गई (चार्ट III.23ए)। सेवाओं के लिए पीएमआई मई के 60.2 से बढ़कर जून 2024 में 60.5 हो गया। हालाँकि, बाजार की अनिश्चितता और मूल्य प्रतिस्पर्धा के कारण भविष्य की गतिविधि (कारोबारी प्रत्याशाएं) 11 महीने के निचले स्तर पर गिर गई (चार्ट III.23बी)।



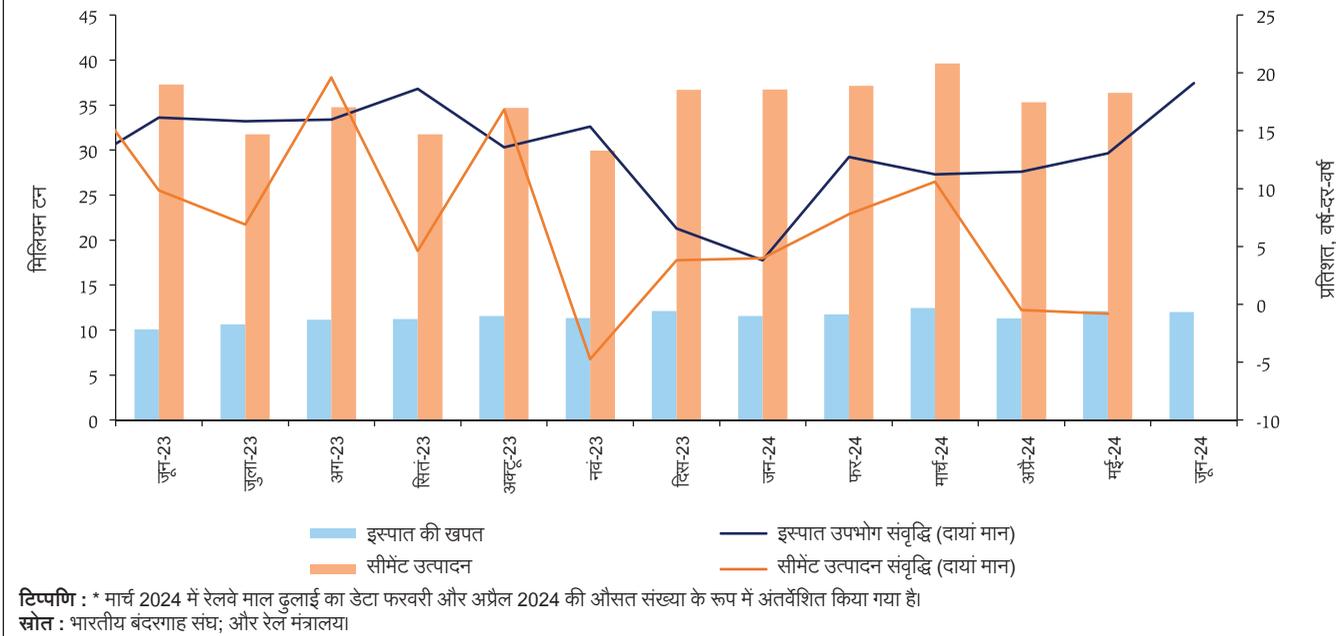
चार्ट III.24: पोर्ट कार्गो और रेलवे माल यातायात



जून 2024 में माल परिवहन के संकेतक अच्छे रहे। कंटेनरीकृत और अन्य विविध कार्गो के कारण प्रमुख बंदरगाहों पर यातायात में 6.8 प्रतिशत का विस्तार दर्ज किया गया (चार्ट III.24e)। कोयला और लौह अयस्क यातायात में वृद्धि के कारण, जून में रेलवे माल यातायात में भी तेजी आई (चार्ट III.24बी)।

निर्माण क्षेत्र ने मिश्रित संकेत दिखाए क्योंकि जून 2024 में स्टील की खपत में सालाना 19.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि सीमेंट उत्पादन पिछले दो महीनों से गिरावट के दौर में है (चार्ट III.25)।

चार्ट III.25: इस्पात की खपत और सीमेंट उत्पादन



सारणी III.1: उच्च आवृत्ति संकेतक- सेवाएं

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

क्षेत्र	संकेतक	सितं-23	अक्टू-23	नवं-23	दिसं-23	जन-24	फर-24	मार्च-24	अप्रैल-24	मई-24	जून-24
शहरी मांग	यात्री वाहनों की बिक्री	3.1	17.3	4.3	3.2	13.9	5.7	8.9	1.2	4.3	4.9
ग्रामीण मांग	दोपहिया वाहनों की बिक्री	0.8	20.1	31.3	16.0	26.2	30.0	15.3	30.8	10.1	21.3
	तिपहिया वाहनों की बिक्री	47.0	42.1	30.8	30.6	9.5	4.6	4.3	14.5	14.4	12.3
	ट्रैक्टर बिक्री	-14.7	-4.3	6.4	-19.8	-15.3	-30.6	-23.1	-3.0	0.0	3.6
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार	वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री	6.9		3.2				-3.8		3.5	
	रेलवे माल यातायात	6.7	8.5	4.3	6.4	6.4	10.1	8.6	1.4	3.7	10.1
	बंदरगाह कार्गो यातायात	0.3	13.8	16.9	0.6	3.2	2.1	2.7	1.3	3.8	6.8
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात*	-4.5	10.6	9.0	8.7	10.0	7.6	8.7	0.3	10.3	6.7
	अंतर्राष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात*	2.7	15.0	4.9	12.2	19.3	25.7	22.5	16.2	19.2	12.3
	घरेलू हवाई यात्री यातायात*	19.3	10.7	8.7	8.1	5.0	2.2	4.7	3.8	5.9	6.6
	अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात*	19.6	17.5	19.8	18.1	17.0	15.2	15.0	16.8	19.6	13.2
	जीएसटी ई-वे बिल (कुल)	9.5	30.5	8.5	13.2	16.4	18.9	13.9	14.5	17.0	16.3
	जीएसटी ई-वे बिल (राज्यांतरिक)	12.4	30.0	22.7	14.2	17.9	21.1	15.8	17.3	18.9	16.4
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतरराज्यीय)	4.9	31.2	-16.2	11.4	13.8	15.0	10.7	9.6	13.6	16.3
	होटल अधिभोग दर@	61.0	62.5	63.0	70.0	66.6	72.5	64.4	62.3	60.3	
	प्रति कमरा औसत राजस्व	18.3	14.8	15.9	12.8	11.0	4.1	6.7	4.8	1.8	
	पर्यटकों का आगमन	17.5	19.8	16.8	7.8	10.4	15.8	8.0	7.7	0.3	
निर्माण	स्टील की खपत	18.6	13.6	15.4	6.5	3.8	12.7	11.2	11.5	13.1	19.1
	सीमेंट उत्पादन	4.7	17.0	-4.8	3.8	4.0	7.8	10.6	-0.5	-0.8	
पीएमआई सूचकांक#	सेवाएं	61.0	58.4	56.9	59.0	61.8	60.6	61.2	60.8	60.2	60.5

<< संकुचन ----- विस्तार >>

नोट: #: डेटा स्तरों में है। *: जून 2024 का डेटा दैनिक आंकड़ों के मासिक औसत पर आधारित है। @: डेटा दर में है, साल-दर-साल वृद्धि दर में नहीं। जुलाई-2021 से अब तक की अवधि के लिए प्रत्येक संकेतक के लिए हीट-मैप का निर्माण किया गया है।

स्रोत: एसआईएम; रेल मंत्रालय: ट्रैक्टर और मशीनीकरण एसोसिएशन; भारतीय बंदरगाह संघ: आर्थिक सलाहकार कार्यालय; जीएसटीएन; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण: एचवीएस एनारॉक; पर्यटन मंत्रालय; संयुक्त संयंत्र समिति; और आईएचएस मार्किट।

जून 2024 में सेवा क्षेत्र के लिए उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतक आर्थिक गतिविधि के लचीलेपन को दर्शाते हैं (सारणी III.1)।

मुद्रास्फीति

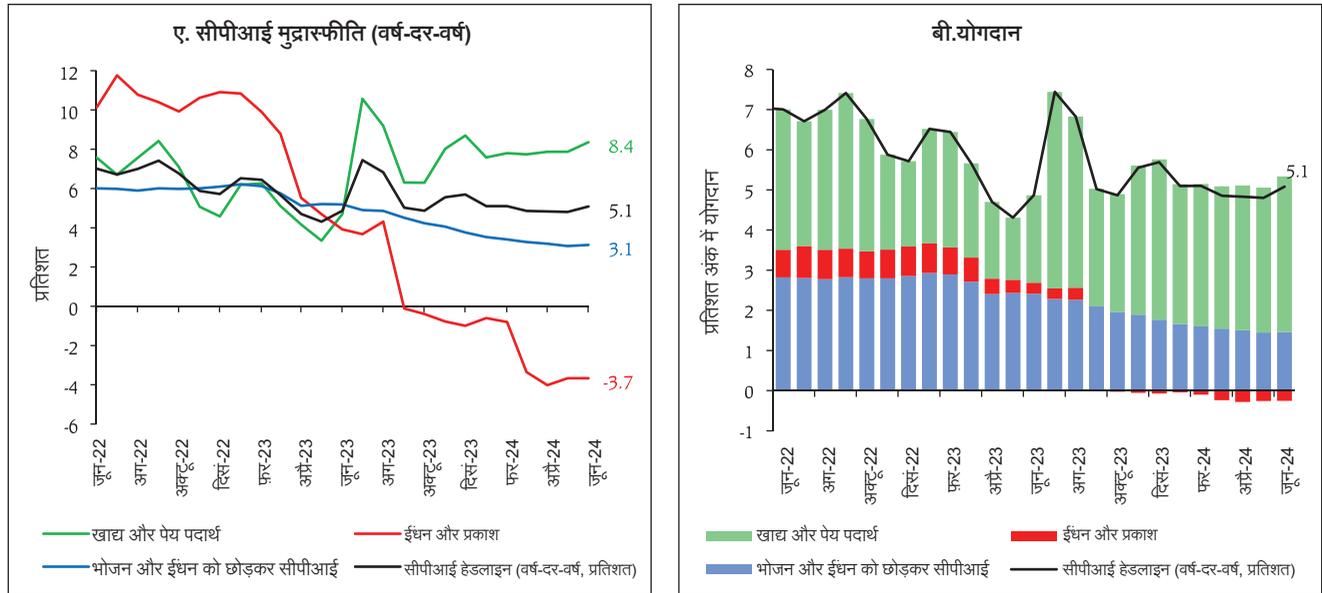
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)²⁰ में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों द्वारा मापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति, मई में 4.8 प्रतिशत से बढ़कर जून 2024 में 5.1 प्रतिशत हो गई (चार्ट III.26)। मुद्रास्फीति में 28 बीपीएस की वृद्धि 133

बीपीएस की सकारात्मक गति से हुई, जो 106 बीपीएस के अनुकूल आधार प्रभाव से कहीं अधिक है। खाद्य में 269 बीपीएस, ईंधन में 6 बीपीएस और कोर गुप में 12 बीपीएस (यानी, खाद्य और ईंधन को छोड़कर) की सकारात्मक गति के कारण समग्र सीपीआई में माह-दर-माह वृद्धि हुई थी।

खाद्य मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) मई के 7.9 प्रतिशत से बढ़कर जून में 8.4 प्रतिशत हो गई, क्योंकि सकारात्मक मूल्य गति अनुकूल आधार प्रभाव से कहीं अधिक है। उप-

²⁰ 12 जुलाई, 2024 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार।

चार्ट III.26: सीपीआई मुद्रास्फीति के रुझान और चालक

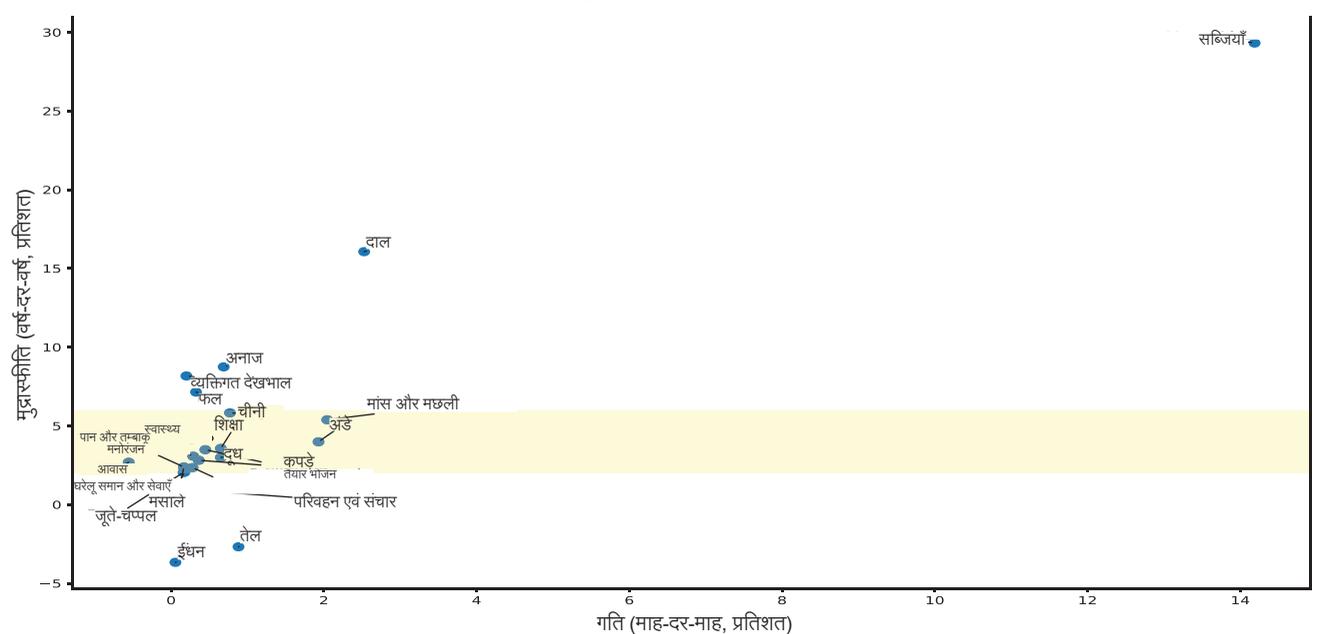


स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

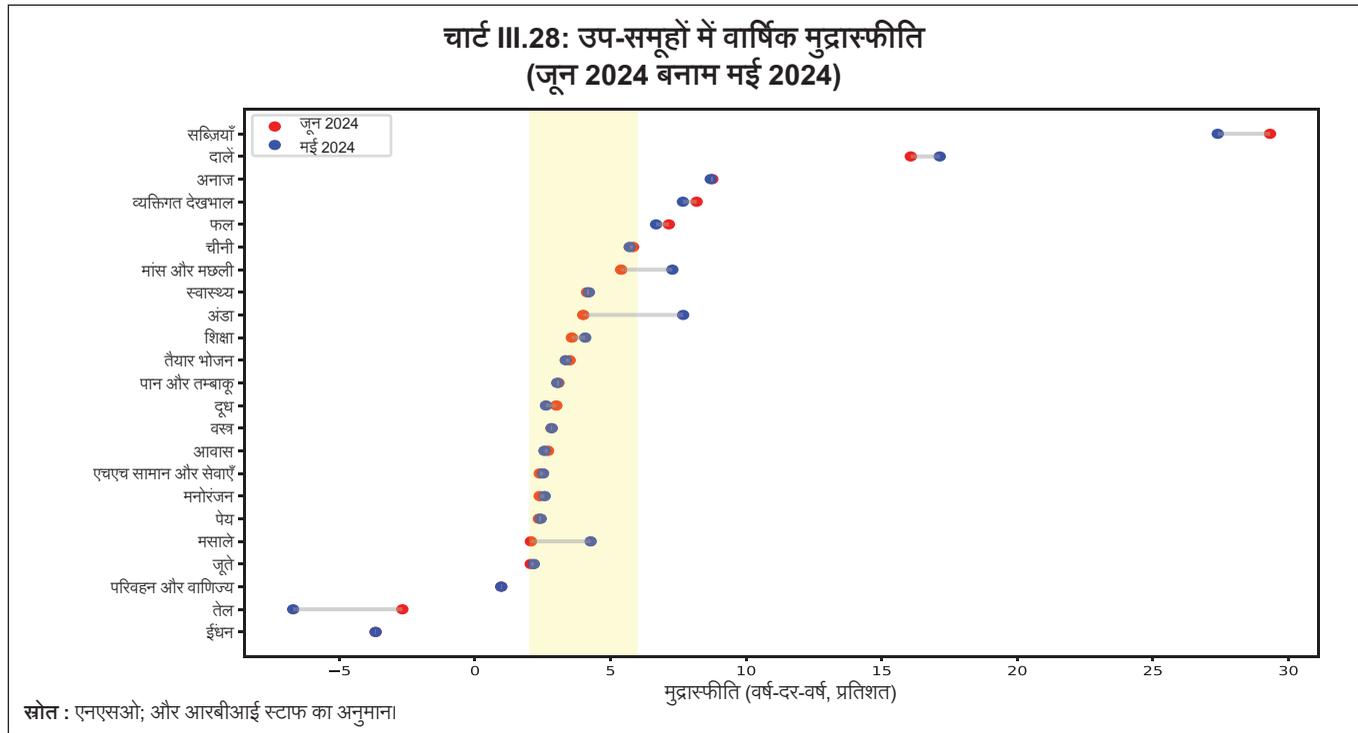
समूहों के संदर्भ में, अनाज, दूध और उत्पाद, फल, चीनी और तैयार भोजन में मुद्रास्फीति बढ़ी, जबकि मांस और मछली, अंडे, दालें और मसालों में नरमी दर्ज की गई। सब्जियों की

कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गई। खाद्य तेलों और वसा में अपस्फीति की कम दर दर्ज की गई (चार्ट III.27)।

चार्ट III.27: उप-समूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) और गति (माह-दर-माह)

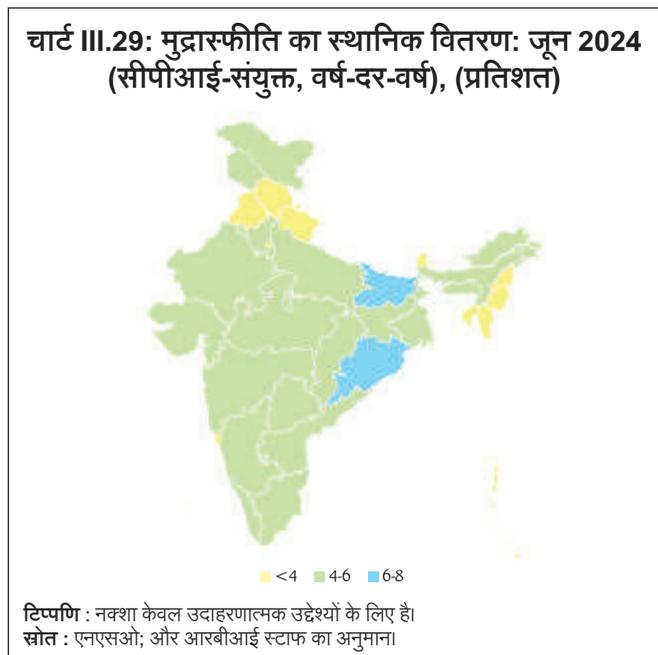


स्रोत : एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।



जून में ईंधन और प्रकाश अपस्फीति (-)3.7 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही। जबकि केरोसीन और बिजली की कीमतों में कम वृद्धि हुई, एलपीजी की कीमतों में अपस्फीति जारी रही।

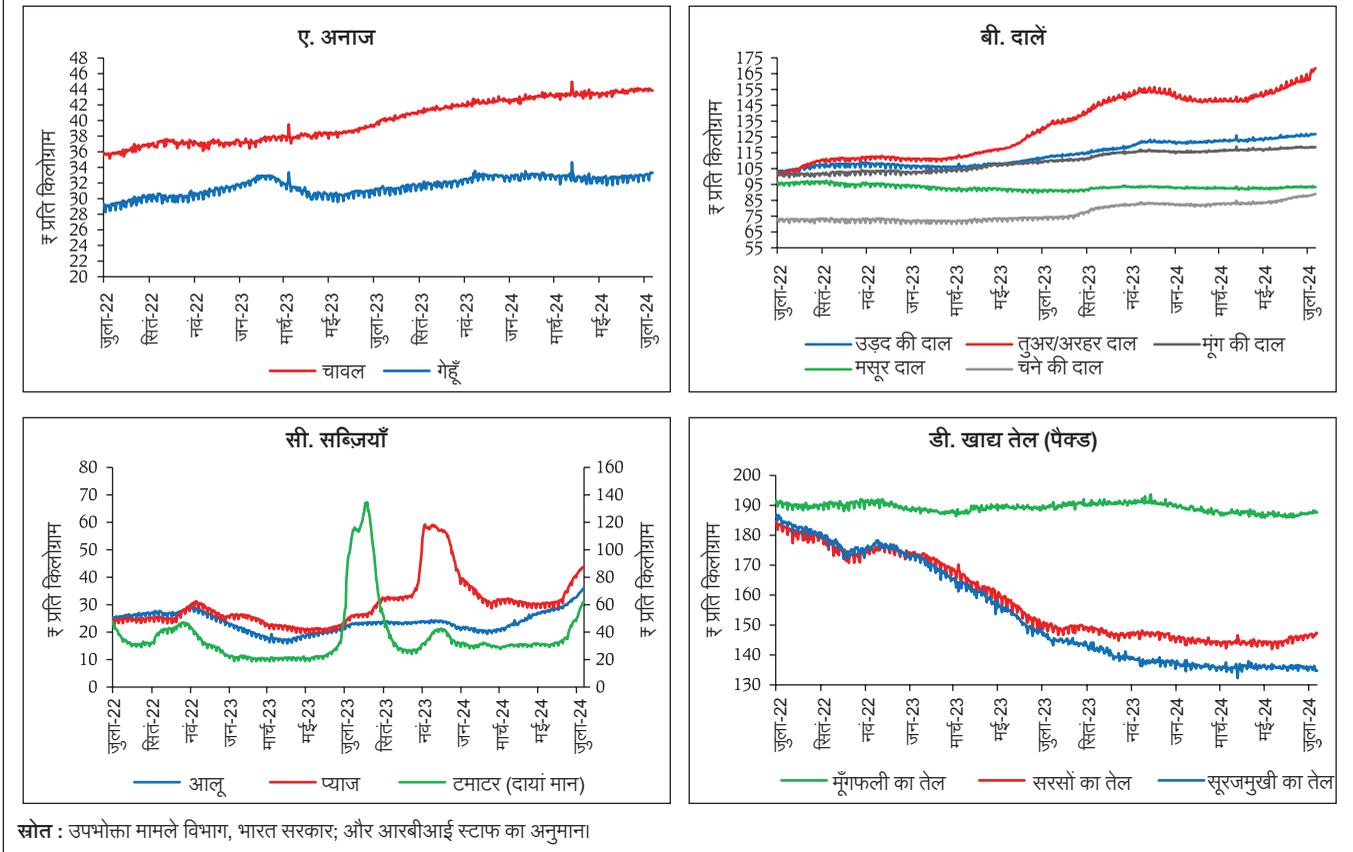
जून में मुख्य मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही। उप-समूहों के संदर्भ में, पान, तम्बाकू और नशीले पदार्थों, आवास और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभावों में मुद्रास्फीति बढ़ी, जबकि घरेलू वस्तुओं और सेवाओं, स्वास्थ्य, मनोरंजन और आमोद और शिक्षा के संबंध में इसमें नरमी दर्ज की गई और कपड़े व जूते, तथा परिवहन और संचार में यह स्थिर रही। (चार्ट III.28)।



क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, ग्रामीण मुद्रास्फीति जून 2024 में 5.7 प्रतिशत थी, जो 4.4 प्रतिशत की शहरी मुद्रास्फीति से अधिक थी। अधिकांश राज्यों में मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से कम दर्ज की गई (चार्ट III.29)।

जुलाई (12 तारीख तक) के अब तक के उच्च आवृत्ति खाद्य मूल्य डेटा से पता चलता है कि अनाज की कीमतों में हुई वृद्धि, मुख्य रूप से गेहूं के कारण हुई है। दालों की कीमतों में भी वृद्धि दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण चना और अरहर/तूरर है। खाद्य तेल विशेषकर, सरसों और मूंगफली तेल की कीमतों में भी वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.30)।

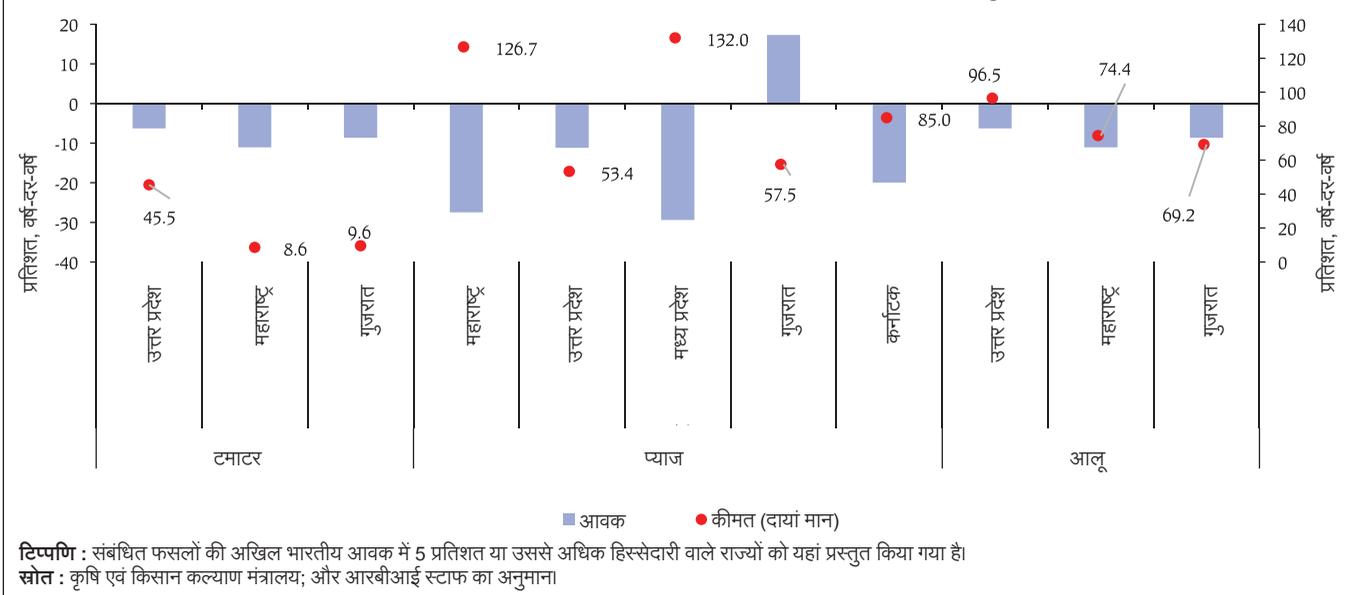
चार्ट III.30: डीसीए आवश्यक वस्तु कीमतें



प्रमुख सब्जियों में से, टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में जुलाई में अब तक क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई है (चार्ट III.30सी)।

यह मुख्य रूप से आवक में उल्लेखनीय गिरावट के कारण हुआ है, जो संभवतः प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में लू और बेमौसम

चार्ट III.31: शीर्ष सब्जियों की मंडी कीमतों में उछाल (01 अप्रैल - 03 जुलाई, 2024)



सारणी III.2 पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

मदें	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		जुलाई-23	जून-24	जुलाई-24 [^]	जून-24	जुलाई-24 [^]
पेट्रोल	₹/लीटर	102.92	100.89	100.97	0.0	0.1
डीजल	₹/लीटर	92.72	90.68	90.42	0.0	-0.3
केरोसीन (सब्सिडीकृत)	₹/लीटर	44.23	46.61	46.65	-6.8	0.1
एलपीजी (गैर-सब्सिडीकृत)	₹/सिलेंडर	1113.25	813.25	813.25	0.0	0.0

[^]: 1-12 जुलाई, 2024 की अवधि के लिए।

नोट: केरोसीन के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों को दर्शाती हैं। केरोसीन के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में सब्सिडी वाले मूल्यों के औसत को दर्शाती हैं।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण कक्ष (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

बारिश²¹ जैसी मौसम संबंधी विसंगतियों के प्रभाव को दर्शाता है (चार्ट III.31)।

मुंबई और कोलकाता में कीमतों में बदलाव के कारण, जुलाई में अब तक (12 तारीख तक) पेट्रोल की खुदरा बिक्री कीमतों में वृद्धि हुई है, जबकि डीजल की कीमतों में मामूली गिरावट आई है।²² केरोसीन की कीमतों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि एलपीजी की कीमतों को अपरिवर्तित रखा गया है (सारणी III.2)।

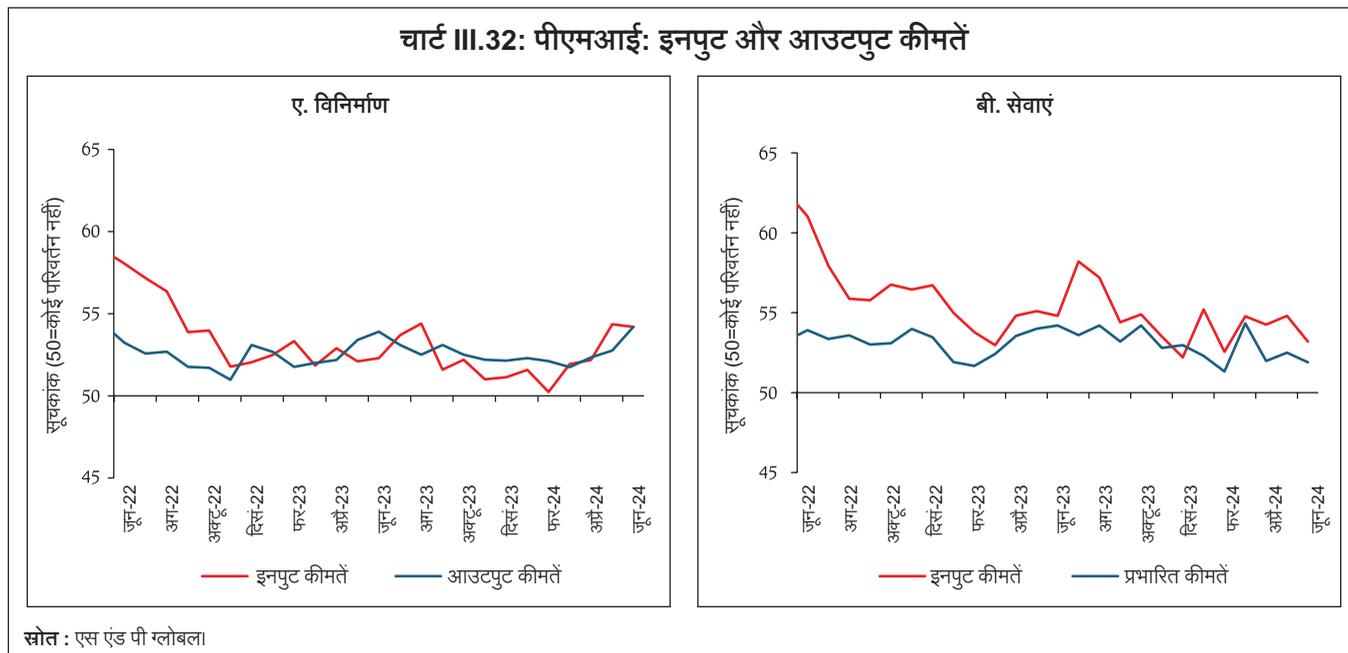
जून 2024 के पीएमआई ने विनिर्माण और सेवा फर्मों में इनपुट लागत में मध्यम वृद्धि का संकेत दिया। दूसरी ओर,

विनिर्माण क्षेत्र में बिक्री कीमतें बढ़ीं, जबकि सेवा क्षेत्र के लिए बिक्री कीमतें कम हो गईं (चार्ट III.32)।

IV. वित्तीय स्थितियाँ

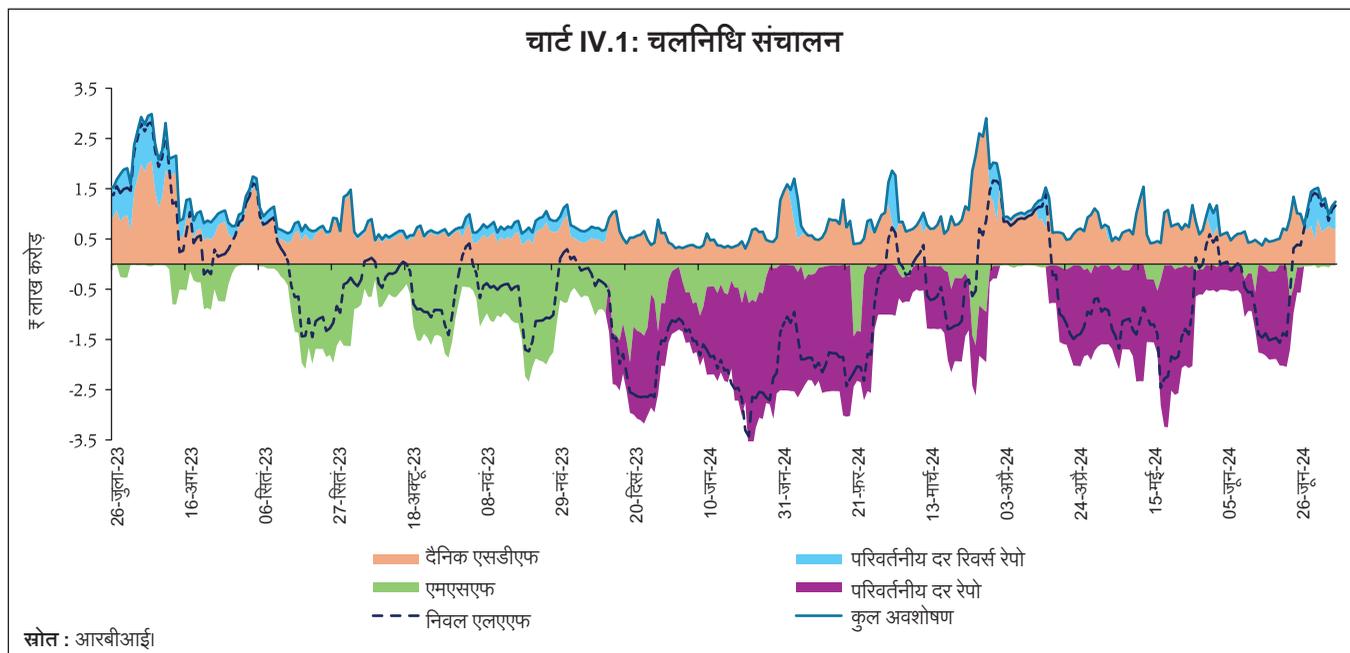
जून 2024 की शुरुआत में अधिशेष में रहने के बाद, सुस्त सरकारी खर्च के बीच अग्रिम कर भुगतान और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित बहिर्वाह के कारण इस महीने की दूसरी छमाही में प्रणालीगत चलनिधि घाटे में बदल गई। महीने के अंत में, सरकारी नकदी शेष में सामान्य गिरावट के साथ यह 28 जून, 2024 से फिर से अधिशेष में बदल गया। इन परिवर्तनों को दर्शाते हुए, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत

चार्ट III.32: पीएमआई: इनपुट और आउटपुट कीमतें



²¹ <https://www.thehindu.com/incoming/unseasonal-rain-in-maharashtra-leads-to-spike-in-agrarian-distress/article68190468.ece>

²² राज्य सरकारों द्वारा करों में परिवर्तन के कारण।



दैनिक नवल अंतर्वेशन 16 जून - 10 जुलाई, 2024 के दौरान औसतन ₹0.12 लाख करोड़ था, जबकि 16 मई - 15 जून, 2024 के दौरान यह ₹0.73 लाख करोड़ था (चार्ट IV.1)। रिजर्व बैंक ने 16-28 जून, 2024 के दौरान 3 से 6 दिनों की परिपक्वता के चार फाइन-ट्यूनिंग परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) संचालन के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि डाली, जिससे प्रणाली की चलनिधि बढ़ाने के लिए संचयी रूप से ₹2.75 लाख करोड़ की राशि प्राप्त हुई। जैसा कि इन परिचालनों के लिए उच्च बोली-कवर अनुपात में परिलक्षित होता है, निधि की मांग अत्यधिक थी। रिजर्व बैंक ने अपने मुख्य परिचालनों के बजाय, 28 जून को 3-दिवसीय वीआरआर नीलामी आयोजित की क्योंकि उसे तरलता की स्थिति में बदलाव और उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद थी। जून के अंत और जुलाई (10 जुलाई तक) में चलनिधि की स्थिति अधिशेष में बदल गई। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने जुलाई में रातोंरात 4 दिनों की परिपक्वता की आठ परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित की, जिससे प्रणाली से संचयी रूप से ₹2.17 लाख करोड़ अवशोषित हुए।

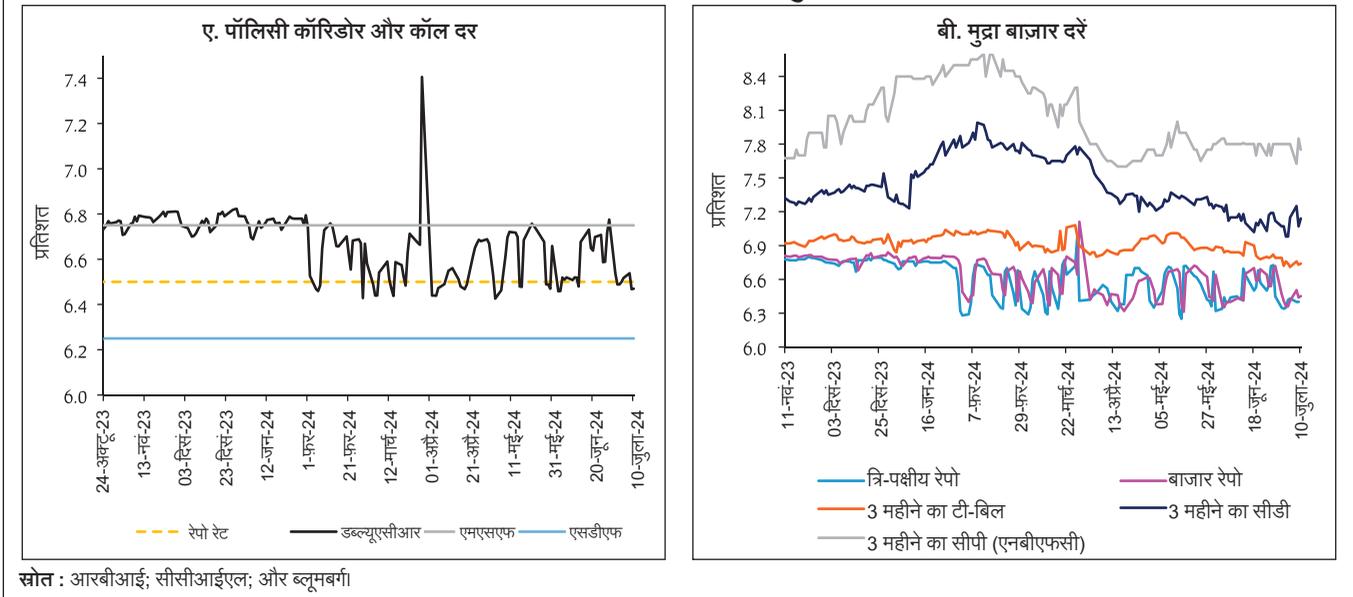
16 जून से 10 जुलाई, 2024 के दौरान सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत उधारी बढ़कर ₹12,440 करोड़ दैनिक औसत हो गई, जो 16 मई से 15 जून, 2024 के दौरान ₹10,910 करोड़ थी। 16 जून से 10 जुलाई, 2024 के दौरान

औसत कुल अवशोषण ₹0.88 लाख करोड़ था। स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत निधि का विनियोजन 16 मई से 15 जून, 2024 के दौरान 94 प्रतिशत की तुलना में 76 प्रतिशत था। शेष राशि फाइन ट्यूनिंग - वीआरआर संचालन के माध्यम से जुटाई गई थी।

मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य - भारत औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) मोटे तौर पर एलएएफ कॉरिडोर के बीच 16 जून से 10 जुलाई, 2024 के दौरान औसतन 6.59 प्रतिशत रहा, जबकि 16 मई - 15 जून 2024 के दौरान यह 6.57 प्रतिशत था (चार्ट IV.2ए)। संपार्श्विक खंड में त्रिपक्षीय और बाजार रेपो दरें डब्ल्यूएसीआर के साथ मिलकर आगे बढ़ीं। औसत आधार पर, त्रिपक्षीय रेपो दर पॉलिसी रेपो दर के समान थी और बाजार रेपो दर 16 जून से 10 जुलाई, 2024 के दौरान पॉलिसी रेपो दर से 4 बीपीएस ऊपर कारोबार कर रही थी (चार्ट IV.2बी)।

सावधि मुद्रा बाजार खंड में, 3 महीने के खजाना बिल (टी-बिल) पर यील्ड और जमा प्रमाणपत्र (सीडी) पर दरें कम हुईं, जबकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए वाणिज्यिक पत्र (सीपी) पर 16 जून से 10 जुलाई, 2024 के दौरान यह स्थिर रही। जून 2024 में आपूर्ति में कमी के कारण, 3 महीने के टी-बिल पर यील्ड कम हो गई। मुद्रा बाजार में औसत जोखिम प्रीमियम (3 महीने का सीपी से 91 दिन का टी-बिल

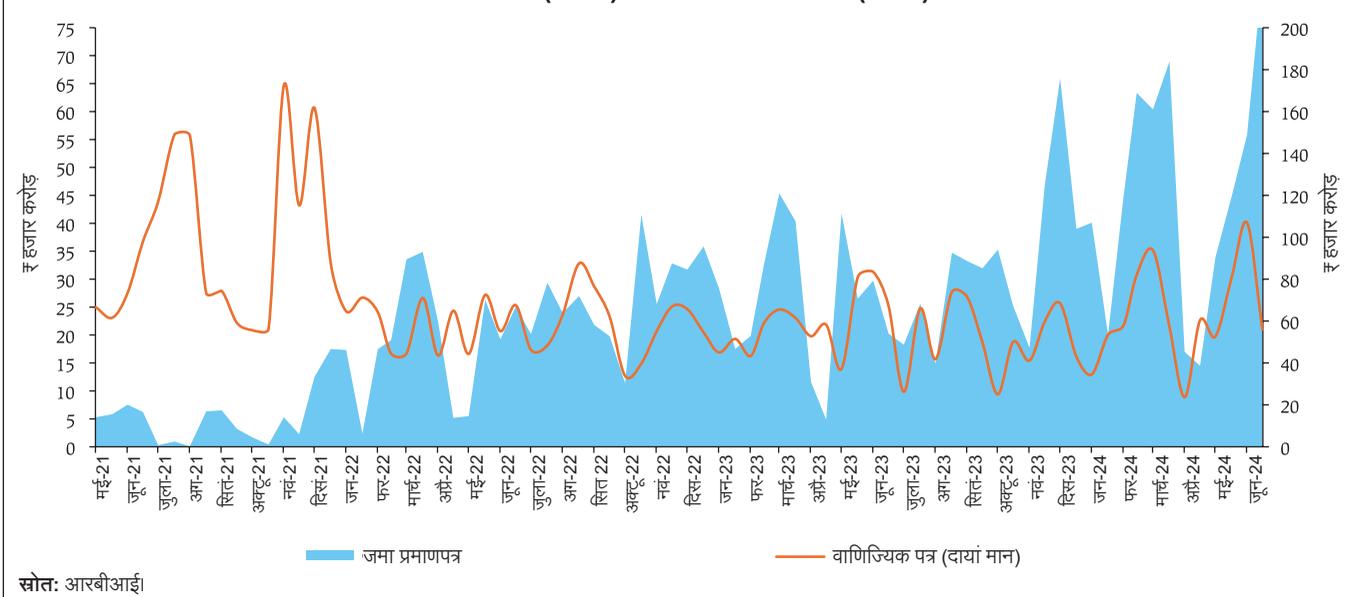
चार्ट IV.2: पॉलिसी कॉरिडोर और मुद्रा बाजार दरें

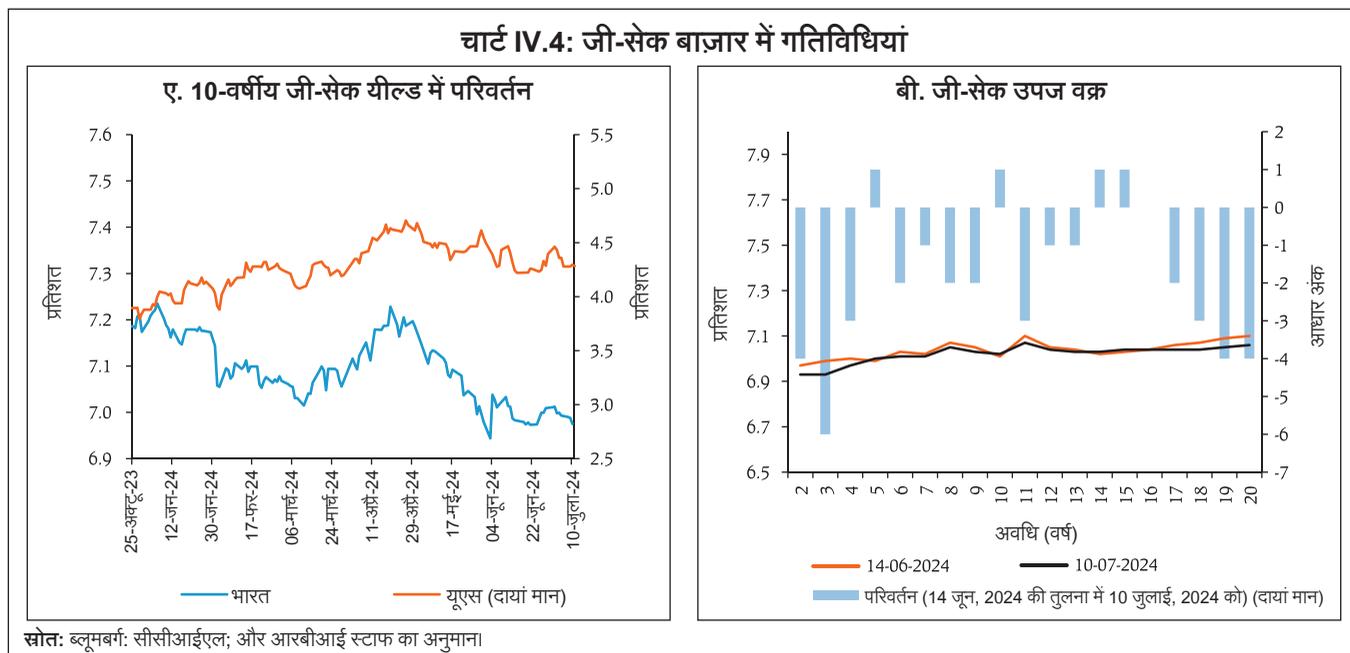


घटाकर) 16 मई - 15 जून, 2024 के दौरान के 92 बीपीएस से बढ़कर, 16 जून - 10 जुलाई, 2024 के दौरान 99 बीपीएस हो गया। इसके अलावा, सावधि स्प्रेड (10 साल की जी-सेक यील्ड से 91 दिन की टी-बिल दर घटाकर) 16 मई - 15 जून, 2024 के दौरान के 14 बीपीएस से 16 जून -10 जुलाई, 2024 के दौरान 20 बीपीएस तक बढ़ गई।

अप्रैल में सुस्ती के बाद, मई-जून में प्राथमिक बाज़ार में, सीडी जारीकरण से धन जुटाने में गति आई। बैंकों ने 2024-25 (28 जून तक) के दौरान ₹2.65 लाख करोड़ की सीडी जारी की, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में जारी ₹1.45 लाख करोड़ से अधिक है (चार्ट IV.3)। जून में अल्पकालिक दरों में गिरावट ने बैंकों को निधीयन अंतराल को पूरा करने हेतु सीडी जारी

चार्ट IV.3: जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) - पाक्षिक निर्गम





करने के लिए प्रेरित किया। 2024-25 (30 जून तक) के दौरान ₹3.8 लाख करोड़ के सीपी का निर्गम पिछले वर्ष की इसी अवधि में संबंधित खंड की गतिविधि के समान था।

16 जून से 10 जुलाई, 2024 के दौरान 10-वर्षीय भारतीय बेंचमार्क (7.10 जीएस 2034) सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) पर यील्ड 6.97-7.01 प्रतिशत के दायरे में रहा (चार्ट IV.4ए)। संपूर्ण अवधि संरचना में जी-सेक यील्ड मोटे तौर पर स्थिर रही (चार्ट IV.4बी)। 28 जून, 2024 को जेपी मॉर्गन के सरकारी बॉन्ड इंडेक्स-इमर्जिंग मार्केट्स (जीबीआई-ईएम) में भारत का समावेश हुआ है। 10 महीने की अवधि में, भारतीय बॉन्ड का भार हर महीने 1 प्रतिशत बढ़ जाएगा, जो अंततः मार्च 2025 तक 10 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

16 जून से 9 जुलाई, 2024 के दौरान परिपक्वता प्रोफाइल और रेटिंग स्पेक्ट्रम में कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड और जोखिम प्रीमियम मजबूत हो गया (सारणी IV.1)। 16 जून से 10 जुलाई के दौरान 3 साल के एए रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड पर यील्ड 7.65-7.75 फीसदी के दायरे में रही और 5 साल के एए रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड पर यील्ड 7.62-7.74 फीसदी के दायरे में रही²³

²³ स्रोत: ब्लूमबर्ग।

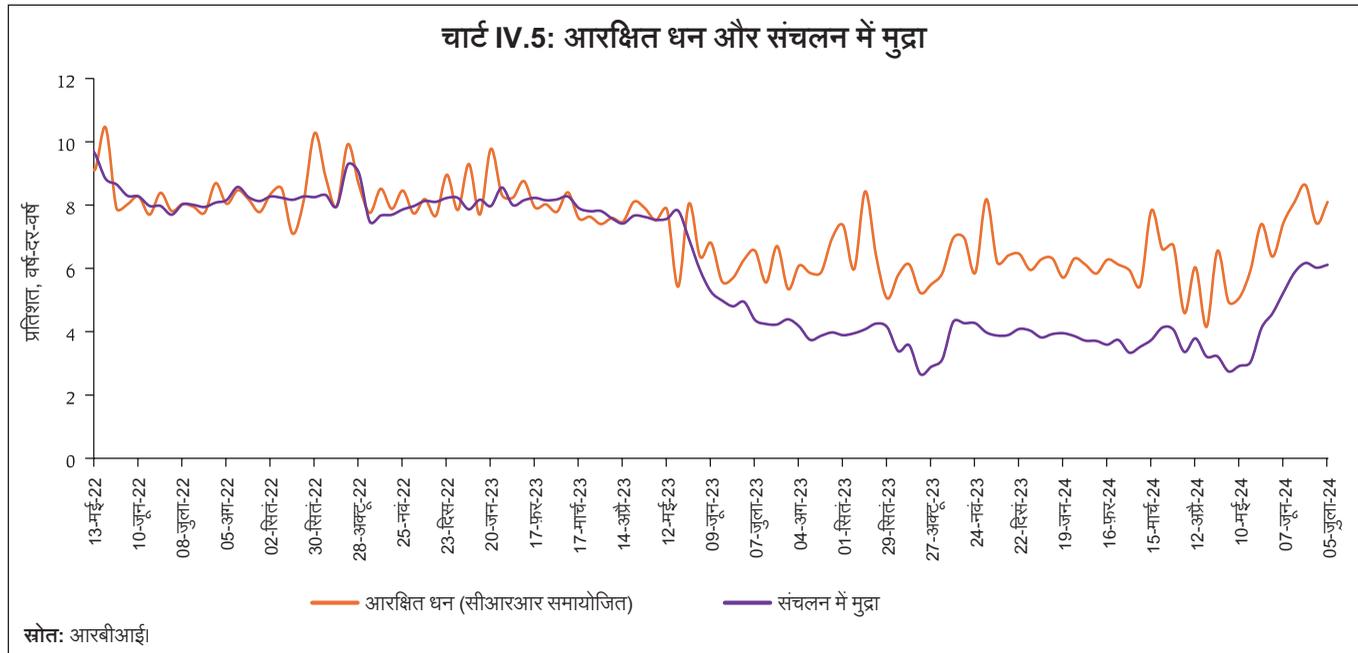
नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर, आरक्षित मुद्रा (आरएम) ने 5 जुलाई, 2024 को 8.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि (एक साल पहले 6.6 प्रतिशत) दर्ज की [चार्ट IV .5]। आरएम का सबसे बड़ा घटक, संचलन में मुद्रा (सीआईसी) 17 मई 2024 के 3.0 प्रतिशत से 5 जुलाई 2024 को 6.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ गई, यह ₹2000 के बैंकनोटों²⁴ को संचलन से वापिस

सारणी IV.1: वित्तीय बाजार - दरें और स्प्रेड

लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			स्प्रेड (आधार अंक)		
	16 मई, 2024-14 जून, 2024	16 जून, 2024-9 जुलाई, 2024	अंतर	16 मई, 2024-14 जून, 2024	16 जून, 2024-9 जुलाई, 2024	अंतर
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
कॉर्पोरेट बॉन्ड						
(i) एए (1 वर्ष)	7.84	7.85	1	71	79	8
(ii) एए (3-वर्ष)	7.90	8.08	18	74	100	26
(iii) एए (5-वर्ष)	7.83	7.85	2	66	71	5
(iv) एए (3-वर्षीय)	8.55	8.79	24	139	170	31
(v) बीबीबी- (3-वर्ष)	12.15	12.42	27	499	533	34

नोट: यील्ड और स्प्रेड की गणना संबंधित अवधि के औसत के रूप में की जाती है।
स्रोत: फिमडा।

²⁴ 19 मई, 2023 को घोषित।

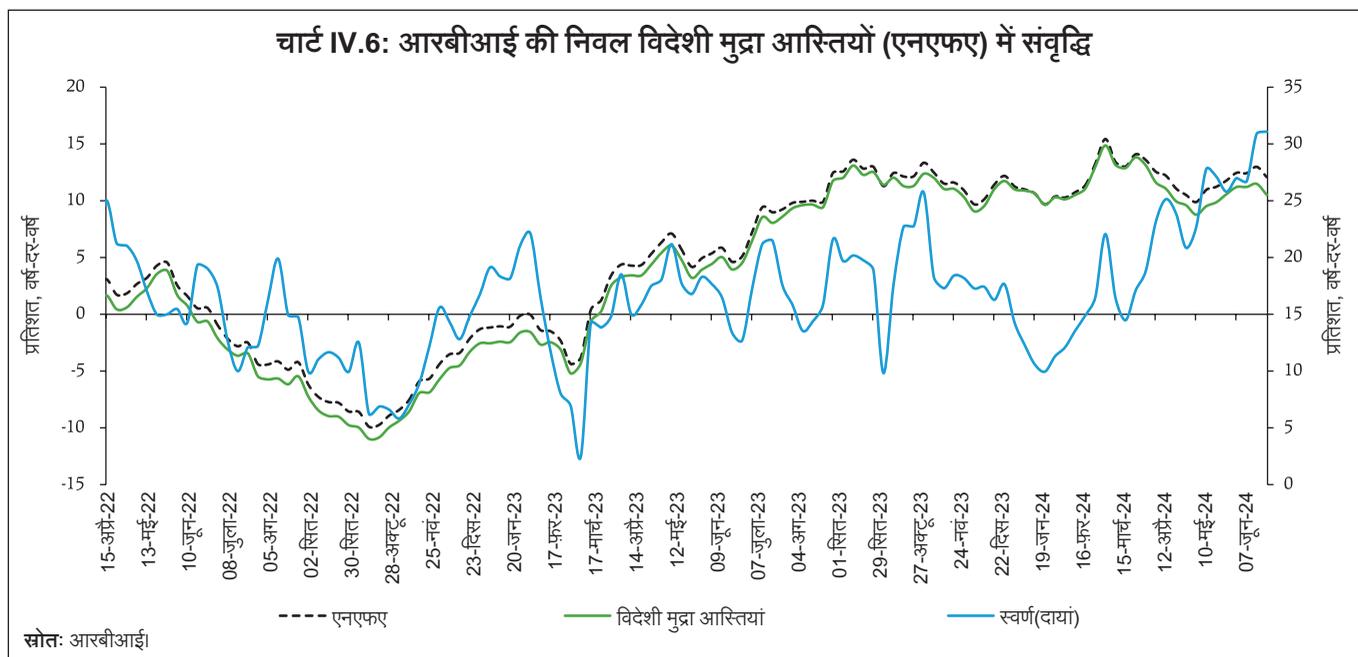


लेने के आधार प्रभाव के कारण हुआ जिससे 97.87 प्रतिशत बैंकनोट ज्यादातर जमा के रूप में बैंकिंग प्रणाली में वापस (28 जून, 2024 तक) आ गए हैं।

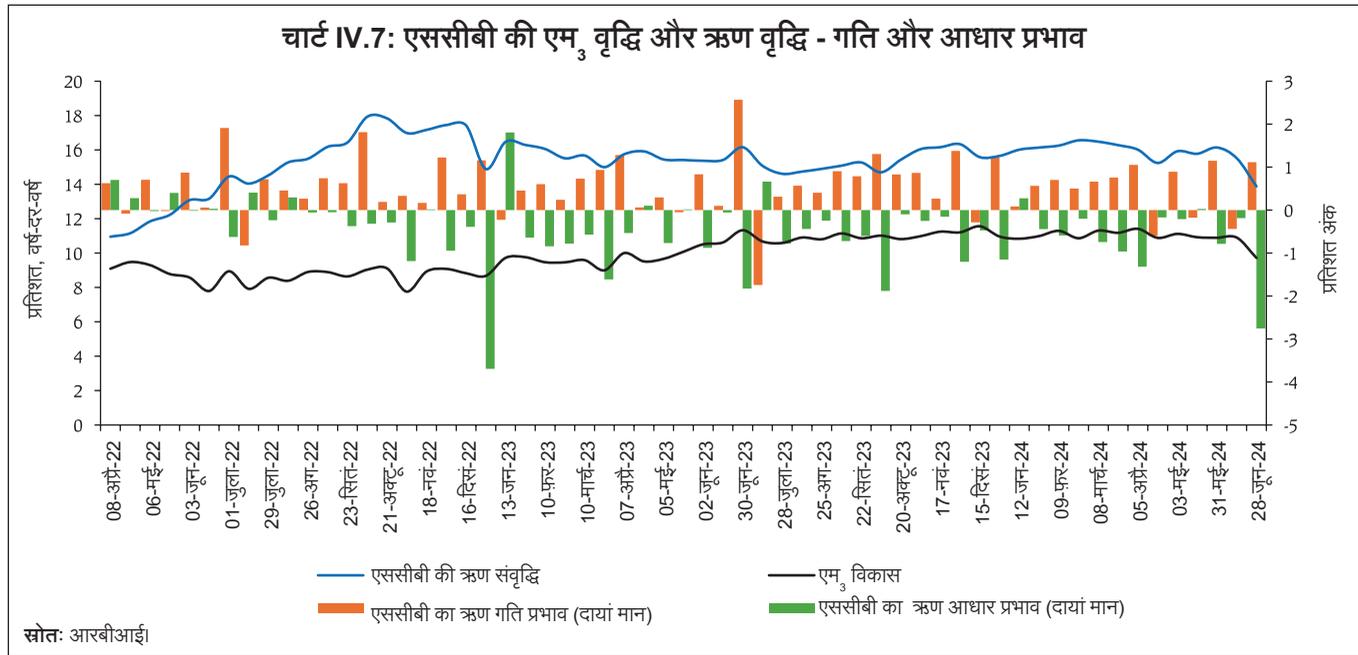
स्रोत पक्ष (आस्ति) को देखे तो, आरएम में रिज़र्व बैंक की निवल घरेलू आस्तियां (एनडीए) और निवल विदेशी आस्तियां (एनएफए) शामिल हैं। 5 जुलाई, 2024 को विदेशी मुद्रा आस्तियों

(एनएफए के 90 प्रतिशत से अधिक के लिए लेखांकन) में 10.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की गई। एनएफए के एक घटक स्वर्ण में 31.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मार्च 2022 से दर्ज की गई सबसे अधिक वृद्धि है (चार्ट IV.6)।

28 जून, 2024 को मुद्रा आपूर्ति (एम₃) में 9.7 प्रतिशत की (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि (एक वर्ष पहले 11.3 प्रतिशत) हुई²⁵ एम3



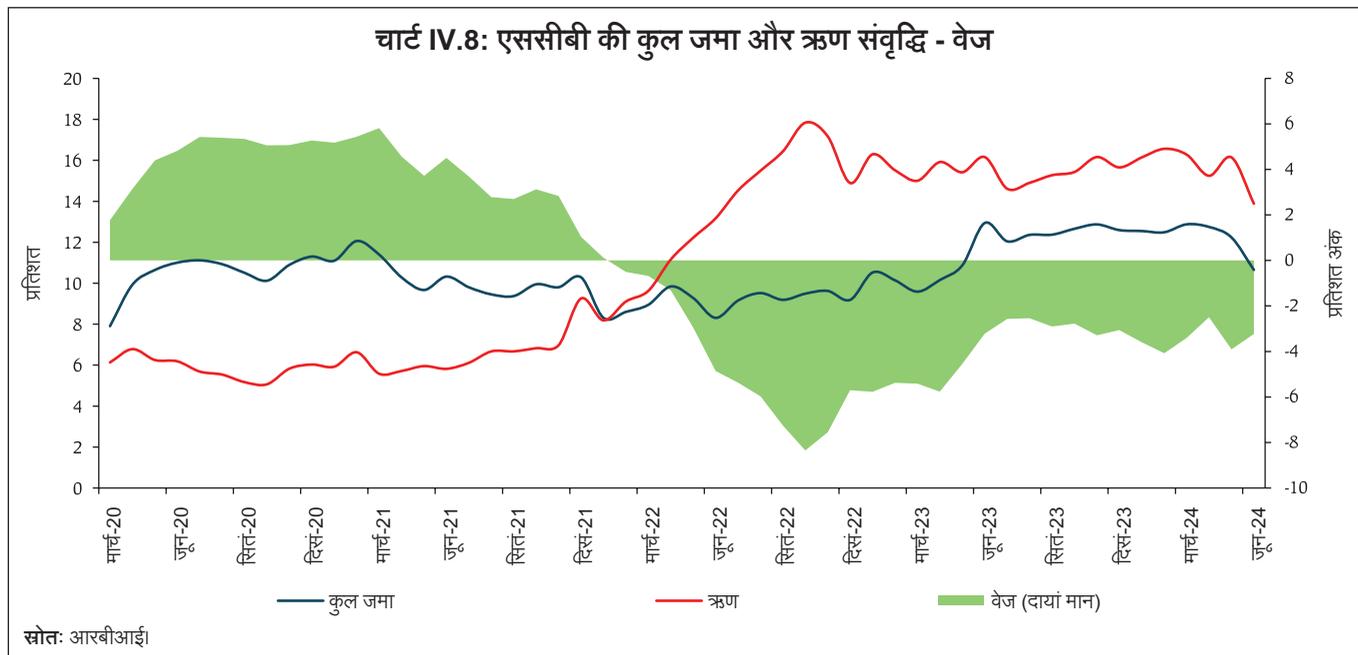
²⁵ किसी गैर-बैंक के बैंक में विलय के प्रभाव को छोड़कर (1 जुलाई, 2023 से प्रभावी)।



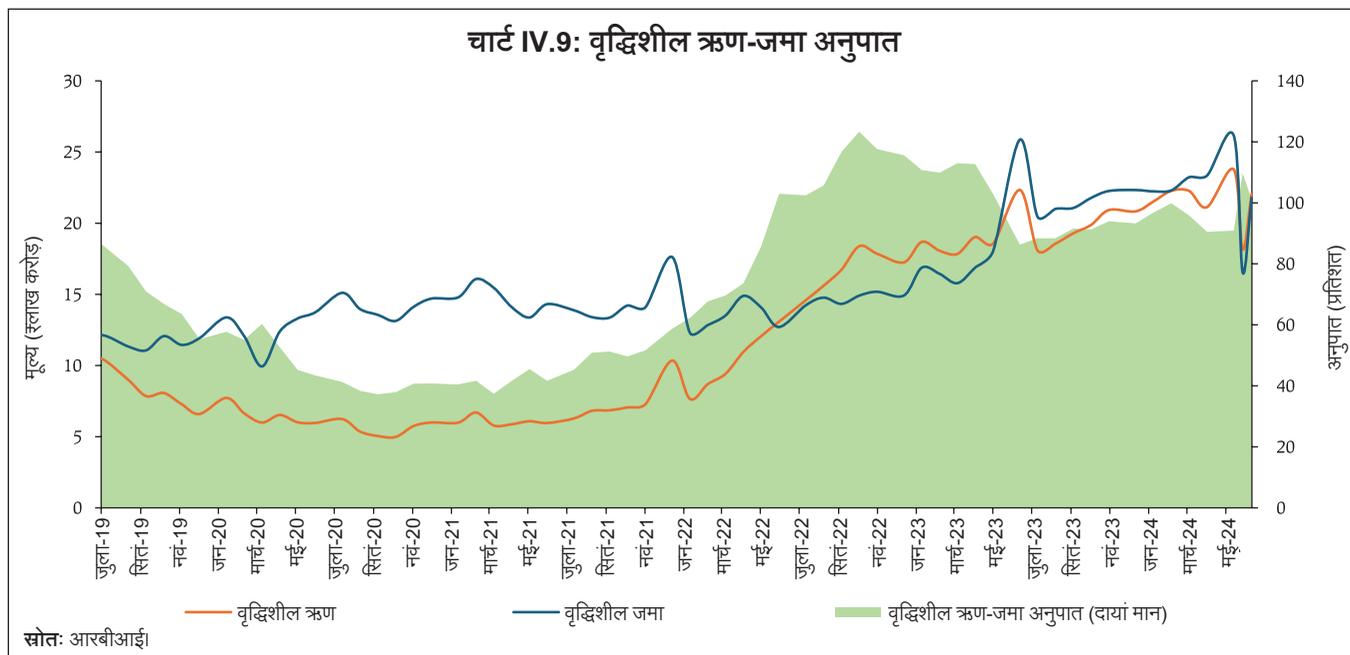
का सबसे बड़ा घटक - बैंकों के पास की कुल जमाराशि में 10.2 प्रतिशत से वृद्धि (एक साल पहले 12.4 प्रतिशत) हुई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि पिछले पखवाड़े में 15.5 प्रतिशत से घटकर 28 जून, 2024 को 13.9 प्रतिशत (एक साल पहले 16.2 प्रतिशत) हो गई [चार्ट IV.7]।

एससीबी की जमा वृद्धि (विलयन के प्रभाव को छोड़कर²⁶) जिसमें ₹2000 बैंक नोटों की वापसी के मद्देनजर वृद्धि दर्ज की गई, वह अप्रैल 2023 से दोहरे अंकों में बनी हुई है (चार्ट IV.8)।

28 जून, 2024 को प्रणालीगत स्तरीय वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात 101 प्रतिशत था (चार्ट IV.9)। सीआरआर और



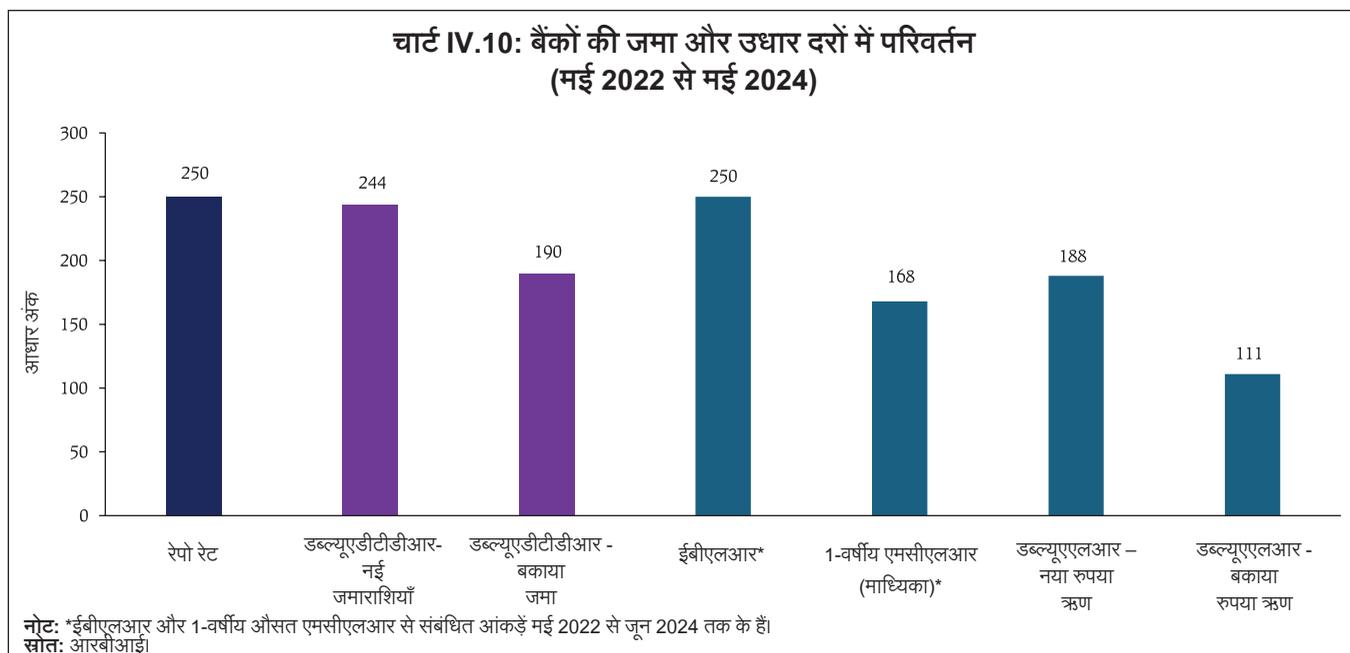
²⁶ 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक के साथ विलय।



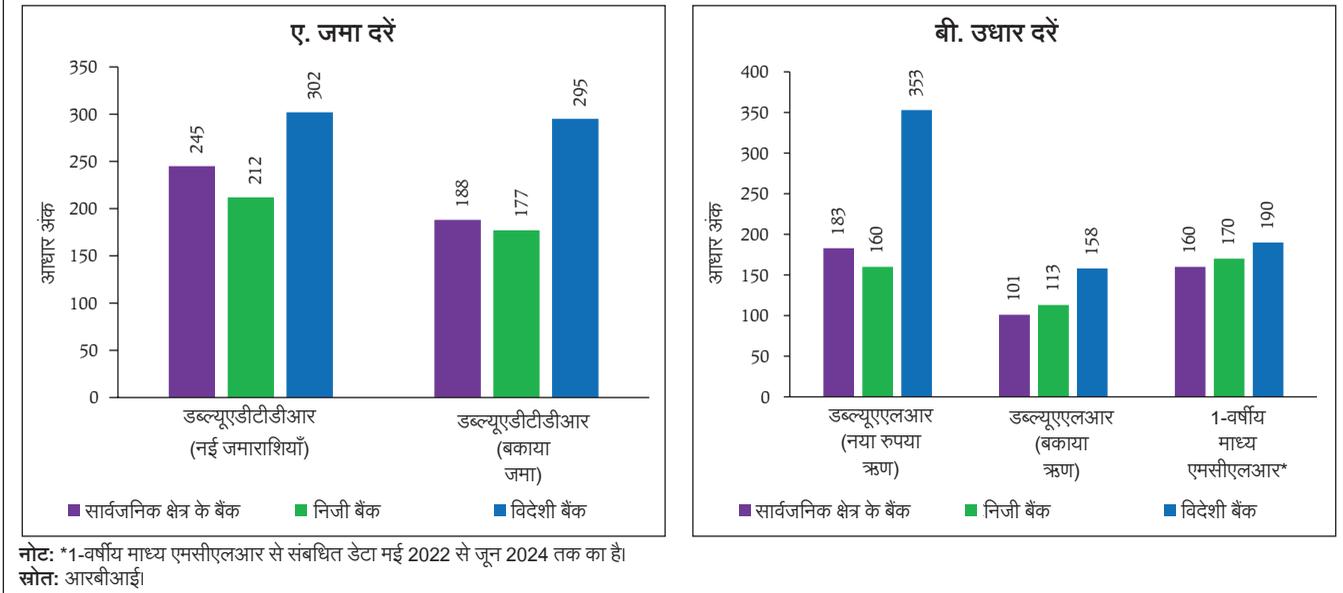
संवैधानिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की संवैधानिक आवश्यकताओं के साथ, 28 जून, 2024 तक लगभग 77 प्रतिशत जमा राशि ऋण विस्तार के लिए बैंकिंग प्रणाली में उपलब्ध थी। जमाराशि आधार को सीडी निर्गम से पूरक बनाया गया।

मई 2022 से नीति दर में 250 बीपीएस की बढ़ोतरी के जवाब में, एससीबी ने अपनी रेपो-लिंकड बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार

दरें (ईबीएलआर) बढ़ाते हुए संशोधित की हैं। मई 2022-जून 2024 के दौरान एससीबी की निधि-आधारित दर (एमसीएलआर) की 1-वर्षीय औसत सीमांत लागत बढ़कर 168 बीपीएस हो गई। नतीजतन, मई 2022 से मई 2024 के दौरान नये और बकाया रुपया ऋण पर भारित औसत उधार दरें (डब्ल्यूएलआर) क्रमशः 188 बीपीएस और 111 बीपीएस बढ़ गईं। जमाराशि के मामले में, उसी अवधि के दौरान नया और बकाया जमा पर भारित औसत



चार्ट IV.11: बैंक-समूहों में संचरण (मई 2022 से मई 2024)



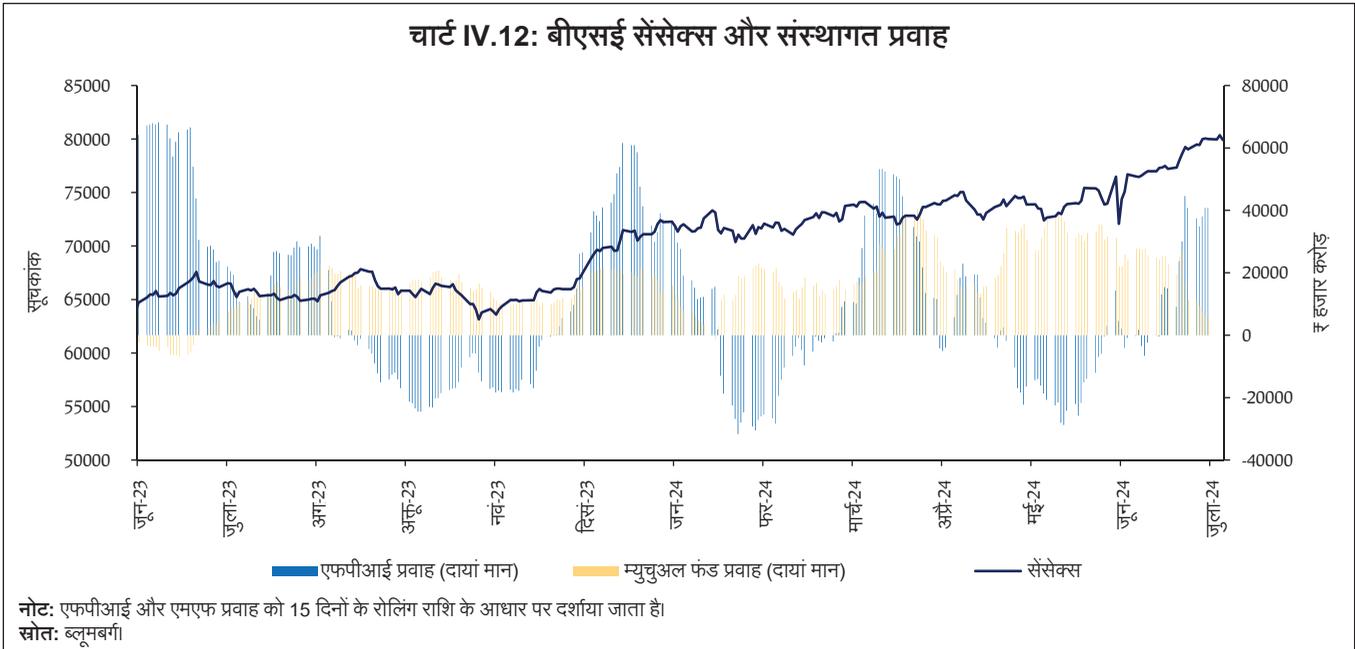
घरेलू सावधि जमा दरों (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में क्रमशः 244 बीपीएस और 190 बीपीएस की वृद्धि हुई (चार्ट IV.10)।

घरेलू बैंकों में, मई 2022 से मई 2024 की अवधि के दौरान बकाया ऋणों को छोड़कर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के मामले में जमा और उधार दरों में वृद्धि अधिक थी (चार्ट IV.11)। पीएसबी की उधार दरें निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) की तुलना में

कम रहीं जबकि उनकी जमा दरें अधिक थीं।

भारत सरकार ने 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर दरें अपरिवर्तित रखीं। सार्वजनिक भविष्य निधि और पांच-वर्षीय आवर्ती जमा को छोड़कर विभिन्न योजनाओं से संबन्धित दरें अब फॉर्मूला-आधारित दरों के अनुरूप हैं।

चार्ट IV.12: बीएसई सेंसेक्स और संस्थागत प्रवाह



अब तक, जून-जुलाई 2024 के दौरान भारतीय इक्विटी बाजार ने नई ऊंचाई हासिल की और बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स 9.1 प्रतिशत बढ़कर 16 जुलाई, 2024 को 80,717 पर बंद हुआ (चार्ट IV.12)। जून की शुरुआत में बढ़ी अस्थिरता के बाद, सूचकांकों में तेजी आई क्योंकि मई 2024 के लिए घरेलू और साथ ही अमेरिकी मुद्रास्फीति प्रिंट में उम्मीद से अधिक नरमी रहने से बाजार को राहत मिली। जून की दूसरी छमाही के दौरान, यूरोप में राजनीतिक अनिश्चितता के बीच कमजोर वैश्विक संकेतों के बावजूद, सूचकांकों में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के शेयरों में मजबूत गति और उच्च आवृत्ति वाले घरेलू पीएमआई डेटा को प्रोत्साहित करने के बीच ऊपर की ओर रुझान में तेजी जारी रही। इसे भारत के चालू खाते के 2023-24 की चौथी तिमाही में अधिशेष में बदलने से और भी समर्थन मिला। जुलाई में, बीएसई सेंसेक्स ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के शेयरों में बढ़त और

यूएस फेड चेयरमैन की नरम टिप्पणी के समर्थन से 80,000 का नया मील का पत्थर पार कर लिया। जून की शुरुआत में तेजी से बढ़ने के बाद, भारत VIX में दूसरी छमाही के दौरान गिरावट आई और जुलाई की पहली छमाही में यह स्थिर होकर 16 जुलाई, 2024 को 14.2 पर आ गया। जून 2024 के बाद से, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के साथ-साथ म्यूचुअल फंड दोनों ने भी भारतीय इक्विटी बाजार में क्रमशः ₹48,342 और ₹34,598 करोड़ की निवल खरीदारी (12 जुलाई, 2024 तक) की।

मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों और एक उत्साही इक्विटी बाजार की पृष्ठभूमि के सामने कई लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) पर्याप्त लिस्टिंग दिवस रिटर्न के साथ खुले हैं, जिससे निवेशकों की रुचि बढ़ गई है, जैसा कि महत्वपूर्ण अत्यभिदान (बॉक्स I) में

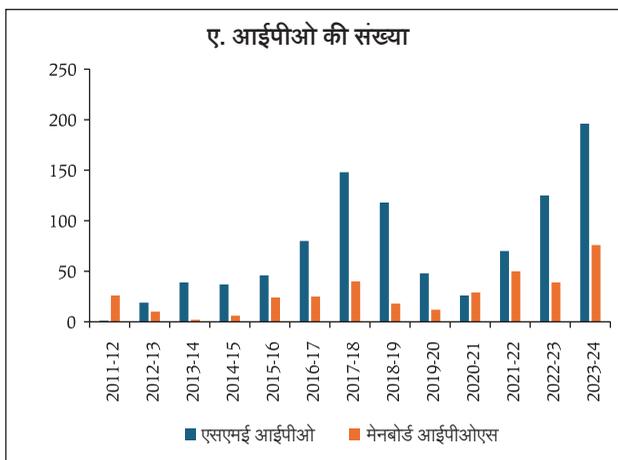
बॉक्स I: अवमूल्यन : मेनबोर्ड आईपीओ बनाम एसएमई आईपीओ

हाल के वर्षों में एसएमई द्वारा सार्वजनिक इक्विटी जारी करने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (चार्ट बी1.ए और बी1.बी)। परंपरागत रूप से, एसएमई अपनी वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों, एनबीएफसी और ऋण लिखतों पर निर्भर रहे हैं। बीएसई और एनएसई दोनों द्वारा एसएमई एक्सचेंजों²⁷

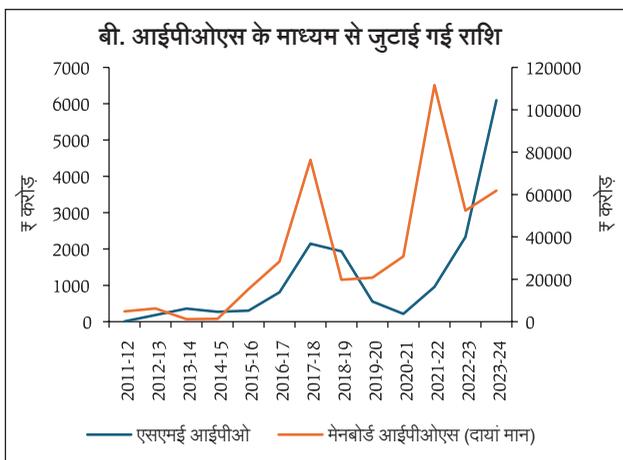
के विकास में एसएमई को धन जुटाने के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया है।

यहाँ पर निवेशकों की रुचि बढ़ी है। औसत अत्यभिदान दर में तेज वृद्धि हुई है जो लिस्टिंग के दिन उच्च रिटर्न को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है और जिसके परिणामस्वरूप

चार्ट बी1: प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ)



स्रोत: सेबी।



(जारी)

²⁷ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म मार्च 2012 में स्थापित किया गया था, जबकि एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म, जिसे इमर्ज के नाम से जाना जाता है, सितंबर 2012 में स्थापित किया गया था।

सारणी बी1: आईपीओ की औसत अत्यभिदान दरें

वर्ष	मेनबोर्ड आईपीओ	एसएमई आईपीओ
2018-19	2.69	1.33
2019-20	20.31	1.18
2020-21	30.12	1.42
2021-22	13.44	2.83
2022-23	3.44	11.49
2023-24	22.60	62.28

नोट: (1) डेटा यह दर्शाता है कि आईपीओ को इश्यू के आकार के सापेक्ष कितनी बार ओवरसब्सक्राइब किया गया।

(2) आईपीओ जारी होने की तारीख के आधार पर डेटा संकलित किया गया।

स्रोत: प्राइम डेटाबेस; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

अधिक अवमूल्यन²⁸ (सारणी बी1) होता है। अनुभवजन्य विश्लेषण से पता चलता है कि अत्यभिदान दर का मेनबोर्ड आईपीओ के अवमूल्यन²⁹ पर सकारात्मक और अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

जनवरी 2012 से मार्च 2024 तक के डेटा का उपयोग करके बीएसई एसएमई एक्सचेंज और एनएसई इमर्ज पर सूचीबद्ध एसएमई आईपीओ के अवमूल्यन की तुलना मेनबोर्ड आईपीओ से की जाती है (चार्ट बी2)। अवमूल्यन माप δ (डेल्टा) को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

$$\delta = r_i - r^*$$

जहां r_i लिस्टिंग दिवस रिटर्न है जिसकी गणना प्रस्ताव मूल्य के ऊपर लिस्टिंग दिवस के समापन मूल्य के रूप में की जाती है।

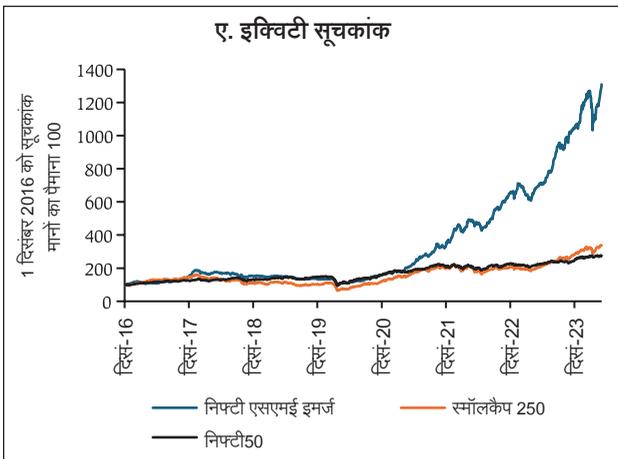
r^* लिस्टिंग के दिन का बेंचमार्क रिटर्न³⁰ है।

अधिकांश वर्षों में, मेनबोर्ड आईपीओ का औसत अवमूल्यन एसएमई आईपीओ की तुलना में अधिक रहा (गांगुली, 2022)। हालाँकि, हाल में एसएमई आईपीओ का औसत अवमूल्यन मेनबोर्ड आईपीओ की तुलना में काफी अधिक रहा है।

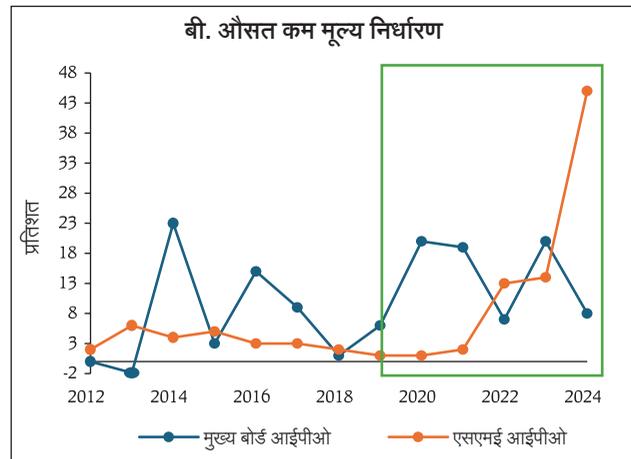
वैश्विक आईपीओ बाजारों में आईपीओ अवमूल्यन आम बात है (महमूद एट अल., 2021)। इसके लिए असममित जानकारी, स्वामित्व और नियंत्रण से संबंधित कारकों से लेकर कई तरह के कारकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है (लुंगक्विस्ट, 2007)। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर आईपीओ अवमूल्यन आईपीओ विशिष्ट चर (जैसे आईपीओ आकार और प्रीमियम); बाजार चर (जैसे पिछड़ा हुआ बाजार रिटर्न और अस्थिरता); और स्थायी विशेषताओं (जैसे आयु, आकार, उद्योग, चलनिधि और लाभप्रदता संकेतक) पर निर्भर करता है (घोष, 2005; भट्टाचार्य, 2017)।

बेंचमार्क से अधिक सूचीबद्ध एसएमई आईपीओ के अपेक्षित अतिरिक्त रिटर्न से संकेत मिलता है कि औसतन, एसएमई

चार्ट बी2: औसत कम मूल्य निर्धारण : मेनबोर्ड आईपीओ बनाम एसएमई आईपीओ



स्रोत: एनएसई, प्राइम डेटाबेस और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।



(जारी)

²⁸ बाजार मूल्य (पहले दिन समापन मूल्य) और प्रस्ताव मूल्य के बीच अंतर के रूप में अवमूल्यन मापा जाता है।

²⁹ 'भारत में लिस्टिंग रिटर्न की घटना: कुछ अन्वेषण' (बॉक्स-आइटम, आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21)।

³⁰ बीएसई सेंसेक्स को मेनबोर्ड आईपीओ के लिए बेंचमार्क के रूप में लिया जाता है और बीएसई स्मॉल कैप को एसएमई आईपीओ के लिए बेंचमार्क के रूप में लिया जाता है।

सारणी बी 2: एसएमई-आईपीओ स्टॉक का बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन

	अपेक्षित अतिरिक्त प्रतिफल (प्रतिशत में)	
	स्मॉलकैप इंडेक्स	सेसेक्स
6-महीने	32.0	42.5
12-महीने	65.2	81.9

नोट : (1) 6 महीने और 12 महीने की अवधि के लिए अपेक्षित रिटर्न की गणना सकारात्मक/नकारात्मक रिटर्न वाले शेयरों के अनुपात को उनके औसत सकारात्मक/नकारात्मक रिटर्न से गुणा करके की जाती है।
अपेक्षित रिटर्न = $P_{\text{लाभ}} * \text{औसत लाभ} + (1 - P_{\text{लाभ}}) * \text{औसत हानि}$
जहाँ P की गणना (सकारात्मक अतिरिक्त रिटर्न वाले स्टॉक) / (विश्लेषण के तहत कुल स्टॉक) के रूप में की जाती है।
(2) विश्लेषण में मई 2021 और नवंबर 2023 के बीच सूचीबद्ध 311 एसएमई आईपीओ शामिल हैं।
(3) उल्लेखनीय बात यह है कि 42 और 36 प्रतिशत एसएमई आईपीओ ने सूचीबद्ध होने के क्रमशः छह महीने और एक वर्ष बाद नकारात्मक पूर्ण रिटर्न दिया है।

स्रोत: बीएसई, प्राइम डेटाबेस; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

शेयरों ने व्यापक बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया है (सारणी बी 2)। एसएमई आईपीओ खंड में उत्साह से मूल्य में हेरफेर³¹ और मजबूत प्राथमिक बाजार के दुरुपयोग के रास्ते खुलते हैं जैसे आईपीओ की आय को उसके इच्छित अंतिम उपयोग से दूर ले जाना³²। सेबी की हालिया कार्रवाइयों से इन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

परिलक्षित होता है। एसएमई आईपीओ प्लेटफॉर्म के लिए विशेष प्री-ओपन सत्र के दौरान एक्सचेंजों में शुरुआती मूल्य खोज/संतुलन मूल्य को मानकीकृत करने की दृष्टि से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने निर्गम मूल्य पर एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग के लिए (4 जुलाई, 2024 से प्रभावी) 90 प्रतिशत तक की समग्र सीमा लगाने का निर्णय लिया।³³

अप्रैल-मई 2024 के दौरान सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 15.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो एक साल पहले दर्ज किए गए 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था (चार्ट IV.13ए)। सकल एफडीआई प्रवाह का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा विनिर्माण, वित्तीय सेवाओं, कंप्यूटर सेवाओं, व्यावसायिक सेवाओं और बिजली और अन्य ऊर्जा

संदर्भ:

Mayank Gupta, Aayushi Bhattacharya, Satyam Kumar, Dilpreet Sharma and Amit Pawar (2024). Exploring Under-Pricing: A Comparative Study of Indian SME IPOs and Mainboard IPOs, Mimeo.

Bhattacharya, A. (2017). Innovations in New Venture Financing: Evidence from Indian SME IPOs. *Global Finance Journal*, 34, 72-88.

Ganguly, S. (2022). *SME Exchanges in India: Empirical Analysis of Firm Attributes and IPO Characteristics* (Working Paper No. 11). Reserve Bank of India.

Ghosh, S. (2005). Underpricing of Initial Public Offerings: The Indian Experience. *Emerging Markets Finance and Trade*, 41(6), 45-57.

Ljungqvist, A. (2007). IPO Underpricing. In B. Espen Eckbo (Eds.). *Handbooks in Finance: Handbook of Empirical Corporate Finance* (pp. 375-422). Elsevier.

Mehmood, W., Rashid, R. M., & Tajuddin, A. H. (2021). A Review of IPO Underpricing: Evidences from Developed, Developing and Emerging Markets. *Journal of Contemporary Issues and Thought*, 11, 1-19.

RBI (2021). *Annual Report 2020-21*. Reserve Bank of India.

जैसे क्षेत्रों में केंद्रित था। प्रमुख स्रोत देशों में मॉरीशस, सिंगापुर, नीदरलैंड, अमेरिका और साइप्रस शामिल हैं, जो 80 प्रतिशत से अधिक प्रवाह के लिए जिम्मेदार हैं। सकल प्रवाह में वृद्धि और प्रत्यावर्तन में नरमी के कारण, अप्रैल-मई 2024 में निवल एफडीआई 7.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले के 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना से भी अधिक है।

अस्थिर वित्तीय स्थितियों, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और गहराते भू-आर्थिक विखंडन के बीच, 2023 में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक एफडीआई प्रवाह में 2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट दर्ज की गई (चार्ट IV.13बी)³⁴ कुछ यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को छोड़कर सभी भौगोलिक क्षेत्रों में नरमी आई। उन्हें छोड़कर, वैश्विक प्रवाह में संकुचन 10 प्रतिशत से भी अधिक तीव्र था।

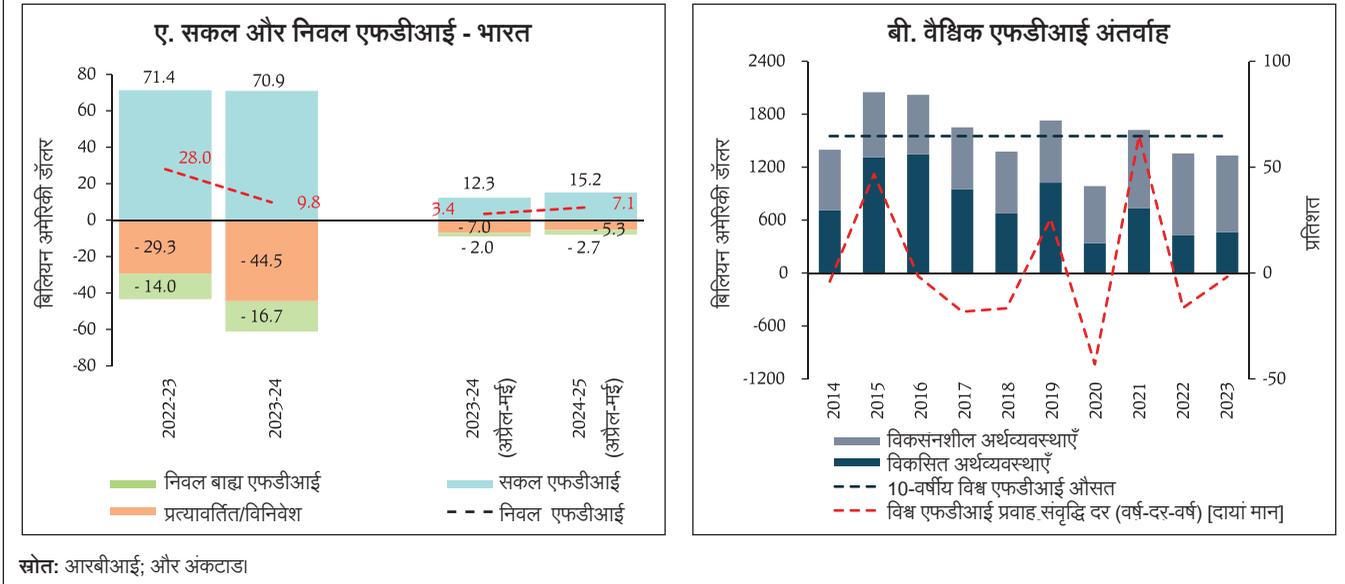
³¹ https://www.sebi.gov.in/enforcement/orders/feb-2024/interim-order-in-the-matter-of-v-marc-india-limited_81831.html

³² https://www.sebi.gov.in/enforcement/orders/may-2024/interim-order-in-the-matter-of-varanium-cloud-limited_83309.html

³³ <https://nsearchives.nseindia.com/content/circulars/SME62757.zip>

³⁴ विश्व निवेश रिपोर्ट 2024, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड)।

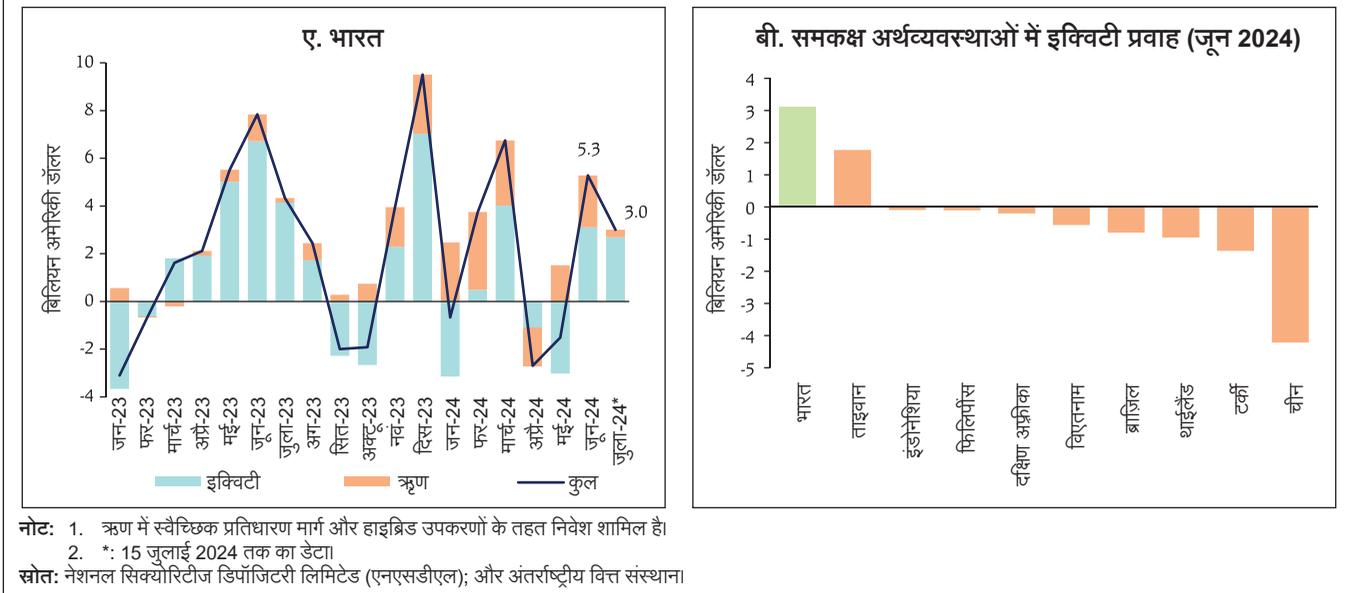
चार्ट IV.13: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह



विनिर्माण परियोजना घोषणाओं में वृद्धि के कारण वैश्विक ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जिससे मंदी की एक दशक पुरानी प्रवृत्ति टूट गई। 2023 के दौरान एफडीआई अंतर्वाह में नरमी के बावजूद, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों दोनों में भारत शीर्ष 5 गंतव्य देशों में बना रहा।

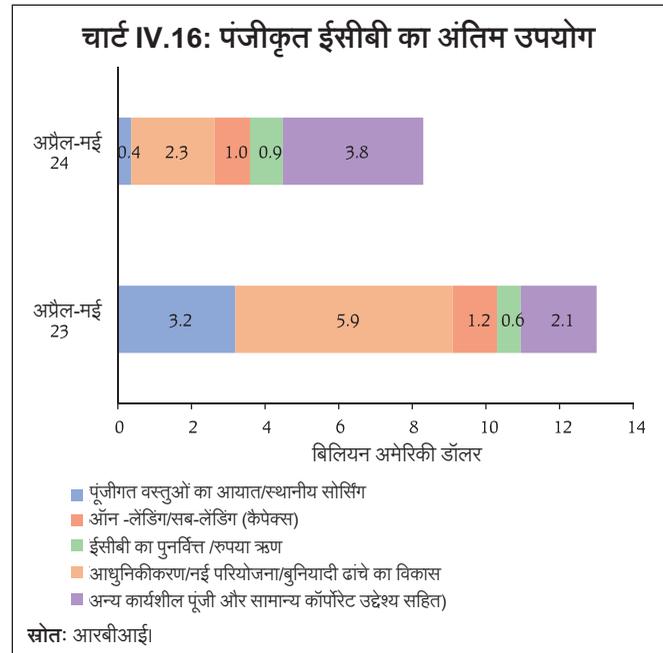
लगातार दो महीनों के निवल बहिर्वाह के बाद, जून 2024 में एफपीआई 5.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल अंतर्वाह के साथ भारतीय वित्तीय बाजारों में निवल खरीदार बन गए (चार्ट IV.14ए)। बाजार में अस्थिरता कम होने से इक्विटी ने दो महीने की बिक्री प्रक्षेपवक्र को उलट दिया, जिसमें 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल एफपीआई अंतर्वाह हुआ। इसके विपरीत,

चार्ट IV.14: निवल पोर्टफोलियो निवेश

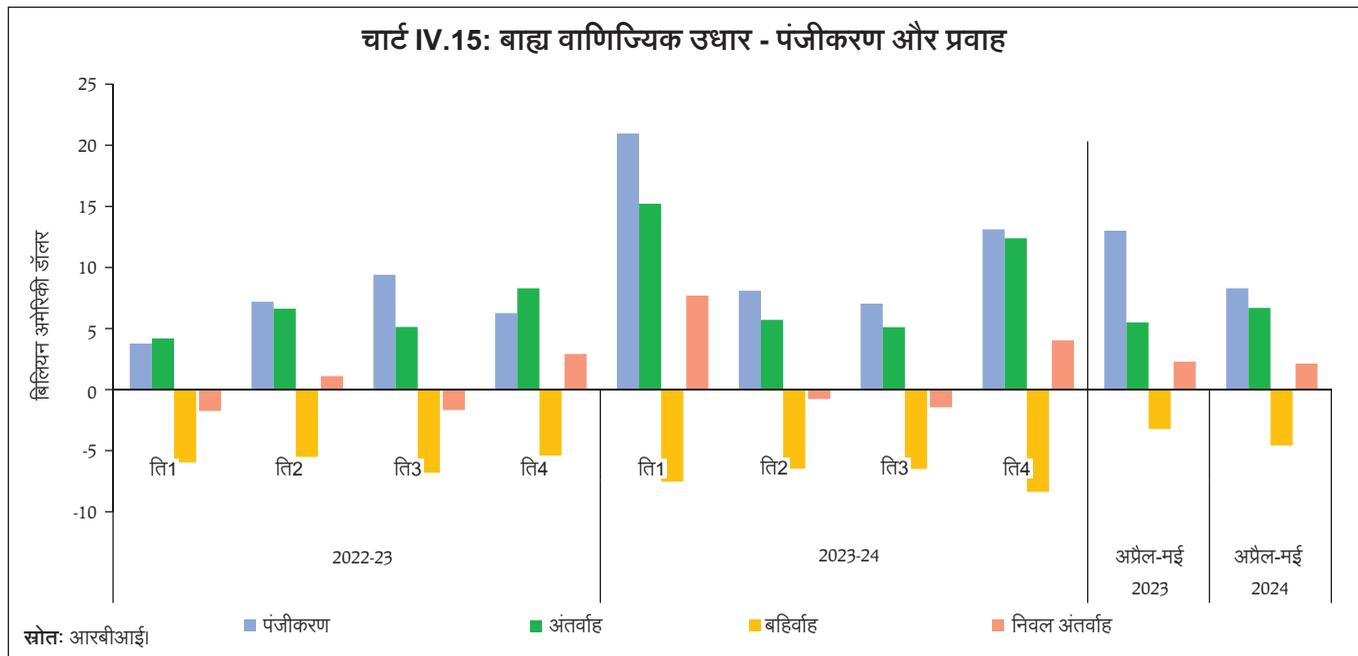


अधिकांश समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं ने जून में इक्विटी खंड में निवल बहिर्वाह दर्ज किया (चार्ट IV.14बी)। वित्तीय सेवाओं, दूरसंचार और उपभोक्ता सेवा क्षेत्रों ने इस महीने के दौरान सबसे अधिक एफपीआई इक्विटी अंतर्वाह को आकर्षित किया। ऋण खंड में एफपीआई अंतर्वाह जारी है और 28 जून, 2024 से जेपी मॉर्गन के जीबीआई-ईएम में भारतीय सरकारी बांडों को शामिल करने की घोषणा के बाद से 18-21 महीनों के भीतर लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर³⁵ तक अंतर्वाह में आने का अनुमान है। एफपीआई ऋण अंतर्वाह की संभावनाएं आशावादी प्रतीत होती हैं क्योंकि भारत अन्य वैश्विक सूचकांकों में शामिल होने जा रहा है³⁶ जुलाई 2024 में (15 जुलाई तक) निवल एफपीआई अंतर्वाह 3.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

अप्रैल-मई 2024 में अनिवासी जमा में 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया, जबकि एक साल पहले यह 0.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह सभी तीन खातों अर्थात् अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता [एनआर(ई)आरए], अनिवासी साधारण (एनआरओ) और विदेशी मुद्रा अनिवासी [एफसीएनआर(बी)] खातों में उच्चतर अंतर्वाह के कारण हुआ।

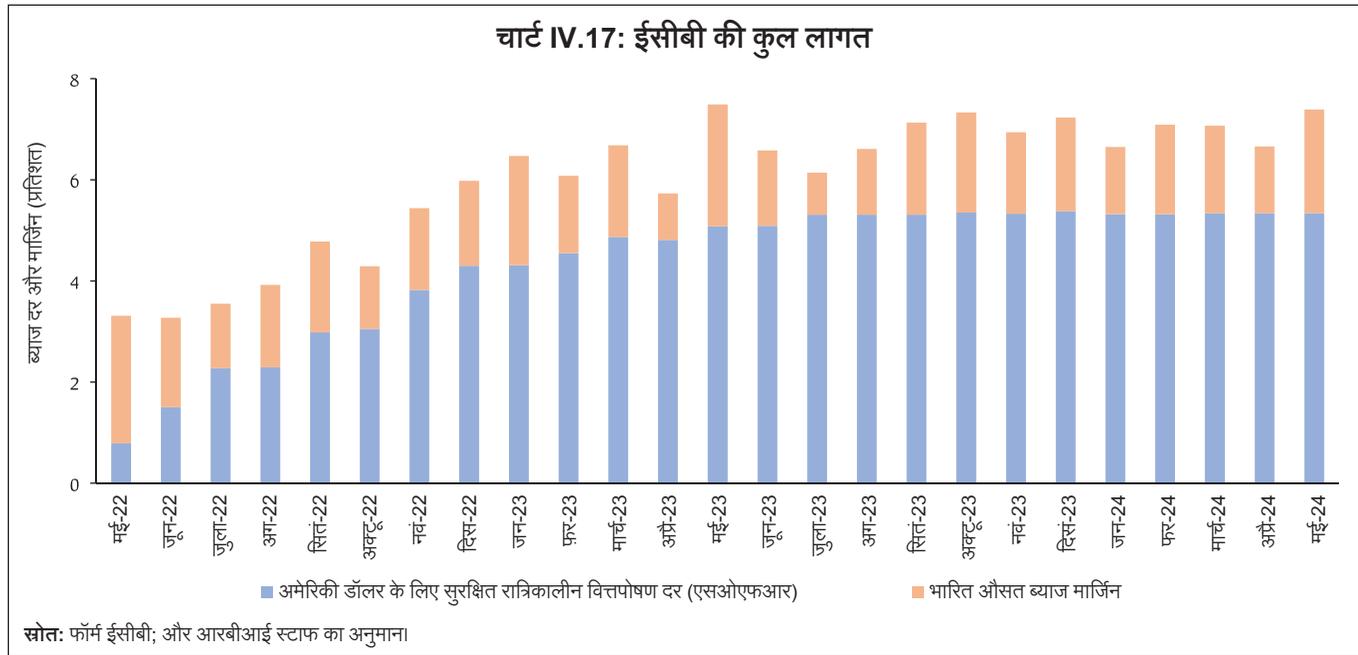


2023-24 की चौथी तिमाही में दर्ज की गई बढ़ोतरी को जारी रखते हुए, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) का सकल संवितरण 2024-25 की पहली तिमाही के पहले दो महीनों के दौरान नए पंजीकरण और संवितरण में क्रमिक मॉडरेशन के बावजूद 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अप्रैल-मई 2023 में 5.5 बिलियन



³⁵ <https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-06-27/what-india-s-inclusion-in-jpmorgan-bond-index-means-for-its-economy-markets?sref=QF6yuiF0>

³⁶ जनवरी 2025 से शुरू होने वाले 10 प्रतिशत के शुरुआती भार के साथ ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट (ईएम) स्थानीय मुद्रा सरकारी सूचकांक में भारतीय पूरी तरह से सुलभ रूट (एफएआर) बांड शामिल किए जाएंगे। यह भी घोषणा की गई है कि भारत को यूएस रिटायरमेंट फंड के नये फेडरल रिटायरमेंट थ्रिफ्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड (एफआरटीआईबी) इंडेक्स में शामिल किया जाना है।

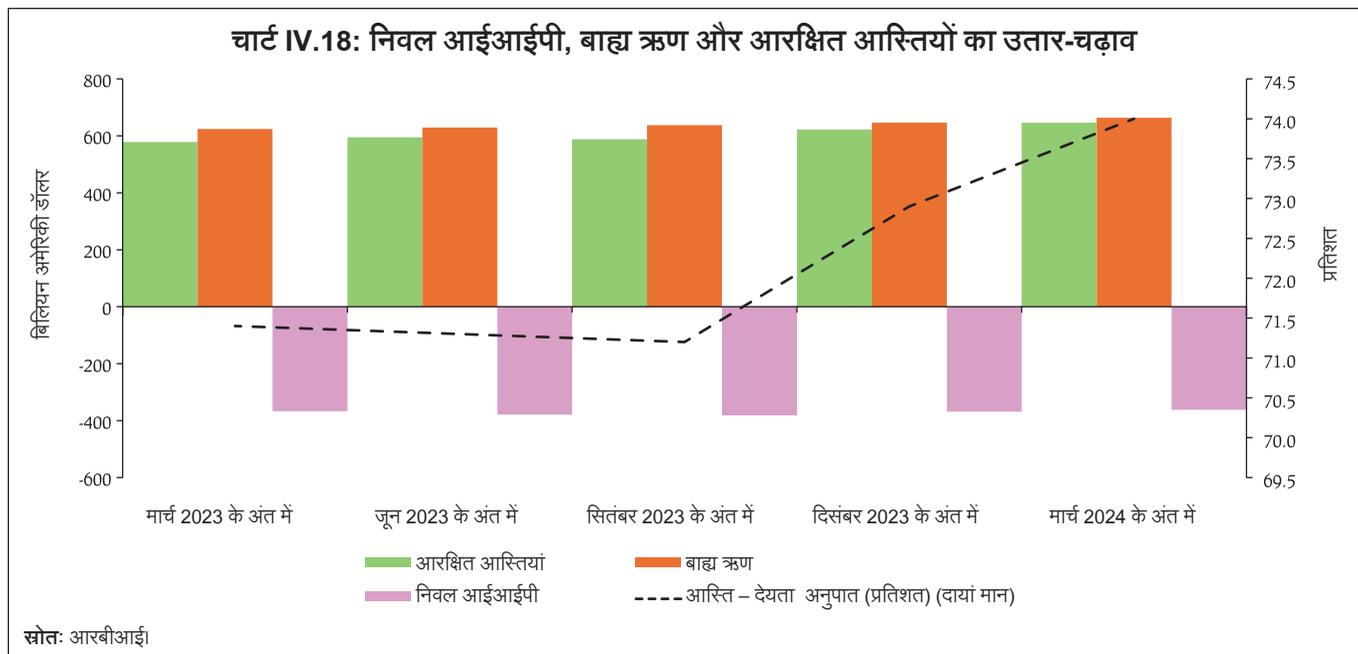


अमेरिकी डॉलर) के उच्च स्तर पर रहा। अंतर्वाह बहिर्प्रवाह से अधिक होने के कारण, निवल प्रवाह सकारात्मक बना हुआ है (चार्ट IV.15)।

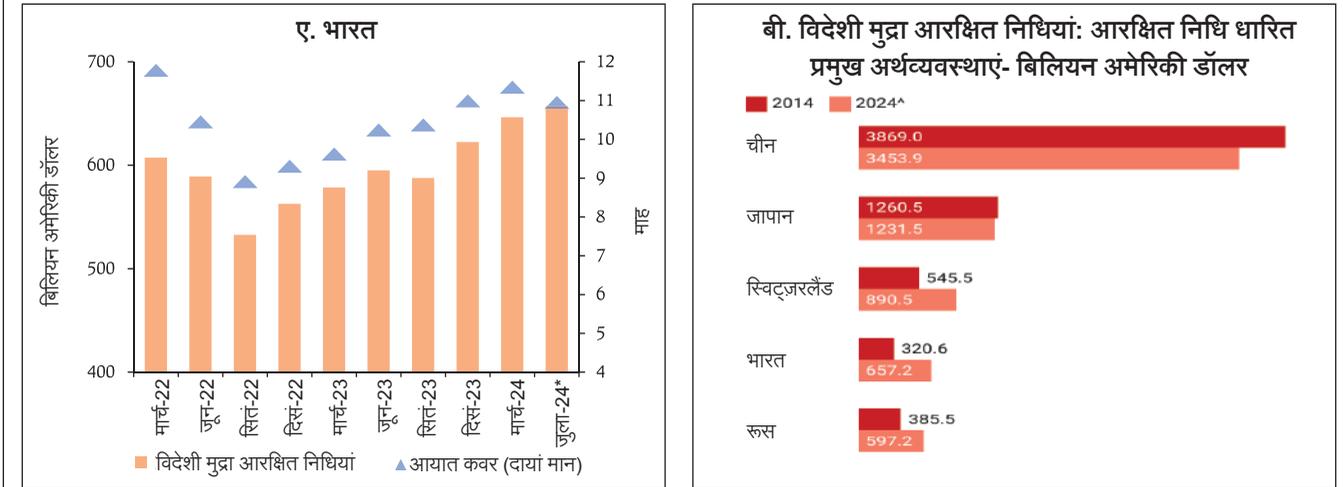
अप्रैल-मई 2024 के दौरान जुटाए गए इसीबी का एक बड़ा हिस्सा नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए था (चार्ट IV.16)।

स्थिर बेंचमार्क दर पर भारत औसत मार्जिन 73 बीपीएस बढ़ गया, जिससे मई 2024 में इसीबी ऋण की कुल लागत बढ़ गई (चार्ट IV.17)।

आरक्षित निधि, मुद्रा और जमा और बाह्य एफडीआई में विस्तार के कारण, 2023-24 की चौथी तिमाही के दौरान भारत की निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) बढ़कर



चार्ट IV.19: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

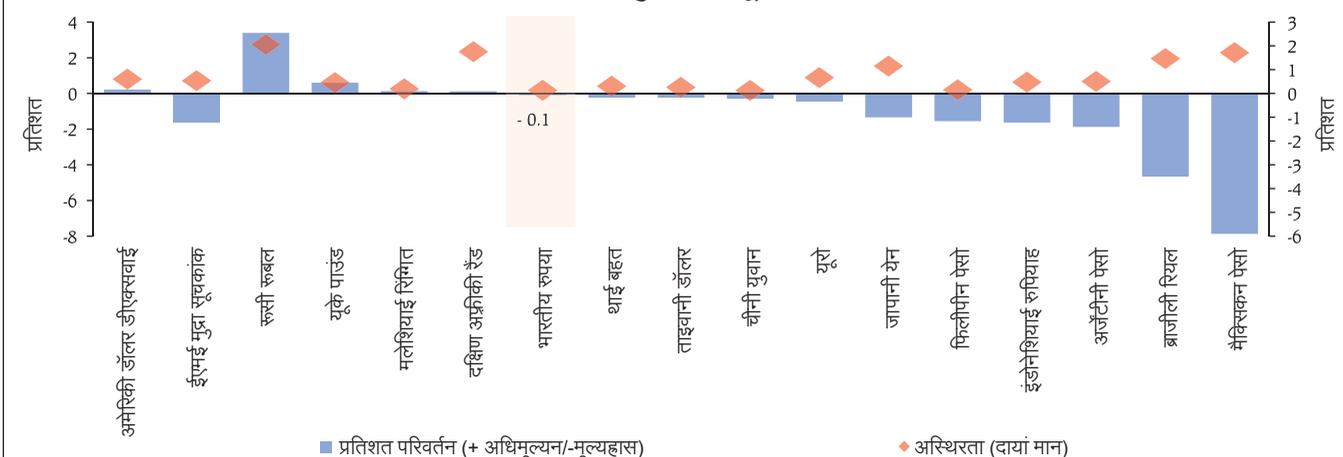


नोट: 1. *: 5 जुलाई का डेटा
 2. *: भारत और रूस के लिए आंकड़े 5 जुलाई, चीन और जापान के लिए जून के अंत और स्विट्जरलैंड के लिए मई के अंत के हैं।
 3. भारत के लिए आयात कवर जुलाई 2024 को छोड़कर, वास्तविक आयात पर आधारित है जो 2024-25 के लिए अनुमानित आयात पर आधारित है।
स्रोत: आरबीआई; आईएमएफ; और संबंधित केंद्रीय बैंक वेबसाइटें।

(-) 361.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जो कि आवक एफडीआई में वृद्धि और बाह्य ऋण देयताओं से मामूली रूप से संतुलित थी (IV.18)। परिणामस्वरूप, मार्च 2024 में भारत की अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों और अंतर्राष्ट्रीय देयताओं का अनुपात सुधरकर 74.0 प्रतिशत हो गया। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का निवल आईआईपी (मौजूदा बाजार मूल्यों पर) अनुपात भी एक साल पहले के (-) 11.3 फीसदी के मुकाबले सुधरकर मार्च 2024 में (-) 10.3 प्रतिशत हो गया।

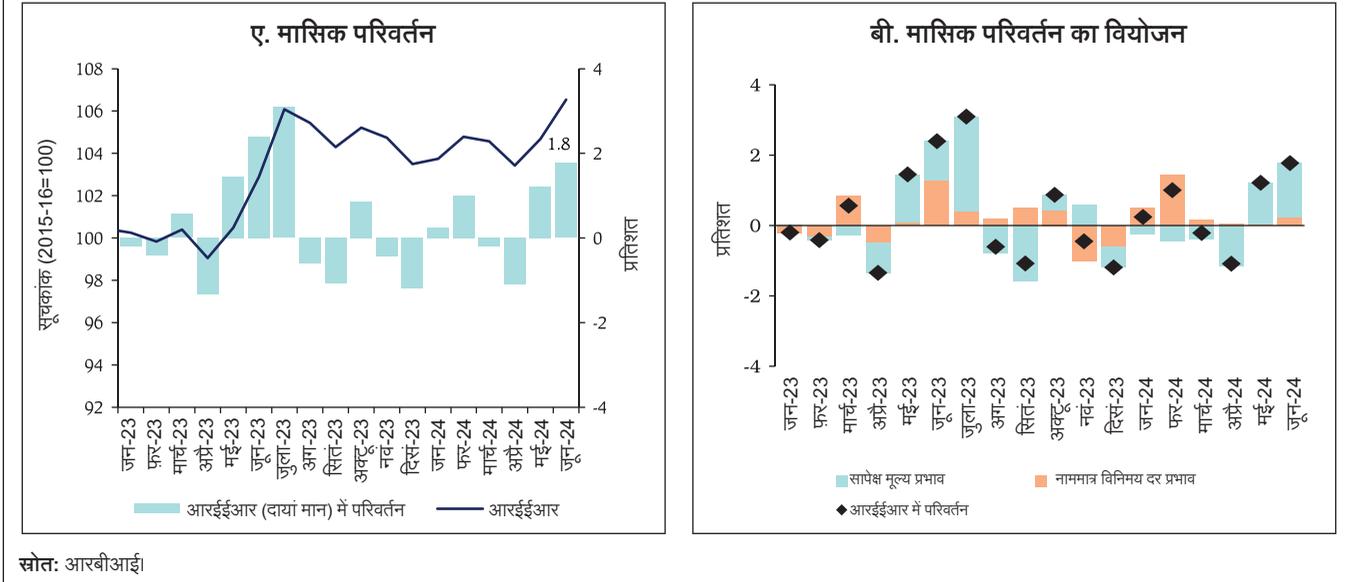
2024 में भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 34.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 5 जुलाई, 2024 को 657.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो 2024-25 के लिए अनुमानित लगभग 11 महीनों के आयात के बराबर है और मार्च 2024 के अंत में कुल बाह्य ऋण बकाया का लगभग 99 प्रतिशत है। (चार्ट IV.19ए)। वर्तमान में, भारत दुनिया में चौथा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि धारक बना हुआ है (चार्ट IV.19बी)।

चार्ट IV.20: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये और प्रमुख मुद्राओं का उतार-चढ़ाव (मई 2024 की तुलना में जून 2024 को)



नोट: अमेरिकी डॉलर (डीएसवीआई) प्रमुख मुद्राओं (यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, कनाडाई डॉलर, स्वीडिश क्रोना, स्विस् फ्रैंक) के एक समूह के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के उतार-चढ़ाव को मापता है।
स्रोत: एफबीआईएल; थॉमसन रॉयटर्स; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट IV.21: 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव

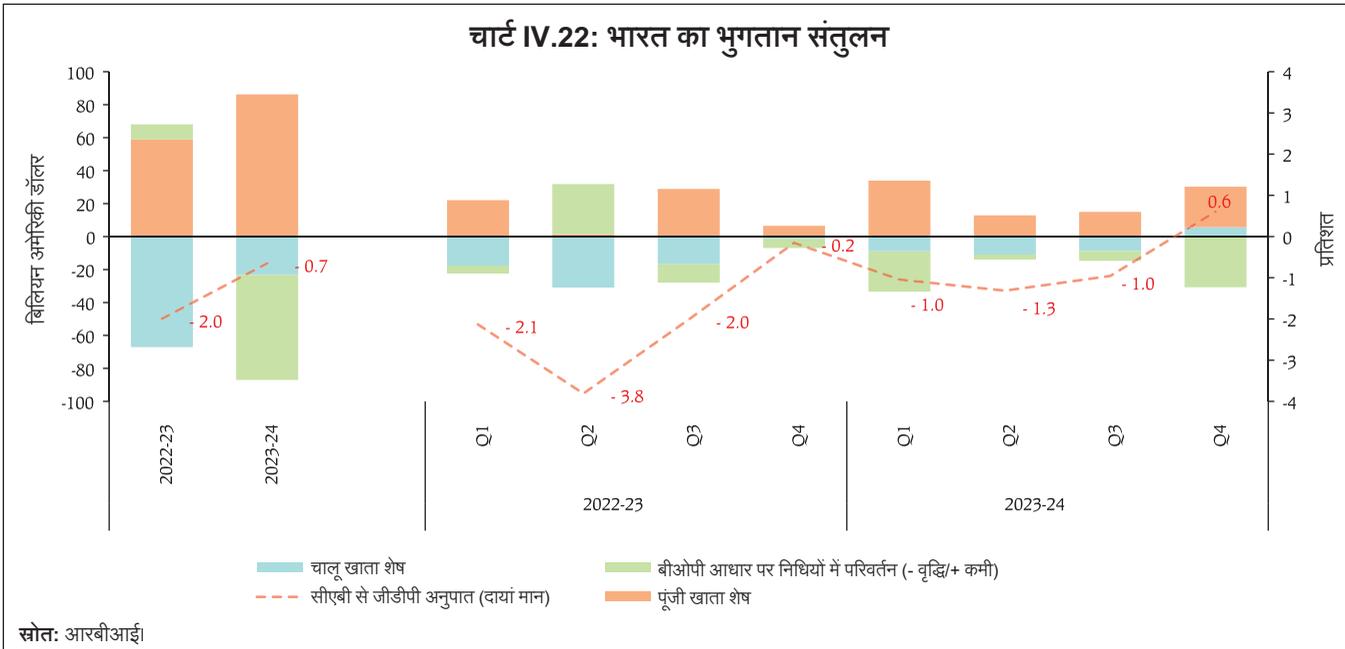


जून 2024 में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये (आईएनआर) में 0.1 प्रतिशत (माह-दर-माह) की गिरावट आई, क्योंकि उभरते बाजार की मुद्राओं को मजबूत अमेरिकी डॉलर और वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण मूल्यहास दबाव का सामना करना पड़ा। हालाँकि, भारतीय रुपया, इस महीने के दौरान सबसे कम अस्थिर प्रमुख मुद्राओं में से एक रहा (चार्ट IV.20)।

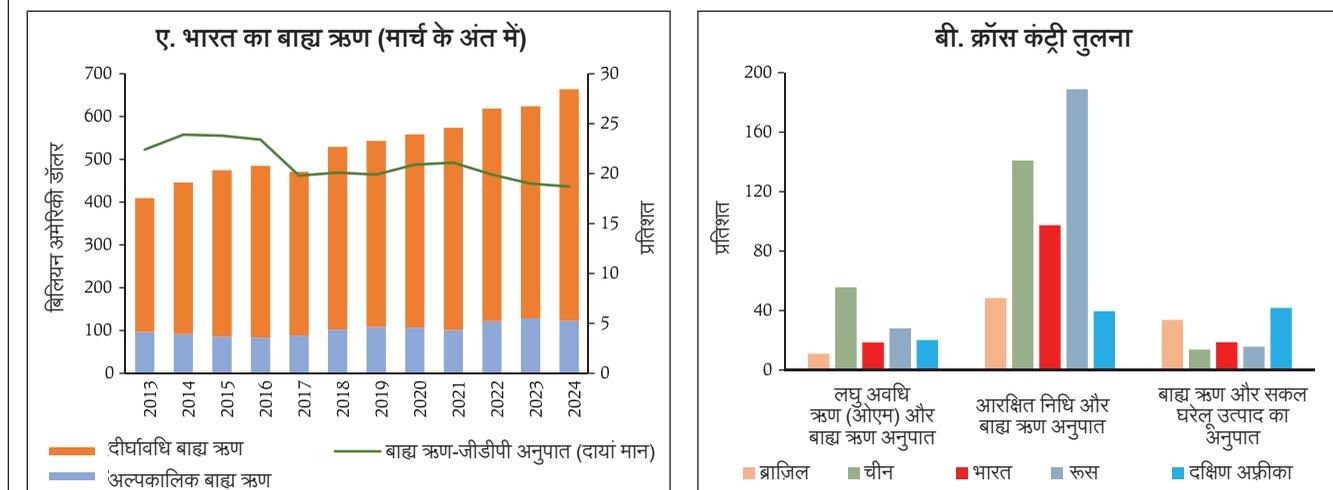
40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संदर्भ में, जून 2024 में भारतीय रुपये में 1.8 प्रतिशत (माह-दर-माह) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण सकारात्मक सापेक्ष मूल्य अंतर (चार्ट IV.21) था।

भारत के चालू खाता शेष (सीएबी) में 2023-24 की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 0.6 प्रतिशत अधिशेष दर्ज

चार्ट IV.22: भारत का भुगतान संतुलन



चार्ट IV.23: बाहरी भेद्यता संकेतक



नोट: 1. ओएम: मूल परिपक्वता।
 2. भारत के लिए बाह्य भेद्यता अनुपात पर डेटा मार्च 2024 के अंत के लिए है, जबकि अन्य देशों के लिए दिसंबर 2023 के अंत के लिए है।
स्रोत: आरबीआई; भारत सरकार: आईएमएफ; विश्व बैंक; और सीईआईसी।

किया गया, जबकि 2023-24 की तीसरी तिमाही में 1.0 प्रतिशत और 2022-23 की चौथी तिमाही में 0.2 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। मजबूत सेवा निर्यात और प्रेषण प्राप्तियों के साथ-साथ माल व्यापार घाटा कम होने से चालू खाते में अधिशेष दर्ज हुआ (चार्ट IV.22)।

समग्र रूप से 2023-24 के दौरान, माल व्यापार घाटे में गिरावट के कारण चालू खाता घाटा (सीएडी) एक साल पहले के 2.0 प्रतिशत से घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत हो गया। 2023-24 के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों (मूल्यांकन प्रभाव को छोड़कर) में 63.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर

की वृद्धि हुई, क्योंकि निवल पूंजी अंतर्वाह - मजबूत एफपीआई प्रवाह और बैंकिंग पूंजी पर हावी अर्थात् सीएडी से अधिक था।

मार्च 2023 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण 39.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 663.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में विदेशी ऋण एक साल पहले के 19.0 प्रतिशत से कम होकर 18.7 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.23ए)। भारत के प्रमुख बाह्य भेद्यता संकेतक टिकाऊ स्तर पर बने रहे और अपने समकक्षों की तुलना में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया (चार्ट IV.23बी)।

सारणी IV.2: चुनिंदा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि

(वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत में)

भुगतान प्रणाली संकेतक	लेन-देन की मात्रा				लेन-देन मूल्य			
	मई-23	मई-24	जून-23	जून-24	मई-23	मई-24	जून-23	जून-24
आरटीजीएस	12.6	13.3	9.2	9.2	15.2	17.9	16.0	11.9
एनईएफटी	28.4	52.5	26.7	43.4	18.8	14.3	11.9	9.6
यूपीआई	58.3	49.1	59.2	48.7	43.2	37.3	45.5	36.0
आईएमपीएस	3.5	11.2	2.7	10.4	16.6	14.9	12.8	15.4
एनएसीएच	-14.3	12.7	18.8	29.5	19.5	20.7	18.7	24.1
एनईटीसी	17.4	3.7	13.7	5.8	24.3	8.7	20.8	11.2
बीबीपीएस	28.4	47.8	24.8	53.6	44.8	114.8	41.6	108.9

नोट: आरटीजीएस: रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी: नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यूपीआई: यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस, आईएमपीएस: तत्काल भुगतान सेवा, एनएसीएच: नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, एनईटीसी: नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, बीबीपीएस: भारत बिल भुगतान प्रणाली।

स्रोत: आरबीआई।

भुगतान प्रणाली

सभी प्रमुख श्रेणियों में डिजिटल भुगतान प्रणाली संकेतकों ने जून 2024 में निरंतर वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) प्रदर्शित की जिसमें मुख्य रूप से भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) और एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) [सारणी IV.2] अग्रणी है। बीबीपीएस ने जून 2024 के दौरान स्थिर वृद्धि बनाए रखी, जो ग्राहकों और बिलर्स दोनों की जरूरतों को पूरा करने वाले एक सहज, सुरक्षित और कुशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरलीकृत बिल भुगतान के कारण बढ़ी हुई पैठ को दर्शाता है।³⁷ जून 2024 में, यूपीआई ने यद्यपि क्रमिक रूप से मामूली गिरावट के साथ मजबूत वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) दर्ज की। अन्य भुगतान प्रणाली संकेतकों के संबंध में, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) की वृद्धि दर मई के सापेक्ष जून 2024 में धीमी हो गई। भुगतान प्रणाली के बुनियादी ढांचे - क्रेडिट कार्ड की संख्या में वृद्धि (17.7 प्रतिशत), पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) टर्मिनलों की तैनाती (10.6 प्रतिशत), भारत त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड (10.4 प्रतिशत) और यूपीआई क्यूआर कोड (23.7 प्रतिशत) में मजबूत वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) के कारण मई 2024 में डिजिटलीकरण लगातार मजबूत हुआ है।

भारतीय भुगतान प्रणालियों की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के विस्तार को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, रिजर्व बैंक प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया, जो एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है, जो चार दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र (एएसईएन) देशों (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड); और भारत के संगठन की घरेलू तेज भुगतान प्रणालियों (एफपीएस) को आपस में जोड़कर त्वरित सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाती है।³⁸ उम्मीद है कि यह प्लेटफॉर्म खुदरा सीमा-पार भुगतान को कुशल, तेज और अधिक लागत प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 3 जुलाई, 2024 को पीएसबी और पीवीबी के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ आरबीआई गवर्नर की एक बैठक हुई, जिसमें मजबूत साइबर सुरक्षा नियंत्रण, तीसरे पक्ष के जोखिमों के प्रबंधन, ग्राहक जागरूकता और शिक्षा से संबंधित मुद्दे शामिल थे। डिजिटल धोखाधड़ी पर

अंकुश लगाने की पहल, उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।³⁹ नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ने नेटवर्क इंटरनेशनल (नेटवर्क) के साथ साझेदारी में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में नेटवर्क के पीओएस टर्मिनलों के माध्यम से क्यूआर-कोड आधारित यूपीआई भुगतान की स्वीकृति को सक्षम⁴⁰ किया। इससे संयुक्त अरब अमीरात में नेटवर्क के विशाल व्यापारी नेटवर्क में भारतीय पर्यटकों और अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए निर्बाध और सुरक्षित सीमा पार लेनदेन की सुविधा मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर यूपीआई की पहुंच को एनआईपीएल की लायरा के साथ साझेदारी⁴¹ के साथ आगे बढ़ाया गया, जिसने पेरिस में गैलरीज लाफायेट के प्रमुख स्टोर पर सुरक्षित और सुविधाजनक यूपीआई लेनदेन को सक्षम किया।

निष्कर्ष

इस पृष्ठभूमि में, अपने लक्ष्यों के संदर्भ में, मौद्रिक नीति के संचालन का जायजा लेना उपयोगी है। नीति दर में संचयी वृद्धि ने फरवरी 2023 तक नीति दर के स्तर को 6.5 प्रतिशत तक पहुंचा दिया, जिसके बाद लंबे समय तक विराम लगा रहा। इस नीतिगत दृष्टिकोण से सितंबर 2023 के बाद से सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति के सहिष्णुता बैंड में गिरावट के रूप में कुछ लाभ प्राप्त हुए हैं। फिर भी, अवस्फीति निराशाजनक और असमान रही है और मुख्य मुद्रास्फीति पर ऐतिहासिक रूप से कम रीडिंग और ईंधन की कीमतों में निरंतर अपस्फीति के बावजूद हेडलाइन मुद्रास्फीति अपनी नवीनतम रीडिंग में 4 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 5 प्रतिशत के करीब बनी हुई है।

यह खाद्य मुद्रास्फीति, इसकी प्रकृति और गतिशीलता पर सार्वजनिक चर्चा का ध्यान केंद्रित करता है। यह तर्क कि खाद्य कीमतों के झटके क्षणिक होते हैं, पिछले एक साल के वास्तविक अनुभव से प्रमाणित नहीं होता है - किसी झटके को क्षणभंगुर कहने के लिए यह बहुत लंबी अवधि है! इस 'निरंतर' घटक पर सब्जियों की एक श्रृंखला की कीमतों में छिटपुट बढ़ोतरी होती

³⁷ 9 जुलाई 2024, एनपीसीआई प्रेस विज्ञप्ति

³⁸ 1 जुलाई 2024, आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति

³⁹ 3 जुलाई 2024, आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति

⁴⁰ 3 जुलाई 2024, एनपीसीआई प्रेस विज्ञप्ति

⁴¹ 5 जुलाई 2024, एनपीसीआई प्रेस विज्ञप्ति

हैं जो सब्जियों की व्यापक श्रेणी की मुद्रास्फीति को एक स्थायी चरित्र देने के लिए घटकों में ओवरलैप होती है। खाद्य कीमतें स्पष्ट रूप से हेडलाइन मुद्रास्फीति और परिवारों की मुद्रास्फीति अपेक्षाओं पर हावी हो रही हैं, जो मौद्रिक नीति और आपूर्ति प्रबंधन के संयोजन के माध्यम से मुख्य और ईंधन मुद्रास्फीति को कम करने के लाभ को कम कर रही हैं। हालाँकि मुद्रास्फीति के बारे में परिवारों की मौजूदा धारणा कम हो रही है, लेकिन यह उनकी तीन महीने आगे और एक साल आगे की प्रत्याशाओं पर प्रतिबिंबित नहीं हो रही है जो ऊंची बनी हुई हैं। खाद्य कीमतों का दबाव बढ़ने से मजदूरी, किराए और प्रत्याशाओं पर असर के रूप में मुद्रास्फीति की संभावना को खतरा है।

इस पृष्ठभूमि में, आरबीआई की एमपीसी ने मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप टिकाऊ रूप से संरेखित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। जब तक यह हासिल नहीं हो जाता, मुद्रास्फीति रीडिंग में हाल ही में रुकी गिरावट को अभी भी प्रगति पर माना जाना चाहिए।

लगभग आधी सदी पहले, मौलिक कार्य ने समय की असंगति की घटना की ओर इशारा किया था⁴² जब मूल्य स्थिरता के लिए

प्रतिबद्ध मौद्रिक नीति अधिकारी बढ़ती वृद्धि के अल्पकालिक लाभ की खोज में उस प्रतिबद्धता से मुकर जाते हैं, तो वे अंततः विश्वसनीयता खो सकते हैं, मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को कमजोर कर सकते हैं और मुद्रास्फीति में वृद्धि को उत्प्रेरित सकते हैं। यह विकास की स्थिरता को भी कमजोर कर सकता है। मुद्रास्फीति के परिदृश्य में छाई उच्च अनिश्चितता को देखते हुए, समय की असंगतता के प्रलोभन से बचना और मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत के लक्ष्य के साथ संरेखित करने के सीधे और संकीर्ण रास्ते पर बने रहना समझदारी है। इसका मतलब यह नहीं है कि मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत तक पहुंच जानी चाहिए और मौद्रिक नीति रुख में बदलाव पर विचार करने से पहले वहां बनी रहनी चाहिए; इसके बजाय, जोखिमों के संतुलन के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के आधार पर, लक्ष्य की ओर एक स्थायी गति के साथ दूरदेशी मौद्रिक नीति को प्रतिक्रिया देने के लिए संकेत प्रदान करना चाहिए। गवर्नर श्री शक्तिकांत दास के शब्दों में, “मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और समयावधि में निरंतर विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करने के लिए मूल्य स्थिरता पर केंद्रित रहती है”।

⁴² किडलैंड, फिन ई., और एडवर्ड सी प्रेस्कॉट, “विवेक के बजाय नियम: इष्टतम योजनाओं की असंगति”, जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 85(3):473-492, 1977, जून।